



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और पर्यटन : परिदृश्य और बहस

एशियाई अनुभवों पर आधारित पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय
संस्थाओं के हस्तक्षेपों पर एक संकलन

इक्वेशंस
जून 2009

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और पर्यटन : परिदृश्य और बहस

एशियाई अनुभवों पर आधारित पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय
संस्थाओं के हस्तक्षेपों पर एक संकलन

इक्वेशंस, जून 2009

इक्वेशंस

इक्वेशंस — न्यायोचित पर्यटन विकल्प (इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस)

न. 415, 2 सी क्रॉस, 4था मेन, ओएमबीआर लेआउट, बनासवाड़ी

बंगलोर — 560043

फोन : +91 80 25457607 / 25457659

फैक्स : +91 80 25457665

ईमेल : info@equitabletourism.org

वेबसाइट : www.equitabletourism.org

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और पर्यटन : परिदृश्य और बहस, जून 2009

इसे तैयार करने में इक्वेशंस शलमाली गुट्टल, सौपर्ण लाहिरी एवं अनीता प्लीमैरम के योगदान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। इसके अलावा मूल अंग्रेजी प्रकाशन "IFIs and Tourism: Perspectives and Debates" का हिन्दी अनुवाद करने के लिए बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी एवं विमल भाई का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करती है।

इस दस्तावेज में उपलब्ध सूचनाओं का उचित संदर्भ देते हुए उपयोग करने के लिए आपका स्वागत है। पर्यटन के असर पर इस प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशनों के लिए कृपया हमें info@equitabletourism.org पर लिखें।

1. मौज मस्ती में निवेश	6
एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के चार दशक के क्रियाकलाप की राजनीति व असर शलमाली गुट्टल, फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ, मार्च 2008	
2. स्वयं को दोहराता इतिहास?	17
पर्यटन विकास में विश्व बैंक की विवादास्पद भूमिका का एक लेखा-जोखा विद्या रंगन, इक्वेशंस, सितम्बर 2007	
3. मीकांग पर्यटन – मॉडल या उपहास	31
‘टिकाऊ पर्यटन’ संबंधी एक केस स्टडी अनीता प्लीमैरम, पर्यटन जांच एवं निगरानी दल, 2001	
4. अनछुआ स्वर्ग – किस कीमत पर?	49
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आशय पर केन्द्रित व एसएसएसईसी क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक की पर्यटन विकास योजना से उठने वाले मुद्दों एवं आशंकाओं का विश्लेषण विद्या रंगन, इक्वेशंस, मार्च 2006	
5. एडीबी का नवीनतम पर्यटन अवतार : सभी लोगों व निवेशकों के लिए खुला मौका	66
व्यापक पर्यटन संरचना विकास परियोजना के माध्यम से भारत को दिए जाने वाले एडीबी के नवीनतम पर्यटन विशेष कर्ज पर विचार सौपर्ण लाहिरी, मार्च 2008	
6. कथन	70
नयी दिल्ली, भारत में 21-24 सितंबर 2007 को इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल की ज्यूरी के समक्ष विश्व बैंक समूह के बारे में कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और आंदोलनकारियों की पर्यटन क्षेत्र के संबंध में बयान/टिप्पणी नयी दिल्ली, भारत	

इक्वेशंस के काम ने व्यापार एवं पर्यटन के बहस के महत्वपूर्ण मुद्दों की कड़ी को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा है। हमारे काम का केन्द्र बिंदु अनियंत्रित एवं पूर्ण उदारीकृत पर्यटन की अर्थव्यवस्था की क्षमता पर सवाल उठाने से लेकर स्थानीय समुदायों के लिए व्यापक एवं टिकाऊ लाभ दिलाने पर रहा है। इसमें भारत में राष्ट्रीय व राज्य सरकारों के उदारीकरण एवं अनियंत्रण के प्रयासों का विश्लेषण एवं डब्ल्यूटीओ, यूएनडब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक और एडीबी जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की छान-बीन शामिल है। हमारे काम को दक्षिणी दुनिया (ग्लोबल साऊथ) में संघर्षों, अनुभवों एवं अभियानों से महत्व मिला है, जो कि समुदायों के अधिकार एवं पर्यटन पर उनके मालिकाना का दावा करता है।

इस बहस के अलावा, यह संकलन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्यटन क्षेत्र की गतिविधियों व हस्तक्षेपों के महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर ध्यान देता है। विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के हस्तक्षेपों के प्रति बढ़ती वैश्विक असंतुष्टि और समुदायिक विरोध के संदर्भ में देखने और व्याख्या करने वाला यह संकलन खासतौर पर पर्यटन के क्रियाकलापों पर उठने वाले सवालों व समीक्षाओं को प्रस्तुत करता है। पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय स्वभाव व असरों और इसके पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने वाले स्वरूप के कारण हम एशियाई क्षेत्र के अनुभवों पर आधारित मुद्दों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और खासकर उन इलाकों का जो कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों के केन्द्र रहे हैं।

पर्यटन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों पर इक्वेशंस द्वारा निगरानी व शोध कार्य के अलावा इन मुद्दों पर लिखते रहने और अभियान में लगे कार्यकर्ताओं का इस संकलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम वास्तव में शलमाली गुट्टल, अनीता प्लिमरम एवं सौपर्ण लाहिरी द्वारा अपने विचारों, शोध और विश्लेषणों को इस संकलन में शामिल करने के योगदान के लिए आभारी हैं। खासतौर पर, हमने पर्यटन क्षेत्र के लिए तैयार किए गए उन कथनों को भी शामिल किया है, जो कि नयी दिल्ली में 21 से 24 सितंबर 2007 को विश्व बैंक समूह पर इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल के समक्ष प्रस्तुति के लिए दुनिया भर के कार्यकर्ताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों एवं अभियानकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए थे। इसके अलावा इसके व्यापक प्रसार के लिए संकलन को अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी एवं विमल भाई का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

इस संकलन को क्षेत्र में, पर्यटन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बढ़ती गतिविधियों के मुद्दों को उजागर करने के लिए आंदोलनों, जमीनी स्तर के समूहों, नागरिक समाज संगठनों, शोधार्थियों एवं नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का उद्देश्य है। हालांकि इन लेखों का उद्देश्य पर्यटन के असरों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के क्रियाकलापों एवं दोनों के बीच संबंधों के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है; लेकिन ये, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादा शोध, अभियान एवं एडवोकेसी के लिए जोरदार आह्वान करते हैं।

इक्वेशंस

जून 2009

मौज मस्ती में निवेश

एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के चार दशक के
क्रियाकलाप की राजनीति व असर

शलमाली गुट्टल, *फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ*, 25 मार्च 2008

पिछले चार दशकों से ज्यादा से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इन नीतियों को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक देशों ने अपनाया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कि सरकारों, निजी कंपनियों और निगमों को आधारभूत परियोजनाओं, निवेश, व्यापार सुविधा, नए कारोबारों की स्थापना, आदि के लिए वित्तपोषण और संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान निजी कंपनियां हैं (उदाहरण के लिए सिटीकॉर्प, मॉर्गन स्टैनले और मेरिल लिंच), लेकिन विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी भी इन विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समूह के हिस्से हैं जिन्हें बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये शब्द कभी-कभी लेन-देन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (एमएफआई)¹ शब्द का प्रयोग करेंगे।

जीवन से व्यापक

एक मायने में देखा जाय तो बहुपक्षीय विकास बैंक 'विशिष्ट राष्ट्रीय सार्वजनिक संस्थान' हैं। जो बात इन संस्थानों को निजी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से अलग करती है वह यह कि ये सरकारों द्वारा विकासशील देशों को मदद करने और विकास वित्त को उत्प्रेरित करने के लिए और व्यापक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जाती हैं। इन सबके अलावा ये दावा करते हैं कि गरीबी व भूख कम करने, आर्थिक विकास के माध्यम से धन और समृद्धि बढ़ाने, और विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व भर में लाखों पेशेवर कर्मचारियों द्वारा चलाए और प्रबंधित किए जाने के बावजूद, संस्थाएं सदस्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। वे पूंजी सदस्यताओं, ब्याज अदायगी और अन्य योगदान के माध्यम से अपने कई क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। और चूंकि ये सरकारों द्वारा स्थापित और समर्थित होते हैं, इसलिए विश्व बैंक, एडीबी को ट्रिपल-ए² का दर्जा प्राप्त है और ये अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में विशाल धनराशि जुटाने में सफल रहे हैं।

विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी के सदस्यों में विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। हालांकि वे अंतर सरकारी सदस्य संगठन हैं लेकिन वे एक देश एक मत के सिद्धांत पर संचालित नहीं होते हैं। इन संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया कंपनी जगत के ही अनुसार शेयरधारक शक्ति पर आधारित है। जो सरकारें एमएफआई में शामिल होती हैं वे संस्था में एक निश्चित राशि का निवेश करती हैं। जिन देशों ने अधिक पूंजी निवेश किया है उनके पास ज्यादा वोट और शक्तियां होती हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ में, अमेरिका सबसे शक्तिशाली शेयरधारक है। एडीबी में, अमेरिका और जापान के वोटों की संख्या बराबर है। यद्यपि एमएफआई वित्तपोषण और तकनीकी और सलाहकार सेवाएं विकासशील देशों में परियोजनाओं की ओर निर्देशित होती हैं लेकिन विकसित देश के सदस्य समग्र नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थाओं की विचारधाराओं को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं।

एमएफआई दुनिया में विकास वित्त के सबसे बड़े स्रोत हैं खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों को किसी भी एक वर्ष में 30–40 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच कर्ज और अनुदान देते हैं।³ वे विकासशील देशों को सामाजिक, आर्थिक बुनियादी ढांचे और संस्थागत विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज, अनुदान, तकनीकी सहायता (टीए) और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं। एमएफआई विकासशील देशों में क्रियाशील निजी उद्यमों को वित्तीय व राजनैतिक जोखिमों के लिए वित्तपोषण, सलाह, समर्थन, सेवा और गारंटी भी प्रदान करते हैं। अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण देश के विकास में एमएफआई की भागीदारी वित्तपोषण से आगे भी होती है वे

¹ आईएमएफ विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की तरह एक विकास बैंक नहीं है; हालांकि यह एक विकासवात्मक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था और विश्व बैंक जैसी ही सिद्धांतों पर चलता है, जैसा कि इसे लेख में आगे वर्णन किया गा है; बैंक में तकनीकी रूप से क्या शामिल होता है, इस बहस में पड़ने से बचने के लिए हम इसे लेख में एमएफआई कहकर संबोधित करेंगे।

² ट्रिपल ए सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग है जो कि एक वित्तीय संस्थान के पास अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में हो सकती है; यह आमतौर पर वित्तीय तंत्र और संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ होता है जिन्हें सरकारी क्रेडिट का पूरा भरोसा और समर्थन हासिल रहता है; एक ट्रिपल-ए क्रेडिट रेटिंग भरोसा दिलाते हैं कि एक संस्थान अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार पर समस्याओं के बिना वित्त पूंजी जुटाने में सक्षम है; ट्रिपल-ए क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं द्वारा समर्थित परियोजना आसानी से निजी निवेशकों को आकर्षित करती है।

³ सटीक आंकड़ों की गणना कठिन हो सकती है क्योंकि प्रत्येक एमएफआई संस्थान और विभाग ऋण, अनुदान, टीए समर्थन और जोखिम गारंटी आदि का अलग-अलग हिसाब-किताब रखते हैं। अपनी वेबसाइट पर विश्व बैंक का दावा है कि आईबीआरडी/आईडीए के माध्यम से हाल की उधारी कुल 25 अरब अमेरिकी डॉलर से कम रही है; लेकिन अनुदानों या आईएफसी द्वारा निजी कंपनियों या एमआईजीए गारंटी के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं; इसी तरह, अपनी वेबसाइट पर एडीबी का दावा है कि उसने सन 2006 में 6.82 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज और और 241.6 अमेरिकी डॉलर टीए के लिए दिया है; लेकिन अनुदान और गारंटी के लिए आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।

सचमुच अपनी ग्राहक सरकारों पर राष्ट्रीय संरचनाओं, संस्थाओं, कानूनों, नियमनों और नीतियों को निजी क्षेत्रों के अनुकूल बनाने के लिए ओवरहाल करने व पुनः आकार देने के लिए दबाव बनाने में सक्षम होते हैं।

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में जो शक्तिशाली स्थिति कायम की हुई है उसका विकासशील देशों के नागरिक समूहों, जन आन्दोलनों, स्वैच्छिक संगठनों, यूनियनों, कामगारों व किसानों के समूहों, महिलाओं व आदिवासी लोगों के संगठनों एवं यहां तक कि अकादमिकों व नीति निर्माताओं द्वारा द्वारा उग्र विरोध किया जाता है। विकास के प्रति एमएफआई की सोच नवउदारवादी विचारधारा पर बनी हुई है और और इस विश्वास पर गहरे तौर पर टिकी हुई है कि विकास का सबसे अच्छा रास्ता है तीव्र आर्थिक विकास, एवं संसाधनों एवं अवसरों के सबसे कुशल मापक है स्वतंत्र और खुला बाजार तथा वस्तुओं और सेवाओं के सौंपने का सर्वोत्तम माध्यम हैं निजी क्षेत्र। सरकार को चाहिए कि आर्थिक गतिविधि के हरेक क्षेत्र में “मालिक-उत्पादक-वितरक” के बजाय “सहयोगकर्ता-नियंत्रक” की भूमिका निभाए एवं “निजी क्षेत्र के भागीदारों के लिए माहौल” तैयार करे। टीए एवं सलाहकारी सेवाओं के लिए वित्तपोषण करने वाले सभी एमएफआई इस नीतिगत शर्त मानते हैं कि उधारी या अनुदान की मांग एवं टीए प्राप्त करने वाली सरकारें विकास की बाजार आधारित अवधारणा को अपनाती हैं।

वाह्य जवाबदेही और जिम्मेदारी के मुद्दे भी समस्याग्रस्त हैं। वास्तव में एमएफआई इन कानूनों से ऊपर हैं। उनके संस्थापक चार्टरों के अनुच्छेद उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों से छूट दिलाते हैं, साथ ही उनके क्रियाकलापों व परियोजनाओं से वस्तुओं को होने वाले नुकसानों के लिए कानूनी जिम्मेदारी से मुक्ति दिलाते हैं। हर किसी द्वारा एमएफआई के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के बजाय नागरिकों के लिए ज्यादा आसान है कि वे अपने या विदेशी सरकारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। कुछ देशों में – उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश-विश्व बैंक ने यहां तक कि राष्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जिससे विश्व बैंक के कर्मचारियों पर अपराधिक आरोपों सहित किसी भी किस्म के कानूनी कार्यवाही से रक्षा हो सके। अपनी जवाबदेही की कमी के बारे में अपील करने के लिए विश्व बैंक एवं एडीबी ने परियोजना निगरानी प्रक्रिया, क्रियाकलाप मूल्यांकन विभाग एवं क्रियाकलाप के दिशानिर्देश व नीतियों की जटिल व्यवस्था बनाई है, उनमें से बहुत सारे में यह सुनिश्चित करने के लिए फेरबदल किए जाते रहे हैं कि अपनी ग्राहक सरकारों की नीतियों के जाल में फंसे बगैर संस्थाएं लाभदायी परियोजनाओं को वित्तपोषण कर सकें। उदाहरण के तौर पर, एडीबी अपनी सुरक्षा उपाय नीतियों में बदलाव कर रहा है और उनके जो मसौदे हैं उनमें पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को इतना कमजोर किया जा रहा है कि कई देशों के नागरिक समाज समूह एडीबी के साथ वार्ता से इनकार कर रहे हैं। विश्व बैंक एवं एडीबी के परियोजनाओं से आज तक नकारात्मक रूप से प्रभावित समुदायों को परियोजना आधारित विस्थापन व आजीविका छिन जाने के बदले समय से सही व उचित मुआवजा तक नहीं मिला तो क्षतिपूर्ति और न्याय के बारे में कहना बेकार है।

विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वयं को एलाइड नेशन कहे जाने वाले 44 देशों के प्रतिनिधियों की संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में जुलाई 1944 एक बैठक के दौरान हुई थी।⁴ बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध से नष्ट हुए यूरोप के पुनर्निर्माण एवं युद्ध पश्चात अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए नियमों, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में विचार किया जाय। विश्व बैंक का शुरुआती नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी), जो बाद में विश्व बैंक की विशिष्ट संस्थाओं में से एक हो गई। आईबीआरडी और आईएमएफ वास्तव में 1946 में संचालन में आए जब पर्याप्त संख्या में देशों ने ब्रेटन वुड्स समझौते पर सहमति जताई और उनकी स्थापना और कार्यप्रणाली की अनुमति दी। विश्व बैंक और आईएमएफ हमेशा एक साथ काम करते हैं, इनका पूरक संचालन ढांचा एवं संयुक्त संचालन मंडल है, जबकि कार्यक्रम की भूमिका अलग-अलग है। आईएमएफ अपने विकासशील देशों के सदस्यों के लिए व्यापक स्तर का वित्तीय एवं आर्थिक नीति का ढांचा तय करता है और जब विकासशील देशों को भुगतान संतुलन या उन्हें वित्तीय तरलता की समस्या आती है तो उन्हें कर्ज देता है। वह एक निगरानीकर्ता एवं जांचकर्ता की भूमिका भी निभाता है ताकि विकासशील देश वित्तीय व आर्थिक उदारीकरण एवं मुक्त व खुले बाजार के रास्ते पर चलते रहें। जबकि विश्व बैंक के क्रियाकलाप का दायरा काफी बड़ा है और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एवं वैश्विक विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों पर केन्द्रित करता है, जिसमें वित्तीय एवं आर्थिक प्रबंधन शामिल है, लेकिन सामाजिक, पर्यावरणीय एवं शासन क्षेत्र को भी कवर करता है।

⁴ एलाइड नेशन वे देश हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली एवं जापान का विरोध किया था (इन्हें एक्सिस पॉवर भी कहा जाता है)।

वर्तमान में, विश्व बैंक वास्तव में पांच वित्तीय संस्थाओं का समूह है : जिसमें आईबीआरडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोशिएशन (आईडीए), इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी), मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ़ इनवेस्टमेंट डिसप्यूट (आईसीएसआईडी) शामिल हैं। आईबीआरडी मध्य आय वाले विकासशील देशों को लगभग बाजार के ब्याज दर पर कर्ज देता है, जबकि आईडीए कम आय वाले देशों को बहुत ही कम ब्याज दर पर अनुदान एवं कर्ज देता है। आईएफसी विकासशील देशों को व्यवसाय निवेश के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और यह विश्व बैंक की सबसे तेजी से बढ़ने वाली संस्था है। वर्तमान में यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों को इक्विटी एवं कर्ज प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी बहुपक्षीय संस्था है। इसका दावा है कि वह विकासशील देशों में निजी कंपनियों को खुली, प्रतियोगी एवं सक्षम बाजार व प्रत्यक्ष मदद के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार प्रदान करने एवं गरीबी निवारण में मदद करता है। एमआईजीए निजी निवेशकों को मेजबान देश द्वारा संपत्तिहरण एवं समझौता तोड़ने एवं युद्ध, बगावत, विद्रोह, तोड़-फोड़ आतंकवाद आदि नागरिक अशांति से होने वाले संपत्ति व लाभ के नुकसान के प्रति सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। आईसीएसआईडी “विवाद निपटान” की सेवाएं प्रदान करता है और सरकार एवं निजी निवेशकों के बीच विवाद के निपटारे के लिए लगभग गोपनीय अदालत की तरह काम करता है।⁵

छठवीं संस्था वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है और विश्व बैंक की “क्षमता निर्माण शाखा” की तरह काम करती है और काफी शोध करती है जिसे विश्व बैंक अपनी विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को तर्कसंगत ठहराने के लिए उपयोग करता है। वह अपने ग्राहक देशों में नवउदारवादी विकास मॉडल के लिए आज्ञाकारी सामाजिक-राजनैतिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं संस्थागत क्षमता निर्माण प्रदान करती है। विश्व बैंक खुद को “ज्ञान संस्था” कहता है। ज्ञान के क्षेत्र में स्वयं को अगुआ की तरह स्थापित करने के लिए उसने जानकारी केन्द्रों एवं विकास पोर्टलों एवं ज्ञान “गेटवे” में काफी रकम लगाई है।⁶

ऐसी गतिविधियां जो कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, विकास एवं सहयोग को प्रोत्साहित करे, वित्तपोषित करने के लिए क्षेत्रीय एमएफआई के तौर पर एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। अब एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विश्व बैंक के बाद विकास वित्त प्रदान करने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा माध्यम है। यह अपने विकासशील सदस्य देशों में सरकारों एवं निजी उद्यमों को कर्ज (रियायती एवं लगभग बाजार दर पर), आंशिक जोखिम गारंटी, इक्विटी निवेश एवं टीए गारंटी प्रदान करता है। विश्व बैंक की तरह एडीबी के पास निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई अलग संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन इसके पास विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट इकाई है।

एडीबी ने सह-वित्तीय योजनाओं के माध्यम से बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एवं निजी वित्तीय संस्थाओं से विकास गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक एवं निजी पूंजी दोनों का ही संयोजन किया है। इसके केन्द्र में है भौतिक ढांचागत परियोजनाओं में सरकारों एवं निजी कंपनियों के बीच “सार्वजनिक-निजी भागीदारी” को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से एडीबी ने सरकार की भागीदारी एवं आंशिक जोखिम गारंटी के लिए निजी निवेशकों को कर्ज प्रदान किया है।

विश्व बैंक और एडीबी की घुसपैठ लगभग उस हर क्षेत्र में है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि कृषि, खाद्यान्न, ग्रामीण विकास, परिवहन, ऊर्जा, पानी, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, सार्वजनिक वित्त, बीमा, पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा एवं युद्ध पश्चात व विपदा पश्चात पुनर्वास व पुनर्निर्माण प्रमुख हैं। भले ही क्षेत्र, नीति की शर्तें कुछ भी हो, विश्व बैंक एवं एडीबी के वित्तपोषण में एंटी की सलाह होती है कि :

- सेवाएं और वस्तु उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम तरीका है “मुक्त” एवं खुला बाजार (जैसे कि पूंजी, तकनीक, रोजगार आदि);
- विकास बाजार आधारित होना चाहिए; सरकार को सब्सिडी समाप्त करनी चाहिए (क्योंकि ये बाजार को “विकृत” करती हैं) और सभी क्षेत्रों को लाभ आधारित बनाने के लिए उनका बाजारीकरण करना चाहिए;
- देश के विकास की रणनीति का आधार मुक्त व्यापार एवं निवेश होना चाहिए; देशों को निर्यात आधारित उत्पादन मॉडल अपनाना चाहिए, एवं; अपने घरेलू बाजार एवं क्षेत्रों को निजी, कंपनी निवेशकों, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए खोल देनी चाहिए;
- हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वह पानी, सैनिटेशन, पर्यटन, कृषि भंडारण या वित्तीय सेवाएं हों;

⁵ विश्व बैंक के इतिहास, संचालन, सदस्यों, संस्थाओं एवं क्रियाकलापों की जानकारी के लिए वेबसाइट देखें : www.worldbank.org

⁶ ज्यादा जानकारी के लिए देखें : <http://go.worldbank.org/53LOBQ2OK0>

- सरकार को निजीकरण के लिए “सक्षम नीति वातावरण” तैयार करना चाहिए, एवं ऐसे नियम व कानून बनाने चाहिए जो कि घरेलू एवं विदेशी निजी कंपनियों के लिए “एकसमान मौके” उपलब्ध कराएं;
- सरकारों को ऐसी अभिशासन प्रणाली एवं व्यवहार अपनानी चाहिए जो कि बाजार एवं निजी क्षेत्र के अनुकूल हो।

व्यवसाय में आना

इसमें कोई शक नहीं कि पर्यटन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि परिष्कृत पर्यटक दुनिया भर में ज्यादा मजेदार स्थलों की तलाश में रहते हैं तो अनछुए समुद्री तट, आकर्षक प्राकृतिक संसाधनों, असमान्य भौगोलिक विशेषताओं एवं स्थानीय आकर्षण, विदेशी पर्यटन एवं इकोटूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। लगता है कि पर्यटन उद्योग की तेजी समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। इससे पर्यटन एवं मेजबानी क्षेत्र के निवेशकों के लिए नये अवसर दिखते हैं, खासकर विकासशील देशों में, जो कि खास अनुभव चाहने वाले पर्यटकों के लिए जबरदस्त प्रस्ताव करते हैं।⁷

हालांकि अन्य क्षेत्र के क्रियाकलाप के मुकाबले इस क्षेत्र में उपस्थिति कम दिखती है लेकिन एमएफआई प्राकृतिक रिजॉर्ट, नदी एवं जंगली पर्यटन एवं सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रों में आने वाले पर्यटकों एवं व्यावसायिक यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न किस्म के पर्यटन एवं पर्यटन संबंधित संरचनाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय हैं। पर्यटन संवर्द्धन योजनाएं अक्सर पर्यावरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण योजनाओं, जैवविविधता संरक्षण क्षेत्रों, वन संरक्षण एवं शहरी विकास एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं से जुड़े होते हैं। एमएफआई के पर्यटन क्षेत्र में शामिल होने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे पर्यटन परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं निजी कंपनियों से वित्त जुटाते हैं और साथ ही पर्यटन के लगभग हर पहलु में निजी क्षेत्र के प्रवेश एवं विस्तार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

निश्चित तौर पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। चूंकि इसका स्वभाव पार-देशीय है तो पर्यटन उद्योग का दायरा आप्रवास प्रक्रियाओं, वायु, रेल, जल परिवहन, से लेकर भोजन, पेय पदार्थों की मेजबानी, ऐतिहासिक विरासतों व हस्तशिल्पों, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संरक्षण – जिनसे रोजगार, निजी आय एवं सार्वजनिक राजस्व (कई प्रकार के करों से) उत्पन्न होते हैं और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में एवं संभावनाओं में बढ़ोतरी होती हो – तक फैला हुआ है। जबकि पर्यटन से बहुत जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं राजनैतिक असर भी होते हैं। यह कीमती संसाधनों एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे जल, जंगल, बिजली एवं खाद्यान्न आदि के लिए आकर्षण की तरह काम करता है और अक्सर हर जगह स्थानीय संसाधनों का खिचाव और कमी हो जाती है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जल, जंगल और जमीन आदि प्रमुख संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। पर्यटन को संभव बनाने के लिए भौतिक संरचना की जरूरत होती है – उदाहरण के लिए एयरपोर्टों, सड़कों, होटलों, रेस्तराओं, जलक्षेत्रों, पार्कों एवं शॉपिंग क्षेत्रों की – इसके लिए अक्सर स्थानीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है, स्थानीय भोजन एवं पानी के स्रोत नष्ट होते हैं, और स्थानीय समुदायों को अनियंत्रित बाजार गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। इसके दीर्घकालीन असरों का पूरा मूल्यांकन भी नहीं हो पाता और इनके असर भी शायद ही कम हो पाते हैं।

चालाकीपूर्ण प्रचार एवं प्रोत्साहन के जरिए पर्यटन को किसी वस्तु, क्षेत्र, कार्यक्रम या परिस्थितियों के बजाय बिकाऊ उत्पाद बनाया जा सकता है, चाहे स्थानीय वन उत्पादों एवं खाद्यान्नों, नमभूमियों, भीड़ भरे बाजार, समुदाय व सामाजिक परंपराएं, धर्म एवं धार्मिकता या यहां तक कि नरसंहार एवं शारीरिक जोखिम एवं असुरक्षा से जुड़ी यात्रा हो। और जब ये सब राजस्व उगाहने वाले बन सकते हैं तो इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं इकोलॉजिकल लागत काफी ज्यादा होती है, जैसे स्थानीय एवं अक्सर विशिष्ट इकोसिस्टम, ज्यादा पेड़ों एवं वनों की कटाई, ज्यादा खपत के कारण महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की कमी (उदाहरण के तौर पर मछली एवं अन्य जलीय प्रजातियां), पर्यावरणीय प्रदूषण एवं मिलावट, पारंपरिक पूज्य स्थलों का बाजारीकरण एवं उल्लंघन, सामाजिक विलगाव (खासकर आदिवासियों एवं युवाओं में), यौन एवं मनोरंजन उद्योगों की बढ़ोतरी एवं खासकर महिलाओं एवं बच्चों की शारीरिक असुरक्षा बढ़ना आदि।

ज्यादा राजस्व एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना होने के कारण एवं जरूरी संरचना का कारक होने के कारण विकासशील देशों में पर्यटन को सरकारों, एमएफआई एवं अन्य वित्तपोषकों द्वारा आर्थिक विकास का प्रमुख

⁷ <http://www.miga.org/documents/tourism06.pdf>

कारक कहकर बहुत जोर-शोर से बढ़ावा दिया जाता है। उनका तर्क होता है कि नकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय असरों को उपयुक्त नियोजन से हमेशा समाप्त किया जा सकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक यह है कि राजमार्गों, पुलों, होटलों, गोल्फ कोर्सों एवं रिजॉर्टों के लिए पर्यटन के रकम लगने के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। जब पर्यटन एवं मेजबानी उद्योग में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो, ज्यादा नौकरियां उपलब्ध होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होगा और दीर्घकाल में समाज को लाभ होगा।

विश्व बैंक और एडीबी पर्यटन परियोजनाओं को सीधे वित्तीय एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ ही भौतिक व संस्थागत ढांचों एवं सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण परियोजनाएं जिससे दीर्घ काल में पर्यटन तेजी से बढ़ने की संभावना होती है, उदाहरणतया सड़कें, एयरपोर्ट, पुल, बंदरगाह, होटल, नगरीय सेवा आधारित ढांचे, पुरातात्विक पुनर्निर्माण एवं पर्यावरणीय संरक्षण। वे पर्यटन एवं संबंधित ढांचागत परियोजनाओं के लिए टिकाऊ विकास, पर्यावरणीय व सांस्कृतिक संरक्षण, नौकरियां उत्पन्न करने एवं स्थानीय आर्थिक विकास के नाम पर सहयोग करते हैं। दोनों संस्थाएं सांस्कृतिक परंपरा के बाजार पर आधारित “समुदाय आधारित” एवं “गरीबों के अनुकूल पर्यटन”, पर्यटन उद्योग के लिए स्थानीय उत्पादों, व सेवाओं, पर्यटन राजस्व को स्थानीय अर्थव्यवस्था से बाहर जाने से रोकने, और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पर्यटन को लाभकारी बनाने की बात करते हैं। और जब विश्व बैंक और एडीबी दोनों ही गरीबी निवारण का दावा करते हैं तो उनकी पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति वास्तव में “गरीब अनुकूल” दिखने लगती है। एडीबी का एक दस्तावेज जो “गरीब अनुकूल पर्यटन” की चर्चा करती है, उसका कहना है कि:-

पर्यटन में गरीबों के अनुकूल पहलों के लिए अन्य उत्पादक क्षेत्रों के मुकाबले कई फायदे हैं : (क) उपभोक्ता (पर्यटक) अक्सर वहां जाते हैं जहां गरीब मौजूद हो सकते हैं; (ख) पर्यटन तुलनात्मक रूप से श्रम आधारित (एवं लैंगिक संतुलित) होता है; (ग) गरीब देशों में अक्सर निर्यात लायक कम उत्पाद होते हैं, एवं (घ) गरीबों को अक्सर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं सांस्कृतिक संपत्तियों का पर्यटन में इस्तेमाल हो सकता है।⁸

अन्य कारक जो कि वास्तव में पर्यटन को “गरीब अनुकूल” बनाते हैं उनमें शामिल हैं पर्यटन क्षेत्र में गरीबों को रोजगार (उदाहरणतया पर्यटक गाइड, रेस्तराओं में वेटर, हस्तशिल्प उत्पादक, आदि), उन व्यवसायों द्वारा पर्यटन उद्योग को वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करना जिनसे गरीबों को रोजगार मिलता है, गरीबों द्वारा पर्यटन से जुड़े छोटे उद्यम स्थापित करना (उदाहरणतया गांवों के घरों में ठहरने की व्यवस्था और आदिवासी लोगों के क्षेत्र में घूमना), ढांचागत परियोजनाओं में निवेश, बाजार की उपलब्धता बढ़ाना एवं संप्रेषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार आदि।

विश्व बैंक पर्यटन को आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी एवं एमआईजीए के माध्यम से वित्तपोषित करता है। आईबीआरडी-आईडीए के वित्तपोषण सीधे सरकारों के पास पहुंचते हैं जबकि आईएफसी एवं एमआईजीए के सहयोग निजी कंपनियों के पास पहुंचते हैं। हालांकि ये संस्थाएं अलग-अलग विभाग से संबंधित हैं, लेकिन विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कई पर्यटन परियोजनाओं में सरकार एवं निजी क्षेत्र को कर्ज और टीए का मिला-जुला हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर जॉर्डन में विश्व बैंक ने पांच शहरों (जेराश, कैरक, मैडाबा, साल्ट एवं अल्जौम) में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं पेट्रा अभयारण्य (सैंचुरी) में पर्यटन प्रबंधन में सुधार करने के लिए 560 लाख डॉलर की मदद दी है। परियोजना के हिस्सों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इलाकों को पुनः कायम करना, शहरों में ढांचागत सुधार, छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय व तकनीकी मदद, एवं नगर निगमों व स्थानीय निजी उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण करना शामिल है।⁹ हाल ही में विश्व बैंक ने चीन के गांसू प्रांत में पर्यटन विकास एवं सिल्क रोड के संरक्षण के लिए 384 लाख डॉलर का लोन दिया है। कोष का इस्तेमाल चीन की ऐतिहासिक दीवार, माउंट माइजी क्षेत्र में एक जूलोजिकल पार्क और कई मंदिरों व मूर्तियों सहित गांसू के हिस्से के सिल्क रोड सहित नौ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्निर्माण एवं संरक्षण के लिए किया जाएगा। कोष का इस्तेमाल स्थलों के संरक्षण में लगे अधिकारियों एवं संरक्षण प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने में भी किया जाएगा।

आईएफसी पर्यटन के वित्तपोषण के लिए एक आकर्षक विभाग भी बना रहा है। सन 1956 से, आईएफसी ने 78 देशों में 231 पर्यटन परियोजनाओं के लिए लगभग 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश किया है, और इसकी मौजूदा पर्यटन विभाग का पोर्टफोलियो 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर है जिसमें से 90 प्रतिशत कर्ज के तौर पर वित्तपोषण किया गया है। इनकी गतिविधियों में आवास व्यवस्था, मनोरंजन पार्क, विशेष यात्रा जहाज एवं इकोटूरिज्म शामिल

⁸ www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/37626-01-GMS/vol2/annex6.pdf; पेज 84

⁹ <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21201247~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html>

है।¹⁰ प्रशांत महाद्वीप के देशों में आईएफसी पर्यटन के लिए वित्त उपलब्ध करा रहा है, छोटे एवं मध्यम उद्यमों में क्षमता विकास के माध्यम से निजी निवेश को मदद कर रहा है, एवं निजी पर्यटन व्यवसाय के विकास को समर्थन करने वाली नियामक वातावरण को मजबूत करके “व्यवसाय अनुकूल माहौल” तैयार कर रहा है।¹¹

मीकांग क्षेत्र¹² में आईएफसी का पर्यटन के लिए सहयोग मीकांग प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट फ़ैसिलिटी के माध्यम से दिया जाता है जो कि विएतनाम, कंबोडिया और लाओ पीडीआर में छोटे एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देते हैं।¹³ हालांकि आईएफसी के नेतृत्व में एमपीडीएफ भी एडीबी और बहुत सारे द्विपक्षीय सहयोगकर्ताओं से वित्तीय सहायता हासिल करता है।¹⁴ इनके पास 6 अंतर्संबंधी कार्यक्रम हैं : व्यवसाय योग्य वातावरण कार्यक्रम, वित्तीय बाजार विकास कार्यक्रम, व्यवसाय क्षेत्र प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, पर्यटन कार्यक्रम, वस्त्र व हस्तशिल्प कार्यक्रम एवं कृषि व्यवसाय कार्यक्रम। एमपीडीएफ द्वारा विकसित वेबसाइट का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर उनकी सेवाओं की बिक्री के लिए छोटे और मध्यम आकार के आवास सुविधा प्रदान करने वालों को मदद करके पर्यटन कार्यक्रम को कंबोडिया, विएतनाम, एवं लाओ पीडीआर में उभरते हुए पर्यटन क्षेत्र में तेजी लाने पर केन्द्रित किया जाता है। कंबोडिया में एमपीडीएफ एक साल लम्बी टिकाऊ पर्यटन परियोजना चला रहा है जो कि पर्यटकों को ज्यादा समय ठहरने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान करने को प्रोत्साहित करता है।¹⁵

विश्व बैंक के पर्यटन परिदृश्य में विश्व बैंक की सहयोगी एमआईजीए भी है जो कि निजी निवेशकों को स्वायत्तता और राजनैतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। एमआईजीए का अनुमान है कि पर्यटन विश्व का सबसे तेजी से विकसित होता उद्योग है और सन 2010 तक विश्व के सबसे बड़े उद्योग कृषि को पछाड़ देगा।¹⁶ एमआईजीए के अनुसार जो देश पर्यटन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बने रहना चाहते हैं उन्हें पर्यटन के “उत्पादों” खासकर बुनियादी ढांचा, आवास एवं सम्बन्धित सेवाओं को अच्छा बनाए रखना चाहिए। विकासशील देशों के लिए ऐसे मानक बनाए रखने में “पर्यटन संपत्ति” की क्षमता को हासिल करने के लिए निजी पूंजी एवं तकनीकी और संस्थागत क्षमता तक पहुंच का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी चुनौतियां कम आय वाले देशों, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बदल रहे देशों, युद्ध से उबर रहे देशों एवं “कमजोर राजनैतिक आधार” वाले देशों में काफी ज्यादा हैं जहां अस्पष्ट एवं कमजोर निजी संपत्ति व राजस्व प्रत्यावर्तन कानून की वजह से विदेशी निवेशकों का मुनाफा असुरक्षित हो सकता है। एमआईजीए का दावा है कि वह पर्यटन उद्योग में विदेशी निजी निवेशकों को गैर व्यावसायिक जोखिमों के बदले राजनैतिक जोखिम बीमा प्रदान करके और मेजबान सरकारों एवं बीमा किए गए निवेशकों के बीच विवाद की मध्यस्थता करके इस चुनौती से निपट सकती है। एमआईजीए ने पर्यटन क्षेत्र में 32 परियोजनाओं को कुल 2,740 लाख डॉलर की गारंटी प्रदान की है, जिनमें ज्यादातर ऊच्च-स्तरीय मेजबानी एवं भौतिक ढांचागत परियोजनाएं हैं।¹⁷

इससे बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी एडीबी भी बहुत जोर-शोर से पर्यटन को वित्तपोषण कर रहा है। भारत में इंकलूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को मदद करने की एडीबी की अवधारणा को बखूबी प्रस्तुत किया है। मई से अक्टूबर 2007 तक भारत सरकार को “राष्ट्रीय पर्यटन संरचना विकास रोड मैप” विकसित करने में मदद करने के लिए एडीबी ने एक अध्ययन करवाया, जिसका उद्देश्य देश में व्यापक स्तर पर पर्यटन संरचना की आवश्यकता दर्शाना था। अध्ययन में भारत के पर्यटन विन्यासों, उच्च क्षमता वाले पर्यटन इलाके एवं परिधि, बाजार प्रवृत्ति, एवं आगामी दस सालों में बुनियादी ढांचा, संस्थागत एवं नियामक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया। एडीबी के अनुसार “पर्यावरणीय टिकाऊ, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील एवं सामाजिक पर्यटन विकसित करने के लिए भारत के साथ एडीबी की भागीदारी के लिए” टीए एक और कदम है।¹⁸ अध्ययन के आधार पर एडीबी ने पर्यटन संरचना विकास परियोजनाओं को भविष्य में कर्ज देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

¹⁰ http://www.ifc.org/ifcext/gms.nsf/Content/Retail_Overview

¹¹ <http://www.ifc.org/ifcext/pacificedf.nsf/Content/TourismHome>

¹² दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र जिसमें दक्षिणी चीन, पूर्वी बर्मा, उत्तर व उत्तर पूर्व थाइलैंड, लाओ, पीडीआर और विएतनाम शामिल है।

¹³ <http://www.ifc.org/ifcext/eastasia.nsf/Content/MPDFI>

¹⁴ इनमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्वीटजरलैंड एवं यूके शामिल हैं।

¹⁵ http://www.ifc.org/ifcext/mekongpsdf.nsf/Content/Tourism_Program

¹⁶ http://www.ifc.org/ifcext/mekongpsdf.nsf/Content/Tourism_Program

¹⁷ <http://www.miga.org/documents/tourism06.pdf>

¹⁸ भारत : व्यापक पर्यटन संरचना विकास परियोजना (जापान विशेष कोष द्वारा वित्त पोषित) तैयार कर रही है। एडीबी, तकनीकी सहायता रिपोर्ट। परियोजना संख्या : 40648, दिसंबर 2007

भावी कर्ज परियोजना में सड़क, परिवहन, हवाई अड्डे, सीवेज, पानी, ठोस कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, पर्यटन सुविधाएं व सेवाएं (उदाहरण के तौर पर पर्यटन सेवा केन्द्र, पर्यटन सूचना सुविधाएं/पटल), प्रमुख मार्गों व स्थलों पर सुविधाएं (उदाहरण के तौर पर शौचालय एवं ठहरने की जगह) एवं समुदाय आधारित पर्यटन योजनाएं शामिल हो सकती हैं। सभी भावी परियोजनाओं में पर्यटन संरचना विकास, “संपत्ति प्रबंधन”, आवास एवं होटल आदि में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थागत एवं नियामक ढांचे भी शामिल होंगे। एडीबी बोर्ड के पास 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कम से कम तीन परियोजनाएं 2009 में मंजूरी के लिए पहले से ही प्रस्तावित हैं।¹⁹

उपरोक्त परियोजनाएं भारत में पर्यटन संरचना एवं विशेष संरचना बनाना शुरू करने के लिए भारत सरकार की *राष्ट्रीय पर्यटन संरचना वित्तपोषण आवश्यकता* की पूर्ति करते हैं। इसे राज्य स्तर पर भी करने को सोचा गया है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में एडीबी *पर्यटन संरचना विकास परियोजनाओं* (टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स) नाम से एक पहल को वित्तपोषण कर रहा है, जिसके अंतर्गत यात्रा सर्किट, पर्यटन पैकेज व सुविधाएं एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग से मेजबानी व यात्रा सेवाओं को सहयोग की संभावना है।²⁰

एडीबी के कार्यक्रम की एक विशेषता जो उसे विश्व बैंक से अलग स्थापित करती है, वह उपक्षेत्रीय अर्थिक सहयोग कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं सहयोग करना है जो कि पड़ोसी देशों को सहयोग वाले क्षेत्रों में मुक्त व्यापार व निवेश करने के लिए करीब लाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रेटर मीकांग उपक्षेत्रीय आर्थिक कार्यक्रम (जीएमएस) से लेकर एडीबी ने इस मॉडल को दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक कार्यक्रम (एसएसएसईसी) के साथ दक्षिण एशिया में एवं केन्द्रीय एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सीएआरईसी) के साथ केन्द्रीय एशिया में फैलाया है। एडीबी अपने सभी उपक्षेत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में पर्यटन को अभिन्न हिस्सा मानता है।

एसएसएसईसी में, एडीबी ने एसएसएसईसी पर्यटन कार्यसमूह की स्थापना की है (जो कि 2001 में शुरू हुआ) और एसएसएसईसी पर्यटन विकास योजना को वित्तपोषित कर रहा है और “धार्मिक पर्यटन एवं प्रकृति व संस्कृति आधारित इकोटूरिज्म से जुड़ी बहुदेशीय सर्किट” विकसित करने के लिए एसएसएसईसी सदस्यों²¹ के लिए टीए प्रदान कर रहा है। चुने हुए पर्यटन सर्किटों में ज्यादा समय के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन आधारित संरचनाओं एवं सुविधाओं से संबंधित बहुदेशीय निवेश की प्राथमिकता वाले पैकेज तैयार करने की योजना है। एडीबी की प्रमुख शहरी विकास विशेषज्ञ सुश्री गुल्फर केजाइरली के अनुसार, “प्रस्तावित परियोजना में ऐसे उपाय शामिल करने सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि स्थानीय समुदाय पर्यटन विकास के लाभों में हिस्सेदारी करें; नाजुक सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा हो; एवं पर्यटन संरचना एवं संपत्तियों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम हो।”²²

एडीबी के जीएमएस कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग की जाने वाली पर्यटन परियोजनाएं इस बात के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं कि किस तरह गरीबी निवारण, रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति, संस्कृति, लोगों एवं इतिहास को पैकेज बनाकर पर्यटन के उत्पाद की तरह बेचा जाता है। इस बात से सहमत कराकर कि क्षेत्र के गरीब देशों में तीव्र अर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण के लिए पर्यटन सबसे अच्छा प्रस्ताव है, एडीबी आक्रामक तरीके से जीएमएस के अंतर्गत पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहा है।

मीकांग क्षेत्र भौगोलिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से अलग एवं आकर्षक क्षेत्र है। इसका नाम मीकांग नदी पर आधारित है, जो कि लगभग क्षेत्र की जीवनरेखा है और दक्षिण पश्चिम चीन (जहां इसे लैंकांग कहा जाता है) के हाइलैंड से लेकर दक्षिण विएतनाम के डेल्टा तक समुदायों, सूक्ष्म पर्यावरणों एवं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ती है। यह क्षेत्र आर्थिक असमानता गरीबी का क्षेत्र भी है। पिछले कई दशकों से अपने विशिष्ट राजनैतिक इतिहास एवं खास इकोसिस्टम के कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण है। हालांकि क्षेत्र के लोग भौगोलिक सीमाओं की हिस्सेदारी करते हैं लेकिन वे अपने प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक धरोहरों को पैकेज करके बेचने के मामले में लक्ष्यों एवं महत्वाकांक्षाओं की उसी तरीके से हिस्सेदारी नहीं करते हैं।

¹⁹ <http://www.adb.org/Documents/PIDs/40648012.asp> एवं <http://www.adb.org/Documents/PIDs/40648012.asp>

²⁰ <http://www.thehindu.com/2007/08/08/stories/2007080861810900.htm>

²¹ ये देश हैं : बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल एवं श्रीलंका।

²² <http://www.adb.org/Media/Articles/2007/12092-asian-tourism-development/>

एडीबी के अनुसार, हालांकि मीकांग क्षेत्र विश्व में सबसे तेज विकसित होता पर्यटन क्षेत्र हैं, लेकिन आपस में पर्यटन प्रोत्साहन एवं बाजारीकरण के समन्वित प्रयास का अभाव, कई संभावित पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचने में दिक्कतें, खराब यात्रा व पर्यटन संरचनाएं एवं पर्यटन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में नीतिगत एवं संस्थागत क्षमताओं के अभाव के कारण जीएमएस देश पर्यटन का पर्याप्त तरीके से दोहन नहीं कर सके हैं। एडीबी का तर्क है कि पर्यटन उद्योग में दुनिया भर में इतनी प्रतियोगिता है कि मीकांग क्षेत्र, पर्यटन में तभी टिक सकता है जब क्षेत्र की सरकारें, इस क्षेत्र को एकल पर्यटन क्षेत्र के तौर पर बढ़ावा दें। इसके अलावा तर्क यह है कि क्षेत्र के गरीब विकसित पर्यटन से लाभान्वित हों एवं अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी, गरीब-अनुकूल समुदाय आधारित पर्यटन में ज्यादा निजी निवेश, और मीकांग क्षेत्र में ज्यादा पर्यटकों को प्रवेश के माध्यम से सक्रिय भागीदारी कर सकें।²³

उपरोक्त बातों का ध्यान में रखते हुए जीएमएस पर्यटन क्षेत्र रणनीति (टीएसएस) का उद्देश्य है कि मीकांग क्षेत्र को “अच्छी गुणवत्ता एवं उच्च उत्पादक उपक्षेत्रीय उत्पादों की विभिन्नता”; जीएमएस सदस्यों की समन्वित राष्ट्रीय पर्यटन प्रयासों; जबकि नकारात्मक असरों को कम करते हुए गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं उचित विकास के प्रति योगदान के आधार पर एकल पर्यटन लक्ष्य के तौर पर विकसित किया जाय। सन 2006 से 2015 की अवधि के लिए टीएसएस के सात प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य हैं : मार्केटिंग एवं उत्पाद विकास; पर्यटन आधारित बुनियादी विकास; मानव संसाधन विकास; प्राकृतिक, सांस्कृतिक-सामाजिक असर प्रबंधन; गरीब अनुकूल एवं लाभों का एकसमान वितरण; निजी क्षेत्र की भागीदारी, एवं पर्यटकों के लिए आवागमन की सुविधा प्रदान करना।²⁴

सन 2006 से 2010 के लिए प्राथमिकता वाले उनतीस परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए चुना गया है। इनमें महत्वपूर्ण संख्या में बुनियादी ढांचा आधारित परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डों को बेहतर बनाना, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में सड़कों को बेहतर करना, नदी तट विकास, जल आपूर्ति, बिजली, बाजार, मनोरम स्थलों का सुन्दरीकरण आदि शामिल हैं। पर्यटन विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के चयन (कुछ आर्थिक गलियारे से सम्बन्धित), टिकाऊ एवं गरीब-अनुकूल पर्यटन विकास के लिए टीए, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मार्केटिंग एवं उत्पाद विकास, एवं धरोहरों का संरक्षण व सामाजिक असर प्रबंधन की परियोजनाएं भी एजेंडे में हैं। मीकांग पर्यटन को “ब्रांड” के तौर पर प्रोत्साहित करने व उद्योग और सरकार के लिए जानकारी के माध्यम के तौर पर काम करने के लिए, एवं जीएमएस पर्यटन कार्य समूह को कार्यालय सहयोग प्रदान करने के लिए बैंकाक में एक मीकांग पर्यटन कार्यालय की स्थापना की गई है।²⁵ एडीबी की सरकारों, बहुपक्षीय विकास एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी व स्थानीय प्रत्यक्ष निजी निवेश, अंतरराष्ट्रीय निजी इक्विटी फंडों एवं अंतरराष्ट्रीय और एवं घरेलू पूंजी बाजारों आदि कई माध्यमों से जीएमएस पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोष एकत्र करने की योजना है।²⁶

अधिकारों एवं संसाधनों की अवहेलना

इकोटूरिज्म एवं गरीब-अनुकूल टिकाऊ पर्यटन के बारे में बेहतर बखान करने के बावजूद एमएफआई द्वारा वित्तपोषित की जाने वाले पर्यटन, बुनियादी व विकास परियोजनाओं के बारे में पिछले खराब कार्य प्रदर्शन इनके बारे में आशंका उत्पन्न करते हैं।

सन 1998 की शुरुआत में, विश्व बैंक और जापान ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड थाइलैंड में 1997 की एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप रोजगार व आमदनी में हुए नुकसान की समस्या हल करने लिए एक सामाजिक निवेश योजना (एसआईपी) के लिए करीब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने के लिए सहमत हुआ। इन कोषों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन संबंधित गतिविधियों, खासकर इको-टूरिज्म एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। अगले कुछ सालों में, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय समुदायों और रॉयल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट (आरएफडी) के बीच इको-टूरिज्म परियोजनाओं पर विवाद उभरा। ये परियोजनाएं फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री ऑर्गनाइजेशन (कटाई क्रियाकलापों पर निगरानी के लिए बनी सरकारी उद्यम) एवं निजी कंपनियों के सहयोग से लेकिन परियोजना स्थल पर निवासरत लोगों से विचार-विमर्श के बिना क्रियान्वित की जा रही हैं। गांव के लोगों का इसलिए विरोध है कि परियोजनाओं से उनकी संस्कृति और पर्यावरण को

²³ <http://www.adb.org/GMS/Projects/flagshipK.asp>

²⁴ <http://www.adb.org/GMS/Projects/flagshipK.asp>

²⁵ इस कार्यालय के बारे में जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : <http://www.mekongtourism.org>

²⁶ <http://www.adb.org/GMS/Projects/flagshipK.asp>

नुकसान होगा। इसी अवधि में, प्रेस और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का कहना है कि ग्रामीण एवं वन इलाकों सहित कानूनी रूप से संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों में इको-टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को आवास, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हो रहे निर्माण के प्रति काफी आक्रोश है।

विश्व बैंक, एसआईपी एवं ओइसीएफ के कोषों के माध्यम से थाइलैंड के राष्ट्रीय पार्कों एवं प्राकृतिक धरोहरों को इको-टूरिज्म के लिए तैयार होने से टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाइलैंड (टीएटी), आरएफडी एवं निजी कंपनियों के लिए बड़े व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हुए हैं। रणनीति के तहत, टूरिस्ट आवास, पार्किंग स्थल, सड़कें, शौचालय, लैंडिंग स्थलों, शिविर मैदानों एवं प्रकृति चिन्ह बनाने के नाम पर सघन जंगलों की कटाई करना शामिल है। अन्य उदाहरणों के तहत, थाइलैंड के आदिवासी समुदायों ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है कि उनकी संस्कृतियों, पोशाकों, गीतों एवं परंपराओं का तेजी से बाजारीकरण तो किया जा रहा है लेकिन राष्ट्रीयता व पारंपरिक क्षेत्रों से संबंधित उनके अधिकारों को थाई अथॉरिटी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

थाइलैंड के इको-टूरिज्म के अनुभवों की गूंज पूरे मीकांग क्षेत्र में भी है। हालांकि स्थानीय पर्यावरणों एवं समुदायों पर इको-टूरिज्म के असरों का व्यवस्थित मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी है, लेकिन पूरे क्षेत्र से खबर आ रहे हैं कि स्थानीय ग्रामीण लोगों को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय व आजीविका संसाधनों से तेजी से प्रतिबंधित किया जा रहा है क्योंकि वनभूमियों, नमभूमियों, नदी तटों और झीलों को पर्यटन के लिए छूट के तहत शांत रखा जाता है। लाओ पीडीआर, थाइलैंड और कंबोडिया में वनों, वन्यजीव वाले इलाकों एवं झीलों को संरक्षित क्षेत्र एवं जैवविविधता संरक्षण क्षेत्र की मान्यता दी जा रही है। कई पीढ़ियों से उस इलाके के रक्षक स्थानीय समुदायों (उनमें से बहुत सारे आदिवासी हैं) को वहां से खाद्य पदार्थ, जड़ी बूटी एवं जलावन लकड़ी आदि एकत्र करने से रोका जा रहा है। जबकि वहीं निजी कंपनियां इन इलाकों में कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीके से पेड़ों की कटाई, पौधरोपण, मछली पकड़ने एवं खनन में छूट पाने में सक्षम हैं। आदिवासी सांस्कृतिक व्यवस्था, घरों, कपड़ों एवं शिल्पों को पर्यटन उत्पाद के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन उन्हें पुरतैनी इलाकों और पारंपरिक खेती व्यवस्था को कायम रखने के अधिकारों से विकास नियोजकों एवं वित्तपोषकों द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जाता है।

चूंकि बहुत सारे इको-टूरिज्म परियोजनाएं भौगोलिक रूप से दूरदराज इलाके में स्थित होते हैं, इसलिए आम तौर पर इन परियोजनाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले समुदायों के पास मदद के ढांचे और मुआवजा व न्याय पाने की व्यवस्था नहीं होती है। कई घटनाओं में, समुदायों को परियोजना दस्तावेज में “हितधारी” कहने के बावजूद उनसे परियोजना के बारे में विचार-विमर्श तक नहीं किया जाता है और उनसे छीने जा रहे संसाधनों को परियोजना निर्माणकर्ताओं, वित्तपोषकों एवं सरकारों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। लाओ पीडीआर और कंबोडिया दोनों में ही इको-टूरिज्म और ऐशोआराम के पर्यटनों में आमतौर पर स्थानीय समुदाय जिन ‘लाभों’ की आशा करते हैं उनमें पर्यटकों के लिए स्थानीय टूर गाइड, नौकाओं या अन्य स्थानीय परिवहन संचालक, ठहरने वाली जगहों व रिजॉर्टों में वेंटर और नर्तक (“स्थानीय आनंद” के तहत सांस्कृतिक प्रदर्शन) की नौकरी प्रमुख हैं।

ऐसे अनुभव एमएफआई द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले और वित्तपोषित आर्थिक विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के दीर्घकालीन एवं व्यापक स्तर के नकारात्मक असरों को स्पष्ट करते हैं। विश्व बैंक-आईएमएफ द्वारा डिजाइन किए गए आर्थिक सुधार पैकेजों को पहले ढांचागत सुधार कार्यक्रम (एसएपी) कहा जाता था और बाद में पुनः नामकरण करके “गरीबी निवारण रणनीति” किया गया है। इसे कर्जदार देशों में व्यापार एवं निवेश उदारीकरण और सार्वजनिक सेवाओं, स्थानों एवं प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण के माध्यम से विदेशी निवेशकों के लिए बाजार एवं अर्थव्यवस्था के द्वार खोलने के विचार से डिजाइन किया गया है। सुधार की यह भी मांग होती है कि गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी, कामगारों एवं घरेलू उत्पादकों के लिए संरक्षण को समाप्त किया जाय और स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं सैनिटेशन सहित सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सेवाओं में तेजी से कटौती की जाय। कर्जदार देशों पर श्रम एवं पर्यावरणीय कानूनों को कमजोर करने एवं बाजार व निजी क्षेत्र के अनुकूल नीतियों की स्थापना करने का दबाव बनाकर विश्व बैंक वास्तव में स्थानीय समुदायों, किसानों, कामगारों, आदिवासी लोगों एवं पर्यावरण की कीमत पर निजी निवेशकों को खुला मौका प्रदान करता है।

एडीबी ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। नागरिक समूहों, शोधार्थियों, जन आन्दोलनों एवं नागरिक समाज संगठनों की स्वतंत्र रिपोर्टों ने स्पष्ट किया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र एडीबी समर्थित परियोजनाओं से निर्धारित होती हैं, जो कि खराब तरीके से डिजाइन, क्रियान्वित एवं प्रबंधित की जाती हैं। ये परियोजनाएं विकास नियोजन में सार्वजनिक भागीदारी को रोकती हैं और परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों के जानकारी के अधिकार को नकारती हैं। संचालन के गैर लोकतांत्रिक, गैर पारदर्शी एवं गैर विचार-विमर्श वाले तरीकों के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय अभिशासन कमजोर होती हैं। एडीबी समर्थित ढांचागत परियोजनाओं ने पूरे क्षेत्र में बार-बार सैकड़ों

हजारों लोगों को कम मुआवजा या बगैर मुआवजा के ही विस्थापित किया है। जिनके नकारात्मक पर्यावरणीय व सामाजिक असर हुए हैं। एडीबी इसे कम करने की फ़िक्र नहीं करता है। तब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे क्षेत्र के जन आन्दोलनों, नागरिक समाज संगठनों एवं शोधार्थियों ने एडीबी पर “विकास शरणार्थी” तैयार करने का आरोप लगाया है।

मीकांग क्षेत्र में ही अकेले तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों एवं आजीविका अवसरों तक लोगों और समुदायों को पहुंचने के अधिकार पर या तो जबरदस्त तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है या फिर एडीबी सहायतार्थ परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वे समाप्त हो गए हैं। एडीबी की “गरीब अनुकूल विकास” रणनीति ने सरकारों को न्यूनतम मजदूरी समाप्त करने और कामगारों के संगठित होने के अधिकार, लाभों और संरक्षणों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया है। पाकिस्तान, भारत, थाइलैंड, कंबोडिया एवं फिलीपींस जैसे देशों में एडीबी की परियोजनाओं व कार्यक्रमों का विरोध हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक समस्या पैदा हुई और फूट पड़ी है। विरोध करने वालों का अकसर राजनैतिक उत्पीड़न किया गया है।

एमएफआई द्वारा परियोजनाओं की असफलताओं, पर्यावरणीय विनाश एवं आजीविका समाप्त करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने की अनिच्छा भी उतनी ही चिंता का विषय है। एमएफआई पारंपरिक तौर पर स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों को अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि उनकी सभी परियोजनाएं कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय, एवं उपराष्ट्रीय विकास योजनाओं के तहत बनी होती हैं, लेकिन एमएफआई का दावा होता है कि निर्णय का अधिकार सरकारों के हाथ में होता है। इस तरह खराब परियोजना डिजाइन और क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार एवं परियोजना की असफलता राष्ट्रीय क्षमता और अभिशासन में व्यवस्थित कमियों की वजह से होता है।

एमएफआई दावा करते हैं कि वे गरीब-अनुकूल, जिम्मेदार, टिकाऊ एवं व्यापक किस्म के पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसानों को कम करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं और पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करते हैं। लेकिन एमएफआई सहायतार्थ पर्यटन परियोजनाओं में आदिवासी समुदायों, महिलाओं, गरीब ग्रामीणों व शहरी निवासियों एवं स्थानीय वातावरण और अर्थव्यवस्था पर पर्यटन से होने वाले नकारात्मक असरों का आकलन करने एवं उन्हें कम करने के उपाय शामिल नहीं होते हैं। पर्यावरण अनुकूल एवं गरीब अनुकूल पर्यटन की योजना विकसित करते समय, विश्व बैंक और एडीबी निजी कंपनियों एवं साधन संपन्न पर्यावरणीय एवं विकास स्वैच्छिक संस्थाओं को भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन वे “मेजबानी” क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं, या गोल्फ कोर्स, राजमार्गों, पोर्ट या प्रकृति रिजॉर्टों से विस्थापित होने वाले समुदायों के विचार नहीं जानना चाहते हैं।

चूंकि पर्यटन का स्वरूप बहु-राष्ट्रीय होता है इसलिए एक बार में इसके पूरे प्रभावों के बारे में आकलन करना कठिन होता है। जो आज सकारात्मक आमदनी व राजस्व उत्पादक गतिविधियां एवं अभिवादन बुनियादी परियोजनाएं दिखती हैं, उनके परिणामस्वरूप दीर्घकाल में स्थानीय उत्पादकों को खाद्यान्न एवं पानी की कमी, महिलाओं व पुरुषों का देह व्यापार के धंधे में प्रवेश एवं आदिवासी समुदायों की पारंपरिक धरोहरों का नुकसान हो सकता है। इस तरह यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समुदाय एवं नागरिक समाज संगठन नियमित तौर पर एवं दीर्घकाल तक पर्यटन विकास रणनीतियों एवं पर्यटन परियोजनाओं की निगरानी करें, और महत्वपूर्ण मुद्दों को नीति निर्माताओं और आम लोगों के सामने लाएं।

स्वयं को दोहराता इतिहास?

पर्यटन विकास में विश्व बैंक की विवादास्पद भूमिका का एक लेखा—जोखा

विद्या रंगन, *इक्वेशंस*, सितम्बर 2007

यह शायद कम प्रचलित तथ्य है कि पर्यटन क्षेत्र में एक दशक तक गंभीर रूप से शामिल रहने के बाद परमाणु ऊर्जा सहित पर्यटन उन कुछ गतिविधियों में से है जिसे विश्व बैंक¹ के निदेशक मंडल ने अस्सी के दशक में रोकने के लिए चुना था। आज जब विश्व बैंक फिर से नये जोश के साथ पर्यटन को सहयोग करना शुरू करना चाहता है, तो ऐसे में यह लेख बैंक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से शामिल रहने की पृष्ठभूमि में इस कदम का परीक्षण करता है।

पर्यटन क्षेत्र में विश्व बैंक के कामों की शुरुआत

विश्व बैंक समूह ने साठ के दशक के अंत में पर्यटन क्षेत्र में तब से कदम रखा था जब आईएफसी ने केन्या² में होटल की संपत्तियों में निवेश करना शुरू किया। तब से मुख्यतः मोरक्को एवं ट्यूनिशिया जैसे अफ्रीकी देशों के होटल और आवास उद्योग में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कोष उपलब्ध कराकर आईएफसी ने पर्यटन विकास के लिए वित्तपोषण जारी रखा। सन 1969 में विश्व बैंक ने विशेष तौर पर पर्यटन परियोजना विभाग (टीपीडी) की स्थापना की, जिसे अगले दशक के लिए पर्यटन क्षेत्र में बैंक के शामिल रहने को परिभाषित करने की प्रमुख भूमिका निभानी थी। विश्व बैंक द्वारा पहली पूर्ण विकसित पर्यटन परियोजना के लिए कर्ज सन 1971 में पूर्व यूगोस्लाविया की दो – बैबिन कुक और बेरनादिन – पर्यटन परियोजनाओं के लिए दी गई थी। साठ के दशक में पर्यटन के बारे में बैंक के अन्दर विचार एवं उसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों को पर्यटन परियोजनाओं पर आधारित कर्ज देना शुरू करने का निर्णय विश्व बैंक के “पर्यटन क्षेत्र आधार पत्र” (टूरिज्म सेक्टर वर्किंग पेपर) में दिखता है। यह 1972 में प्रस्तुत हुआ था और इस क्षेत्र में दशकों तक यह बैंक की क्रियाकलाप नीति बनी रही। यह पेपर तब तैयार हुआ था जब विश्व बैंक और आईएफसी ने पर्यटन क्षेत्र में तुरंत कदम ही रखा था। इस तरह उन नये अनुभवों के आधार पर इसे पर्यटन की भावी गतिविधियों पर लागू करने का विचार तय किया था।

यह आधार पत्र विकासशील देशों में पर्यटन के मामले में यह कहते हुए शुरुआत करता है कि – “सन 1960 और 1968 के बीच, विकासशील देशों से तेल के अलावा अन्य निर्यात प्रतिवर्ष बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक हो गया, तब पर्यटन से होने वाली आमदनी सालाना 11 प्रतिशत तक हो गई। विश्व बाजार की अनिश्चितता और औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों से ज्यादा निर्मित वस्तु आयात करने की अनुमति देने के बारे में अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, पर्यटन उन्हें विदेशी मुद्रा आदान-प्रदान में विविधता लाने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।” इस तरह इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विकासशील देशों में पर्यटकों के आने की संभावना और इनकी वजह से उन देशों के लिए आवश्यक पर्यटन सुविधाओं के बारे में वर्णन किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में बैंक के क्रियाकलाप की मात्रा व स्वरूप का निर्धारण करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस पत्र में उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

- विश्व में पर्यटन उत्पन्न करने वाले तीन प्रमुख देश हैं – उत्तरी अमेरिका (यू.एस. और कनाडा), पश्चिमी यूरोप एवं जापान। विकासशील देशों में आने वाले पर्यटकों सहित करीब तीन चौथाई अंतरराष्ट्रीय आवक 12 देशों से होती है – यू.एस., कनाडा, यू.के. फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्वीटजरलैंड, आस्ट्रेलिया एवं इटली।
- यह उम्मीद है कि हवाई यात्रा के समय और लागत में कमी होने से मेडिटेरेनियन नदीघाटी³, मैक्सिको और कैरिबियाई क्षेत्रों में ज्यादा पर्यटक आने की संभावना है। लम्बी दूरी की यात्रा के लिए विकासशील देशों में

¹ विश्व बैंक समूह में आपस में जुड़े पांच संस्थाएँ शामिल हैं – आईबीआरडी (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंशट्रक्शन एंड डेवलपमेंट), आईडीए (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन), आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन), एमआईजीए (मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी) एवं आईसीएसआईडी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसप्यूट)। समूह में हर किसी की अलग भूमिका है। इन संस्थाओं में से आईबीआरडी और आईडीए को संयुक्त रूप से आम तौर पर “विश्व बैंक” कहा जाता है।

आईबीआरडी की स्थापना 1944 में हुई और यह विश्व बैंक समूह की वास्तविक संस्था है, जो अपने 185 सदस्य देशों की मालिकाना में संचालित होता है। विश्व बैंक का हिस्सा आईडीए की स्थापना 1960 में हुई, जो कि ब्याज मुक्त कर्ज और अनुदान प्रदान करके विश्व के निर्धनतम देशों के लिए काम करता है। आईएफसी विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की घटक है जिसकी स्थापना 1956 में हुई है और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में निजी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एमआईजीए की स्थापना 1988 में हुई है, जो कि राजनैतिक जोखिम बीमा एवं गारंटी प्रदान करके बैंक की गतिविधियों को मदद करती है और युद्ध, संपत्ति जब्ती, नागरिक संघर्ष जैसे गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के दौरान निवेशकों की रक्षा करती है। आईसीएसआईडी की स्थापना 1966 में हुई है, जो कि मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से सरकारों एवं निजी निवेशकों के बीच विवादों का निपटारा करती है।

² आईएफसी का पर्यटन में पहला निवेश 1966 में हुआ था : क्रेडिट 0120 – केन्या होटल प्रोपर्टीज लिमिटेड
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html>

³ मेडिटेरेनियन क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज देश हैं – स्पेन, यूगोस्लाविया, यूनान, मोरक्को, अल्जिरिया, ट्यूनिशिया, मिस्र, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की एवं साइप्रस।

संभावित ज्यादा रुचिकर देश हैं पूर्वी अफ्रीका (केन्या, तंजानिया एवं यूगांडा), एवं दक्षिण पूर्व एशिया (नेपाल, थाइलैंड, इंडोनेशिया, भारत)। साठ के दशक के बाद जापान से पर्यटक आवक बढ़ने से कोरिया, चीन गणतंत्र और इंडोनेशिया में पर्यटक आवक बढ़ने की संभावना है।

- विकासशील देशों में ऐसे पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा पूरी करने की मांग होती है। इनमें होटलों एवं बोर्डिंग हाउस के अलावा पर्यटकों के लिए मनोरंजन व खेल सुविधाएं, आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं परिवहन और ऐतिहासिक/प्राकृतिक/सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तक पहुंचने की सुविधा भी शामिल होते हैं।
- ठहरने की व्यवस्था की इकाईयों की कमी एवं निजी निवेशकों द्वारा होटल की संपत्ति में धन लगाने की अनिच्छा के कारण विकासशील देशों की सरकारों एवं बैंक को अपनी पर्यटन विकास योजनाओं के पहलू पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके अलावा, सरकारों का प्रमुख काम होगा एकीकृत पर्यटन विकास योजना क्रियान्वित करना।

वर्किंग पेपर का यह भी कहना है कि पर्यटन के पिछले अनुभव के आधार पर बैंक “प्राथमिकता के आधार पर तुलनात्मक रूप से उन पर्यटकों के लिए सुनियोजित रिजॉर्ट इलाके विकसित करेगा जिनके ज्यादा बिखरे होने के बजाय ज्यादा किफायती होने की संभावना है....।” इसके अनुसार पर्यटन में वित्तपोषण के लिए बैंक समूह को दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं :

- होटलों एवं ठहरने की परियोजनाओं को वित्तपोषण करने से आगे ध्यान दें और सांस्कृतिक संपत्तियों की रक्षा के लिए वित्तपोषण को सहयोग करें।
- दो या ज्यादा देशों में संयुक्त वित्तपोषण (जैसे पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी एशिया) पर विचार करें जिससे इन सर्किटों के विकास में मदद मिल सकती है।
- पर्यटन उद्योग के लिए दक्ष व्यक्ति तैयार करने के लिए विकासशील देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करें।
- तकनीकी सहायता एवं क्षेत्रीय अध्ययन को एक साथ वित्तपोषण करें।

निम्नलिखित सारिणी 1972 तक विश्व बैंक द्वारा पर्यटन के लिए वित्तपोषण का सारांश और 1976 तक के अनुमानों का सारांश प्रदान करता है जिससे बैंक का पर्यटन के क्रियाकलाप की व्यापकता का संकेत मिलता है।

सारिणी 1 : सन 1969-73 तक विश्व बैंक समूह की पर्यटन गतिविधि एवं 1976 तक पूर्वानुमान का सारांश

	वास्तविक			कार्यक्रम		वास्तविक ¹		कार्यक्रम
	1969	1970	1971	1972	1973	1964-68	1969-73	1972-76
क्षेत्र अध्ययन	4	9	7	8	6	3	34	33
वादा (लाख डॉलर)	140	50	420	550	590	30	1750	4040
कुल बैंक समूह का प्रतिशत	1.0	0.2	1.6	2.0	2.1	0.1	1.4	2.4
देशों की संख्या	4	2	6	6	8	1	19	22
वित्तीय क्रियाकलापों की संख्या	4	2	7	6	8	1	27	44
निगरानी के अंतर्गत परियोजनाएं (अंतिम वित्तीय वर्ष)	5	7	12	18	25	1	14 ²	42 ²

1. सन 1972-73 के लिए कार्यक्रम सहित, 2. पांच साल का औसत

स्रोत : टूरिज्म सेक्टर वर्किंग पेपर, विश्व बैंक, 1972

बाद के दशक में, इस व्यापक आदेश के साथ बैंक के पर्यटन परियोजना विभाग ने विकासशील देशों के चुने हुए क्षेत्र में पर्यटन परियोजनाओं की जबरदस्त शुरुआत की। जैसे कि उम्मीद और आदेश था टीपीडी का निशाना बड़ी ढांचागत परियोजनाएं थी। विश्व बैंक द्वारा 1970-1980 के बीच वित्तपोषित 25 पर्यटन विशेष परियोजनाओं की प्रवृत्ति इस प्रकार रही :

- क्षेत्र आधार पत्र के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं के लिए चुने गए विकासशील देश एवं क्षेत्र – उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, मिस्र, ट्यूनिशिया; कैरिबियाई देशों में होंडुरास, बारबाडोस एवं डोमिनिक गणराज्य; दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल, इंडोनेशिया, कोरिया; मध्यपूर्व में जॉर्डन एवं तुर्की एवं केन्या, तंजानिया, सेनेगल, गांबिया, आइवरी कोस्ट (अफ्रीका में कोट डी आइवोइर) और मैक्सिको।
- पर्यटन परियोजनाओं के लिए औसत कर्ज की रकम थी करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर।
- इस अवधि में बैंक द्वारा जो एक खास परियोजना वित्तपोषित की गई थी उसमें शामिल था औसतन 3000 कमरे, पानी, सीवेज एवं परिवहन जैसे आवश्यक सहयोगी ढांचे; गंतव्य को बढ़ावा देने एवं मार्केटिंग के लिए सहयोग; स्थानीय लोगों को रिजॉर्ट/या गोल्फ कोर्स, खेल रिजर्व आदि अतिरिक्त मनोरंजन सुविधाओं में काम

करने के लिए प्रशिक्षण। इस अवधि में बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की विशेषताओं में पर्यटकों के लिए गंतव्य का मास्टर प्लान तैयार करना और पर्यटन में स्थानीय लोगों को रोजगार में लगाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास परियोजनाएं भी शामिल थीं।

इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटन विकास बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि पर्यटकों के आवक के साथ-साथ हवाई परिवहन क्षेत्र में भी सुधार हुआ। बैंक द्वारा ऐसी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए कर्ज देने के परिणामस्वरूप, विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एकीकृत पर्यटन कॉम्प्लेक्स को एक प्रमुख मॉडल के तौर पर अपनाया गया। एक दशक तक के क्रियाकलाप से पर्यटन के लिए बैंक द्वारा दिया जाने वाला कर्ज सन 1970 में 7 देशों के लिए 5 करोड़ डॉलर था जो 1980 में बढ़कर 27 देशों के लिए 1 अरब डॉलर हो गया। कुछ विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि 70 के दशक में ज्यादातर वैश्विक पर्यटन विश्व बैंक वित्तपोषित था (हॉकिंस एवं मान, 2007)। वास्तव में बैंक की मदद से उस समय शुरू हुए पर्यटन गंतव्य अब स्थापित हो चुके हैं, जैसे कि बाली, केन्या, मैक्सिको, गांबिया, डोमिनिक गणराज्य एवं ट्यूनिशिया। इस चरण में बैंक की गतिविधियों में आईएफसी की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी। विश्व बैंक समूह के निजी क्षेत्र के घटक होने के कारण, आईएफसी ने निजी होटल के निवेशकों पर व्यापक स्तर पर ध्यान दिया। उदाहरण के तौर पर, 1971 में केन्या और यूगांडा को दिए गए एक कर्ज को होटलों एवं दोनों देशों में सहयोगी पर्यटक कंपनियों के लिए वाहन सेवाओं जैसी सहायक सेवाओं के माध्यम से क्षेत्रीय सर्किटों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। ट्यूनिशिया को 1969 में दिया गया अन्य कर्ज देश में पर्यटन को प्रोत्साहित एवं वित्तपोषित करने वाली निजी कंपनी को नये रिजॉर्ट इलाके बनाने के लिए था। सारिणी 2 में 70 के दशक की शुरुआत में आईएफसी की परियोजनाओं की सूची दी गई है। ज्यादातर निवेशकों द्वारा होटल बनाने में पूंजी की कमी को पूरा करके आईएफसी बहुत जल्द ही होटल निवेशकों के लिए निजी कर्ज व इक्विटी पूंजी जुटाने का मुख्य बाहरी माध्यम बन गया। शुरुआती सालों में अफ्रीका, लैटिन अमेरीका एवं मध्य-पूर्व में पहले से स्थापित एवं भावी पर्यटन गंतव्यों के लिए होटलों का निर्माण एवं नवीनीकरण इसके मुख्य गतिविधियों में से एक था।

सारिणी 2 : आईएफसी द्वारा पर्यटन के लिए वित्तपोषण (1968-71)

देश	परियोजना	आईएफसी द्वारा वादा या मंजूर वास्तविक रकम (हजार डॉलर में)	वास्तविक वादा या मंजूरी का वित्तीय वर्ष	आईएफसी द्वारा तय राशि 31 दिसंबर 1971 को (हजार डॉलर में)			टिप्पणी
				इक्विटी	कर्ज	कुल	
केन्या	होटल संपत्ति	3204	1967,68	561	1550	2111	राजधानी शहर में 200 कमरों वाले होटल, कुछ खेल लॉज, और 100 कमरों वाले बीच होटल में आंशिक वित्तपोषण
जमैका	पीगैसस, जमैका के होटल	2913	1969	679	1280	1559	राजधानी में सम्मेलन होटल
अल-सल्वाडोर	होटल माइरामोंट	933	1969	333	600	933	राजधानी में 224 कमरों वाले प्रथम श्रेणी होटल
ट्यूनिशिया	साइ फाइनैसिएर एट ट्यूरिस्टिक	9905	1969	1905	6891	8796	पर्यटन विकास एवं होल्डिंग कंपनी
कोलंबिया	होटूरिज्मों	6	1969	6	—	6	होटल विकास कंपनी में भागीदारी
कोलंबिया	प्रो-होटल्स, एस.ए.	1045	1970	238	800	1038	प्रांतीय राजधानी में 225 कमरों का व्यवसाय व पर्यटन होटल
मॉरिशस	डाइनारोबिन इंस एंड मोटल्स लि.	600	1971	—	600	600	360 बिस्तरों के दो बीच होटल के लिए वित्तपोषण
पनामा	कॉर्प डी डेसरोल्लो, होटेलेरो एस.ए.	1473	1971	267	1206	1473	राजधानी शहर में 256 कमरों का होटल
केन्या एवं यूगांडा	टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज लि.	2420 1180	1971	—	3600	3600	950 बिस्तर युक्त 6 होटलों व लॉजों के लिए वित्तपोषण एवं 138 वाहन टूरिंग सेवा
	कुल	23679	—	3989	16257	20516	

स्रोत : टूरिज्म सेक्टर वर्किंग पेपर, विश्व बैंक, 1972

इस तरह कहा जा सकता है कि पर्यटन में शामिल रहने के सर्वोच्च स्थिति में विश्व बैंक (और आईएफसी) ने पर्यटन विकास के लिए विकासशील देशों के कुछ क्षेत्रों में कोष लगाया। ऐसे विकास में बड़े, भारी ढांचे, एकीकृत पर्यटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना तय किया था, जो कि मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार देश के चुने हुए क्षेत्र में स्थापित होने थे।

एकाएक ठहराव

हालांकि, 1978 में अचानक और अभूतपूर्व कदम के तहत विश्व बैंक ने अपने पर्यटन परियोजना विभाग को बंद करने का निर्णय लिया। उसके लिए कारण बताया गया कि प्रत्येक परियोजना में मानव श्रम की लागत (परियोजना वाले देशों एवं बैंक दोनों में ही) बहुत ज्यादा थी, जिससे पर्यटन परियोजनाओं में जटिलता और बहुक्षेत्रीय संपर्क उत्पन्न हो रहे थे (क्रिस्टी एवं क्रॉम्पटन, 2001)। जबकि अन्य विश्लेषकों का कहना है कि टीपीडी के बंद होने की मुख्य वजह बैंक के अंदर ही असंतोष पैदा हो रहा था। वह इसलिए कि बैंक सीमित विकास सहायता कोष को संपन्न एवं विलासिता वाले पर्यटन परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर रही थी जिससे यूरोपीय और अमेरिकी समाज के ऊंचे तबके को लाभ होना था। टीपीडी को बंद करने के संभावित कारण महत्वपूर्ण थे – एक ऐसी संस्था जिसे विकासशील देशों में निचले तबके के 40 प्रतिशत लोगों (निर्धनतम लोगों) की सहायता के लिए बनाया गया था, वह विकसित देशों के संपन्न पर्यटकों के लिए विलासिता वाले आवास के लिए वित्तपोषण कर रही थी। टीपीडी को बंद करने के लिए बोर्ड को दिए गए ज्ञापन में तीन प्रमुख कारण कारण गिनाए गए थे – ज्यादा मानव श्रम लागत एवं परियोजनाओं के समन्वय में परेशानी, अन्य जगहों पर लगाए गए संसाधनों को प्राथमिकता और पर्यटन के वित्तपोषण के लिए अन्य स्रोत मौजूद हैं।

लेकिन विश्लेषकों के अनुसार टीपीडी के बंद होने के अन्य महत्वपूर्ण कारण थे – दुनिया भर में पर्यटन गंतव्यों में नियोजित एवं अप्रबंधित पर्यटन के हानिकारक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य असरों के प्रमाण – उनमें से कई को तो बैंक ने मदद की थी (गुडविन, 2000)। सत्तर और अस्सी के दशक में विश्व पर्यटन का कैसे विकास हुआ, उसे इलियट एवं मान (2005) ने संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया है –

“चूंकि यात्रा सस्ती और ज्यादा लोगों के पहुंच में हो गई थी, तो विकासशील देशों ने तेजी से आगे बढ़ रहे बाजार आधारित विदेशी पर्यटन कंपनियों को प्रस्ताव दिया। सत्तर और अस्सी के दशक के दौरान विदेशियों के ज्यादा मालिकाना, पर्यटन के आय का काफी हिस्सा बाहर जाना एवं सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसान ने पर्यटन के “उत्तर-दक्षिण” सम्बन्ध के स्वरूप को प्रस्तुत किया। वास्तव में, यह संसाधन छिनने या शोषण मॉडल से कुछ भी अलग नहीं था।”

विश्व बैंक ने इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई। केन्या में 1976 और 1985 के बीच क्रियान्वित हुए वन्यजीव एवं पर्यटन परियोजना के बारे में विश्व बैंक की परियोजना पूर्णता रिपोर्ट का कथन है कि, हालांकि परियोजना ने विदेशी विनिमय आय में सुधार किया, एवं ‘वन्यजीव प्रदर्शन’ में योगदान दिया, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन, प्रबंधन और संरक्षण पर बहुत ही कम ध्यान दिया। इसका कहना है कि –

“हालांकि केन्या के विदेशी मुद्रा आय में पर्यटन के योगदान के महत्व को स्वीकार किया गया और पर्यटन विकास में वन्यजीव प्रदर्शन की भूमिका को मान्यता मिली, लेकिन वन्यजीव संसाधनों के बेहतर नियोजन और प्रबंधन को दिया जाने वाला ध्यान एवं इन संसाधनों के बेहतर संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय परियोजना समाप्त होने तक कम होता प्रतीत हुआ। इस तरह, केन्या की अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ और देश के वन्यजीव संसाधनों को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षण एवं प्रबंधन करने के उपाय को ध्यान में रखते हुए वन्यजीवों को खासकर प्राथमिकता देते हुए बाद की सहायता पर विचार किया जा सकता था।”⁵

इसका निष्कर्ष था कि परियोजना पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार की तरह स्थापित करने में सहयोगी था। लेकिन वन्यजीव एवं संरक्षित इलाकों के संसाधनों को परियोजना द्वारा नजरअंदाज किया गया एवं अनियंत्रित पर्यटन से होने वाले नुकसान से अलग ही संभावना दिखती है (हॉकिंस एवं मान, 2007)। इसी तरह बाली में, फ्रांसीसी सलाहकार कंपनी स्केटों द्वारा तैयार एवं बैंक द्वारा सहायतार्थ मास्टर प्लान अपने तयशुदा उद्देश्य पर्यटन विकास को नुसा दुआ क्षेत्र तक सीमित करने में असफल रहा। बाली में सत्तर के दशक में पर्यटन ज्यादा

⁴ “डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड टूरिज्म : पर्सपेक्टिव्स एंड इंप्लुएंस इन सब सहारान अफ्रीका”, शेरेल एम इलियट (जार्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी) एवं शाउन मान (विश्व बैंक के सामयिक पत्र श्रृंखला, जी डब्ल्यू सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के सलाहकार, <http://www.gwu.edu/~gwcsng>)

⁵ केन्या वन्यजीव एवं पर्यटन परियोजना (1976–84), परियोजना पूर्णता रिपोर्ट, अप्रैल 20, 1989, निष्कर्ष बिन्दु 8.2

और अनियंत्रित रूप से फैला, जिसके परिणामस्वरूप अल्पकाल⁶ (मर्डोक, वर्ष ज्ञात नहीं) में बहुत सारे विपरीत सामाजिक एवं पर्यावरणीय असरों का सामना करना पड़ा और इससे आर्थिक अंतर बढ़ रहा था अंततः इंडोनेशिया सरकार को 1991 में सभी होटल निर्माण रुकवाकर इस प्रक्रिया को रोकना पड़ा (थुलेन, 1996)।⁷ इक्सटापा – जिहुआतनेजो में बैंक की मैक्सिको पर्यटन परियोजना से मेजबान अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अनौपचारिक भूमिका को ध्यान में लेने में नियोजकों की असफलता को प्रकाश में लाया। मैक्सिको की पर्यटन योजना के प्रभाव से समाज के सबसे निचले तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई (नोरोन्हा, विश्व बैंक, 1979)। इसका अपरिहार्य प्रमाण यह रहा कि इसमें टीपीडी या उन संभावित विपरीत असरों को ध्यान में नहीं लिया गया जो कि पर्यटन परियोजनाओं के कारण हो सकते थे।

जब विश्व बैंक ने यूनेस्को की भागीदारी से 1976 में विकासशील देशों में पर्यटन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक असरों को आकलन करने के लिए एक सेमिनार आयोजित की तो वह अपने अनुभवों एवं आवश्यकताओं से सीखने के लिए थी। इमैनुएल डी कैट⁸ के निर्धारित काम “टूरिज्म – पासपोर्ट टू डेवलेपमेंट?” (1979) जो कि 1976 के सेमिनार से निकलकर आया, के प्रस्तावना में विश्व बैंक के एस. एम. टोलबर्ट लिखते हैं –

“हालांकि विकासशील देशों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन एक उपयुक्त गतिविधि है जो विवादास्पद रही..... ज्यादा विवाद खासकर पर्यटन के गैर आर्थिक लागतों में रही; दुर्भाग्यवश चर्चा सतही रही। जबकि हमारी संस्थाओं ने व्यक्तिगत पर्यटन क्रियाकलापों में सामाजिक-सांस्कृतिक असरों को ध्यान में रखने की कोशिश की, लेकिन हमने इस सवाल पर ज्यादा व्यवस्थित अवधारणा की जरूरत महसूस की।”

पर्यटन विश्लेषक डी कैट के काम पर चर्चा करने का विचार करते हैं क्योंकि यह पर्यटन के दो प्रमुख सैद्धान्तिक आधारों – ब्रिटन के “डिपेंडेंसी मॉडल” और बटलर के “लाइफसाइकिल मॉडल” पर टिका है। दोनों ने ही पर्यटन के सामाजिक व पर्यावरणीय असरों (ज्यादातर नकारात्मक) को उजागर किया है एवं कहा है कि पर्यटन पहले से ही स्पष्ट उत्तर-दक्षिण अलगाव को बढ़ा सकता है (एलियट एवं मान, 2005)। इस किताब में विश्व के सबसे ज्यादा चर्चित पर्यटन गंतव्यों (ट्यूनिशिया, मैक्सिको में इक्सटापा-जिहुआतनेजो, बेरमुडा, बाली, सीचेलिज, साइप्रस, माल्टा) के अनुभवों को, सरकारी अधिकारियों, यूएन संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शोधर्थियों के शोधपत्रों के माध्यम से एक साथ सामने रखा गया है। किताब की प्रस्तावना में, डी कैट ने विकासशील देशों के मामलों के अध्ययन में सामाने आए पर्यटन से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया है। इसके अलावा, उस समय “सोशल एंड कल्चरल डायमेंट्स ऑफ टूरिज्म” शीर्षक वाले एक व्यापक लेख में विश्व बैंक के टीपीडी में सलाहकार रहे रेयमंड नोरोन्हा ने एक व्यापक लेख में निष्कर्ष के तौर पर कहा है कि विश्व बैंक अपने पर्यटन क्रियाकलापों में सामाजिक लागत को ध्यान देने में धीमा रहा है (नोरोन्हा, 1979)। हालांकि लेख में कहा गया है कि इस कमी की वजह मौजूदा लेखनों में पर्यटन के व्यवस्थित सामाजिक विश्लेषण की कमी रही है; दूसरी तरफ इसने बैंक के पर्यटन के क्षेत्र में बैंक की एक दशक के क्रियाकलाप में निगरानी की कमी को उजागर किया है।

चाहे वह सेमिनार की वजह से हो या फिर आंतरिक दबाव की वजह से, लेकिन टीपीडी के बन्द होने से बैंक की पर्यटन गतिविधियों में ठहराव सा आ गया। हालांकि टीपीडी के बन्द होने के बाद भी, बैंक का पर्यटन में शामिल होना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। बोर्ड द्वारा स्व-सहयोग वाली परियोजनाओं को बंद करने के निर्णय के बावजूद, बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने बैंक को पर्यटन के लिए ढांचागत निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग एवं आईएफसी को होटलों के लिए वित्तपोषण की अनुमति दी। इसके बाद अस्सी के दशक में बैंक ने मौजूदा पर्यटन इलाकों को सहयोग करने या विस्तार करने के लिए यूगोस्लाविया में परिवहन परियोजना, मैक्सिको में पानी व सीवेज परियोजना, बाहमास में व्यावसायिक प्रशिक्षण को वित्तपोषण किया (क्रिस्टी एंड क्रॉम्पटन, 2001)। आगामी दशक में पर्यटन में बैंक की यही भूमिका जारी रही।

पर्यटन में विश्व बैंक की घटती भूमिका के साथ ही विश्व पर्यटन संगठन (ओएमटी) एवं पर्यटन पर सरकारों व नीति निर्माताओं के प्रमुख सलाहकार के रूप में यूएनडीपी जैसी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं का उदय हुआ।

⁶ <http://www.science.murdoch.edu.au/teach/n420/n420content/casestudies/bali/case01.htm#background>

⁷ थुलेन, स्टीफेनी ए – “बाली, टूरिज्म एंड इनवायर्मेंटल डिग्रेडेशन”, जून 1996, टीडी केस स्टडीज, खंड 5, संख्या 2 – <http://www.american.edu/TED/balitour.htm>

⁸ उस समय प्रोफेसर इमैनुएल डी कैट प्रस्तुत पेपर के आधार पर सेमिनार के लिए बैकग्राउंड पेपर तैयार करने के लिए एवं किताब संपादित करने के लिए विश्व बैंक व यूनेस्को द्वारा गठित समिति में ससेक्स विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज में थे।

जबकि ये संस्थाएं शुरुआती चरण में विकासशील देशों के ढांचागत निर्माण या बेहतर मानवश्रम आवश्यकताओं को वित्तपोषण के बजाय अध्ययन, तकनीकी सहायता एवं मास्टर प्लान को ही वित्तपोषित कर सकती थीं।

“टिकाऊ पर्यटन” की नई अवधारणा एवं “इकोटूरिज्म” का मंत्र

नब्बे के दशक में, वि व बैंक के साहित्यों एवं नीति में पर्यटन को फिर से महत्व मिला। “टिकाऊ विकास” के विचार के हिस्से के तौर पर, पर्यावरणीय व सामाजिक रूप से जिम्मेदार पर्यटन ने बैंक को नया रास्ता मुहैया कराया (हॉकिंस एंड मान, 2007)। रियो सम्मेलन (1992) में, पर्यटन के लिए नारा था – “..... सभी प्रमुख समूहों, आदिवासियों एवं स्थानीय समुदायों के सहयोग से उपयुक्त रणनीति विकसित करके गरीबी मिटाने के लिए पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करना” (घोषणा का एजेंडा 21)। पर्यटन की अपनी पुरानी समझ में प्रमुख बदलाव लाते हुए, बैंक अब पर्यटन को मेजबान देश में जैवविविधता संरक्षण, शहरी विकास, ढांचागत निर्माण, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, तटीय संरक्षण एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण के एक उपकरण के तौर पर देखने लगा है। यह नई सोच कई बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में फिर से उतरने के लिए आधार बन गया है (एलियट एंड मान, 2005)। सन 1991 में विकासशील देशों में पर्यावरण संरक्षण के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विश्व बैंक ने यूएनडीपी की भागीदारी से ग्लोबल इनवायरमेंटल फेसिलिटी (जीईएफ) की स्थापना की। जीईएफ की स्थापना ने पर्यटन आयामों के लिए नई परियोजनाओं की मेजबानी में शामिल करने के लिए दरवाजा खोला, जिसने आर्थिक लाभ को पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए वित्तपोषण को तर्कसंगत बनाने के लिए उपयोग किया।

विश्व बैंक के पर्यावरण विभाग द्वारा 1996 में प्रकाशित किए गए “इकोटूरिज्म एंड कंजरवेशन : ए रिव्यू ऑफ़ की इश्यूज” शीर्षक वाले उपयोगी लेख में वैश्विक संरक्षण प्रयासों को इकोटूरिज्म से जोड़ते हुए एक तर्क प्रस्तुत किया गया है। लेख में इकोटूरिज्म या प्रकृति आधारित पर्यटन से संरक्षण के पांच प्रमुख लाभ प्रस्तुत किए गए हैं:

- पार्को एवं संरक्षण के लिए वित्त का स्रोत प्रदान करना
- पार्क की सुरक्षा के लिए आर्थिक तर्क प्रदान करना
- संरक्षित इलाकों में स्थानीय लोगों को अतिक्रमण का आर्थिक विकल्प प्रदान करना
- संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जनमत तैयार करना
- निजी संरक्षण प्रयासों के लिए परिस्थिति तैयार करना

ये बिन्दु खासतौर पर ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि इस लेख के बाद वाले हिस्से में हम बैंक के संरक्षण प्रयास का विश्लेषण करते हैं। इसके अनुसार सिफारिश की गई है कि सरकार, निजी उद्योग, स्वैच्छिक संगठनों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों में इकोटूरिज्म को अवश्य शामिल करना चाहिए।

नब्बे के दशक में, जीईएफ के अंदर और बाहर बैंक की पर्यटन में अप्रत्यक्ष और अस्थायी उपस्थिति थी न कि अनुपस्थिति। कोट डीआइवरी, घाना, केन्या, सेनेगल, तंजानिया, यूगांडा, जिम्बावे और बुरुंडी फासो में संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बैंक की ज्यादा कृपा बनी रही। जीईएफ के बाहर 10 प्रतिशत सांस्कृतिक संरक्षण सहित मुख्यतः जैवविविधता संरक्षण पर केन्द्रित विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 34 देशों में कुल 44 परियोजनाएं थीं। इनमें खास बात यह थी कि इनमें कुछ परियोजनाएं उन्हीं परियोजना इलाकों में स्थित थीं जहां कि पहले बैंक ने 70 के दशक में टीपीडी द्वारा पर्यटन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया था। ये परियोजनाएं थीं :

- केन्या प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्डलाइफ सर्विसेज प्रोजेक्ट (1992) का उद्देश्य था देश में वन्यजीवों एवं राष्ट्रीय पार्को व रिजर्व की घटती संख्या को रोकना और केन्या में पर्यावरणीय टिकाऊ वन्य-जीव आधारित पर्यटन की ठोस नींव डालना।
- डोमिनिक रिपब्लिक वेस्टवाटर डिस्पोजल इन टूरिज्म सेंटर्स प्रोजेक्ट (2002) का उद्देश्य था तटीय शहरों में शोधित गंदे पानी का आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ निकास की व्यवस्था करना एवं चुने हुए पर्यटन इलाकों में जल आपूर्ति सेवाओं की व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करने का मॉडल तैयार करना। इसे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों – प्योरटो प्लाटा, सोसुआ एवं कैबेरेंट क्षेत्रों में जल आपूर्ति सेवाओं की व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को क्रियान्वयन के लिए तैयार करना भी था।

डोमिनिकन रिपब्लिक परियोजना सूचना दस्तावेज (पीआईडी पी059510, 2002) का कहना है कि –

“नौ अति महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में होटलों में कमरों की संख्या सन 2000 में 28,000 से बढ़ाकर करीब 43,000 और 2010 में बढ़ाकर 109,000 करने का आकलन किया गया। जबकि सीवेज और ठोस कचरे के निवारण के अपर्याप्त प्रबंधन की वजह से जल सीवेज सेवाओं की कमी एवं पर्यावरण प्रदूषण से पर्यटन उद्योग को धक्का लगा। कुछ मामलों में, गैर-उपचारित गंदा पानी नदियों व समुद्र तटों पर छोड़ा जाता है; अन्य मामलों में मौजूदा गंदा जल उपचार प्रणाली अपर्याप्त या असंचालित होते हैं, और सीवेज को समुद्र तट के पास छोड़ा जाता है या फिर होटल रिजॉर्ट इलाकों में पार्क व हरित इलाकों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उनकी गुणवत्ता उस लायक नहीं होती है।”

परियोजना प्योरटो प्लाटा, सोसुआ एवं कैबेरेट के 3 मुख्य पर्यटन केन्द्रों में पानी आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रस्ताव की ओर बढ़ गया है।

ये दो परियोजनाएं इन देशों में 70 के दशक में बैंक द्वारा व्यापक स्तर के पर्यटन कॉम्प्लेक्सों को वित्तपोषित करने से हुए नुकसानों को सुधारने के लिए बैंक द्वारा सुधार रणनीति अपनाने के प्रमाण हैं। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से कुछ परियोजनाएं पर्यटन से हुए असरों की गणना करती हैं। सन 1996 में हुए इकोटूरिज्म केस स्टडी की एक समीक्षा “इकोटूरिज्म एंड कंजरवेशन” ने मजबूती से इसे बढ़ावा देने की बात कही है, उसका कहना है कि –

“कई मामलों में, इकोटूरिज्म एवं प्रकृति आधारित पर्यटन संरक्षण के लिए राजस्व उगाहने या वैकल्पिक आमदनी के स्रोत तैयार करने की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं.....।”

बैंक द्वारा गठित एक अध्ययन (मार्कड्या, पेडरोसों एंड टेलर, 2003) का कहना है कि 1997 और 2002 के बीच समीक्षा की गई बैंक की 1500 परियोजनाओं में से 56 में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया और 32 में पर्यटन केन्द्रीय पहलू था। हालांकि, उन 32 में से सिर्फ 8 ने पर्यटन का वास्तविक लाभ दिया। सन 1992 से 2003 के बीच समीक्षा की गई 94 जीईएफ परियोजनाओं का कहना है कि इकोटूरिज्म राजस्व उगाहने एवं संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है लेकिन इनमें से केवल 8 में इकोटूरिज्म से होने वाले लाभ का संख्यात्मक विश्लेषण किया गया। अध्ययन का निष्कर्ष यह रहा कि बैंक के पर्यटन परियोजनाओं का बेहतर शोध करने की आवश्यकता है और उनके पर्यावरणीय व सामाजिक असरों को बहुत सावधानी से अध्ययन किया जाना चाहिए। जीईएफ के मामले में निष्कर्ष यह रहा कि हालांकि पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन राजस्व के अन्य स्रोत से अतिरिक्त आमदनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र से निर्धारित लक्ष्य अकसर अव्यवहार्य हो जाते हैं।

इस तरह पर्यटन गतिविधियों के दूसरे चरण में शामिल होते समय, हालांकि विश्व बैंक ने पर्यटन को नये दृष्टिकोण से परिभाषित किया, लेकिन गलतियां कायम रहीं। इकोटूरिज्म एक नया राग था जो कि 70 के दशक के पर्यटन मॉडल के बदले पेश किया गया। इससे उम्मीद की गई कि इस नये स्वरूप से न सिर्फ पिछले चरण के गंभीर सामाजिक-सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय असर कम होंगे, बल्कि इसके बदले इकोटूरिज्म वैश्विक जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में योगदान करेगा। लेकिन, दुर्भाग्यजनक परिणाम यह रहा कि इकोटूरिज्म ने भी व्यापक पैमाने पर समुदायों के विस्थापन में योगदान किया, जो कि वैश्विक संरक्षण प्रयासों की वजह से हुआ। संरक्षित इलाके (संरक्षित इलाके जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ रिजर्व) तैयार करने जैसी संरक्षण रणनीति व्यवस्थित रूप से उन समुदायों को दरकिनार कर रहे हैं जो कि पारंपरिक रूप से जंगलो के अंदर रहते रहे हैं लेकिन साथ-साथ उन्हें इकोटूरिज्म के लिए खोला जा रहा है! हालांकि संरक्षण या स्थानीय आर्थिक सशक्तीकरण के मामले में इकोटूरिज्म का योगदान अभी साबित होना बाकी है, लेकिन बैंक एजेंसियां टिकाऊ जैवविविधता संरक्षण एवं समुदायों के लिए वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में इसे एक व्यवहार्य विकल्प के तौर पर लगातार बढ़ावा दे रही हैं।⁹

बैंक का वर्तमान में पर्यटन में जुड़ाव

21वीं सदी के पहले दशक की शुरुआत में, बैंक की पर्यटन गतिविधियों में फिर से प्रवेश के बारे में लेखों व रिपोर्टों (अकादमिकों एवं विश्व बैंक सलाहकारों द्वारा) में व्यवस्थित तर्क उभरने शुरू हुए। सन 2001 में क्रिस्टी एवं क्रॉम्पटन ने एक व्यापक अध्ययन “टूरिज्म इन अफ्रीका” में विश्व बैंक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में गैर-भागीदारी की लागत की बात उठाते हुए कहा है कि बैंक विश्व की सबसे तेज बढ़ती आर्थिक गतिविधि के प्रति वर्तमान में बहुत

⁹ पढ़ें “अनलॉकिंग अपॉर्च्यूनितिज फॉर फारेस्ट डिपेंडेंट पिपुल इन इंडिया”, विश्व बैंक रिपोर्ट, 28 दिसंबर 2005, कृषि एवं ग्रामीण सेक्टर इकाई, दक्षिण एशिया क्षेत्र

कम ध्यान दे रहा है। अफ्रीका में बैंक द्वारा पर्यटन को अनियमित मदद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण लागत बताए गये :

- यदि बैंक सरकारों को सतत पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए सहायता नहीं देता है तो उन प्राकृतिक संसाधनों का जोखिम होगा जिन पर पर्यटन आधारित है।
- पर्यटन उद्योग बैंक द्वारा प्रस्तावित नये वित्तीय तरीकों का फायदा उठाने में असमर्थ रहे हैं।
- एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर बैंक की उपस्थिति न होने से, पर्यटन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के हितों से समझौता होता है।
- अनियंत्रित विकासकर्ताओं के दबाव से देश पर जोखिम बढ़ता है।

इस तरह यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में बैंक के फिर से प्रवेश के निम्न फायदे होंगे :

- पर्यटन विकास के बहुपक्षीय पहलुओं को हल करने के लिए बैंक का मौजूदा ढांचा ज्यादा अनुकूल है जो कि परियोजनाओं की सफलता और टिकाऊपन निर्धारित करेगा।
- पर्यटन एवं रोजगार की आर्थिक लागतों एवं लाभों पर सत्तर के दशक में शुरू हुए शोध कार्य को फिर से शुरू करना।
- सर्वोत्तम तरीकों पर जानकारी एकत्र व प्रसार करते हुए चाहे तटीय क्षेत्रों में हो या आंतरिक हिस्सों में हो यह सुनिश्चित करना कि पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है।
- पर्यटन के माध्यम से गरीबी निवारण एवं सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा का परीक्षण करना।
- और अंत में – “पर्यटन के लिए एक बार फिर बैंक के शामिल होने से क्षेत्रीय विकास बैंक व्यापक स्तर पर प्रवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे पर्यटन को टिकाऊ बनाने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए लाभों का बंटवारा समान हो इसके लिए और तेजी से अभियान फैलेगा।”

परिणामस्वरूप, आज बैंक, छोटे पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को वित्तपोषित करने के लिए फिर से प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में पर्यटन आधारित परियोजनाएं एजेंसियों के माध्यम से कुल 3.5 अरब डॉलर के करीब फैल चुकी हैं (हॉकिंस एवं मान, 2007)। हालांकि “पर्यटन” अब भी बैंक द्वारा कर्ज देने के विशिष्ट मुद्दों की सूची में नहीं हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप से पर्यटन, टिकाऊ विकास, कृषि व ग्रामीण विकास एवं परिवहन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में दिखती हैं। बैंक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में शामिल होने की सांकेतिक सूची सारिणी 3 में नीचे दिया गया है :

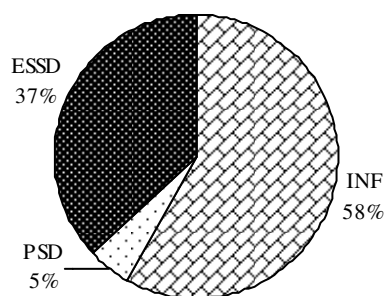
सारिणी 3 : पर्यटन वाले हिस्से सहित विश्व बैंक की मौजूदा परियोजनाएं (सन 2005 के अनुसार)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल मूल्य लाख अमेरिकी डॉलर में
पूर्वी एशिया एवं प्रशांत	11	10850
यूरोप एवं केन्द्रीय एशिया	13	2300
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश	30	5150
मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका	9	4950
दक्षिण एशिया क्षेत्र	2	190
उप सहारा अफ्रीका	29	6400
योग	94	29840
आईएफसी	70	5440
कुल योग	164	35280

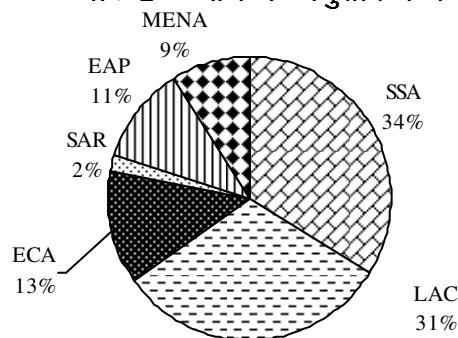
स्रोत : मान (2005)

बैंक के एक मौजूदा दस्तावेज का कहना है कि पर्यटन परियोजनाओं की इस सूची में वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित 17 परियोजनाओं सहित संख्या 94 से बढ़कर 114 हो गई है (विश्व बैंक नोट संख्या 16, 2006)। इनमें से केवल 3 ही वास्तव में “पर्यटन परियोजनाएं” हैं, जबकि बाकी सब पर्यटन आधारित विकास के परिणाम हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अंदर, पर्यटन के लिए कर्ज देने वाले तीन प्रमुख नेटवर्क हैं – इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क (आईएनएफ) (अब सरस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क), इएसएसडी (इनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका) एवं पीएसडी (निजी क्षेत्र विकास) इकाईयां। क्षेत्रीय स्तर पर, बैंक लगातार अफ्रीका पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और अफ्रीका बैंक के पर्यटन के वित्तपोषण का 34 प्रतिशत हासिल कर रही है। बैंक द्वारा पर्यटन के लिए प्रति इकाई कर्ज का विवरण चार्ट 1 में एवं क्षेत्र के अनुसार कर्ज का विवरण चार्ट 2 में दिया गया है।

चार्ट 1 – नेटवर्क के अनुसार कर्ज



चार्ट 2 – क्षेत्र के अनुसार कर्ज



आईएफसी एवं पर्यटन

आज तक आईएफसी ने दुनिया भर में मुख्यतः ठहरने की व्यवस्था, मनोरंजन पार्कों, यात्रा जहाजों, इकोटूरिज्म, प्रबंधन सेवाओं एवं कार्यालयों पर केन्द्रित करते हुए पर्यटन परियोजनाओं (आईएफसी, होटल्स एंड टूरिज्म ब्रोसर 2007) के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश किया है। पर्यटन के लिए मौजूद 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ इसके पास 70 सक्रिय परियोजनाओं के साथ-साथ बड़े सुनिश्चित निवेश एवं छोटे स्तर के आपूर्ति व्यवसायों के बीच कड़ी तैयार करने को सहयोग के लिए तकनीकी सहायता एवं सूक्ष्म-वित्तीय उपकरण हैं। पर्यटन में इसके अनुभव में रिजॉर्ट, शहरी एवं व्यावसायिक होटल, एवं मिश्रित इस्तेमाल वाले कारपोरेट निवेश शामिल हैं। आईएफसी के ग्राहकों में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशक एवं पर्यटन के मालिक-संचालक जैसे कि ओरिएंट एक्सप्रेस होटल्स, ऑस्ट्रेलियन लेइजर एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, हयात, मैरियट, ताज और कई सरकार संचालित होटल एवं निगम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आईएफसी का कहना है कि चूंकि वह पर्यावरणीय एवं सामाजिक रूप से टिकाऊ परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इकोटूरिज्म एवं सांस्कृतिक पर्यटन जैसी पर्यटन की नई अवधारणाओं के कारण पर्यटन धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है, एवं इसकी खासकर ऐसे निवेशों के प्रति रुचि है।

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाय तो विश्व बैंक के अनियमित जुड़ाव के मुकाबले आईएफसी का पर्यटन मेजबानी उद्योग के प्रति दीर्घकालीन एवं ज्यादा नियमित जुड़ाव रहा है। सन 1995 के आईएफसी के पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा का स्पष्ट कथन है कि – “जिन देशों में प्राकृतिक सुन्दरता के अलावा थोड़े संसाधन हैं उन देशों में हॉलिडे होटल के लिए निवेश... का एक महत्वपूर्ण विकास असर रहा है।” समीक्षा का यह भी कहना है कि विदेशी यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्यटन में आईएफसी का फोकस मुख्यतः रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्सों एवं व्यावसायिक होटलों के प्रति रहा है। समीक्षा का कहना है कि इसके फलस्वरूप – “होटल निवेशों में उत्प्रेरक एवं निवेश की भूमिका के लिए आईएफसी का स्वाभाविक तर्क है विकास प्रभाव, निवेश जोखिम एवं दीर्घकालीन वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के अभाव का संयोजन होना।” जहां विश्व बैंक के निवेश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में रहा है वहीं आईएफसी का सबसे बड़ा निवेश एशिया में रहा है। यहां तक कि 1995 में, पर्यटन में आईएफसी के अपने पोर्टफोलियो मूल्यांकन का कहना है कि पोर्टफोलियो में 50 प्रतिशत से ज्यादा होटल अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखला से संचालित होते थे। आईएफसी के पर्यटन पोर्टफोलियो के अन्य विशेषताएं रही हैं –

- रिजॉर्ट संपत्ति एवं व्यावसायिक होटलों के लिए निवेश।
- ज्यादातर होटल निवेश या तो स्थापित या फैल रहे गंतव्य में है।
- पोर्टफोलियो में ज्यादातर 4 सितारा होटल हैं जबकि एशिया में 5 सितारा होटल हैं।

आईएफसी के मौजूदा कुछ पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं¹⁰ :

- मालदीव एसएल : सांग्रीला एशिया लिमिटेड को सहयोग करना जिसके अंतर्गत मालदीव में सांग्रीला मालदीव रिजॉर्ट एंड स्पा नाम से 142 कमरों वाले 5 स्टार होटल की स्थापना करना। परियोजना विलिंगिली द्वीप में स्थित होगा जो कि हाल ही में सुधार किए गए गैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले द्वीप के बगल में है और हवाई जहाज से राजधानी शहर माले में मुख्य अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लगभग एक घंटे की दूरी पर है। यह परियोजना आईएफसी एवं मालदीव सरकार की संयुक्त उपक्रम है।

¹⁰ स्रोत : आईएफसी वेबसाइट – ठहरने एवं पर्यटन सेवाओं की परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेशों का सारांश

- **पेरु ओइएच-2** – एक मौजूदा आईएफसी ग्राहक पेरु ओरिएंट होटल्स (पीओइएच या कंपनी) ने पेरु में अपनी दो संपत्ति के नवीनीकरण के सहयोग के लिए आईएफसी से 130 लाख डॉलर का कर्ज देने का अनुरोध किया है। ये दो संपत्ति हैं कुस्को में नजारेनास कावेंट एवं कोल्का घाटी में एल पैराडोर डेल कोल्का लॉज। कंपनी वर्तमान में कुस्को शहर में 32 कमरो वाले माचु पीछु सेंचुरी लॉज, 123 कमरो वाले होटल मोंसाटेरियो एवं कोल्का घाटी में 7 कमरो वाले एल पैराडोर डेल काल्का लॉज संचालित करती है।
- **टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज (पाकिस्तान)** – टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज (पाकिस्तान) लिमिटेड (टीपीएसपी), आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट (एकेएफडी) की एक सहायक कंपनी है। टीपीएसपी “सेरेना” ब्रांड के अंतर्गत पूरे पाकिस्तान में 6 होटलों के नेटवर्क की मालिक हैं एवं उन्हें संचालित करती है। टीपीएसपी 750 लाख डॉलर की लागत से 213 कमरो वाले होटल का विकास कर रही है, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद सेरेना होटल का विस्तार है। इसके साथ ही वह किराए में देने योग्य लगभग 215,000 वर्ग फुट वाले कार्यालय भवन भी विकसित कर रही है।

यह स्पष्ट है कि आईएफसी की पर्यटन में भूमिका विकासशील देशों में संपत्ति नवीनीकरण या संपत्ति विकसित करने के लिए निजी होटलों को और खासकर अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखला को वित्तीय सहयोग प्रदान करने पर केन्द्रित है। छोटी और मध्यम कंपनियों या अन्य किस्म के उद्यमियों को वित्तपोषण करने में इसकी भूमिका नजर नहीं आती है।

एमआईजीए एवं पर्यटन

आईएफसी के साथ-साथ एमआईजीए ने भी पर्यटन एवं संबंधित निजी निवेश परियोजनाओं के प्रति निष्ठा कायम रखी है। बैंक के निवेश जोखिम गारंटीकर्ता होने के नाते, एमआईजीए गैर वाणिज्यिक पर्यटन एवं मेजबानी के जोखिमों को कम करने में मदद करके पूंजी की लागत कम करती है। अपनी स्थापना से अब तक एमआईजीए ने पर्यटन क्षेत्र में कुल 27.40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के 32 अनुबंधों को गारंटी जारी की है। वर्तमान में एमआईजीए का पर्यटन पोर्टफोलियो 13 करोड़ डॉलर है जो कि इसके कुल पोर्टफोलियो का 2.4 प्रतिशत है (एमआईजीए, 2006)। एमआईजीए के मौजूदा 14 सक्रिय परियोजनाओं में से 10 होटलों के निर्माण या नवीनीकरण से संबंधित है। आज तक एमआईजीए लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देश, केन्द्रीय एशिया, केन्द्रीय यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में पर्यटन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उपलब्ध कराने में सक्रिय रही है। एमआईजीए के उप कार्यकारी निदेशक मोतोमिची इकावा का कहना है कि, “पर्यटन को सहयोग करने में एमआईजीए की पहली भूमिका यह है कि विकासशील देशों में परियोजनाओं को गारंटी प्रदान करके निवेश की जोखिमों को कम करना एवं दूसरी यह कि देशों के पर्यटन के वातावरण में सुधार करना और वहां व्यवसाय के अवसर प्रदान करने में मदद करना है।”

जीईएफ एवं पर्यटन

सीबीडी के वित्तीय उपायों के कारण जीईएफ विकासशील देशों को उनकी जैवविविधता क्षति कम करने में मदद करती है (जीईएफ, ब्रोसर, 2007)। सन 1991 में अपनी स्थापना से आज तक जीईएफ ने भी उन परियोजनाओं को सहयोग किया है जिनमें पर्यटन के घटक होते हैं। जीईएफ का जैवविविधता पोर्टफोलियो उसके कुल अनुदान का 36 प्रतिशत है जो कि दुनिया भर में संरक्षित इलाकों के प्रबंधन व्यवस्था को सुधार करने पर केन्द्रित है और मात्स्यिकी, पर्यटन एवं कृषि जैसे उत्पादन क्षेत्रों में जैवविविधता शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। निम्नांकित सारिणी में 1992 से 2003 तक की अवधि में प्रमुख जीईएफ परियोजनाओं में मुद्दों के अनुसार पर्यटन के जुड़ाव को प्रदर्शित किया गया है कि परियोजना में पर्यटन का उल्लेख है, उन्हें उभारा गया है और/या उनकी गणना की गई है।

सारिणी 4 : पर्यटन के जीईएफ परियोजना का उल्लेख

पर्यटन का उल्लेख	उल्लेख नहीं	संक्षेप में उल्लेख	विशेष तौर पर	विशेष तौर एवं मात्रा सहित	जानकारी उपलब्ध नहीं	कुल
जैवविविधता	22	20	40	8	45	135
अंतरराष्ट्रीय जल	11	14	6	0	6	37
बहु केन्द्रित	8	4	2	0	7	21
कुल	41	38	48	8	58	193

स्रोत : विश्व बैंक जीईएफ डेटा बेस

निष्कर्ष एवं सवाल

सत्तर के दशक में ज्यादा सक्रियता के बाद, सन 2000 के बाद के चरण में शायद पर्यटन में विश्व बैंक के क्रियाकलाप में बहुत गहनता देखी जाती है। हालांकि पर्यटन का अब भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर चयन नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर में विश्व बैंक द्वारा पर्यटन के लिए कर्ज देना बढ़ रहा है। हाल के सालों में विकासशील देशों द्वारा बैंक के भीतर के विश्लेषकों के पर्यटन सहित्यों के साथ-साथ सहयोग एवं सलाह की मांग बढ़ी है (हचिंस एवं मान, 2007)। हालांकि पर्यटन में आईबीआरडी एवं जीईएफ का क्षेत्र जैवविविधता, सांस्कृतिक संरक्षण एवं परिवहन है, लेकिन आईएफसी एवं एमआईजीए का फोकस बड़े स्तर के, मोटे तौर पर विदेशी मालिकाना वाले पर्यटन परियोजनाओं और खासकर ठहरने की व्यवस्था स्थापित करने में है। बैंक की मौजूदा परियोजनाओं में से तीन (जॉर्डन कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म एंड अरबन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मोंटेग्रो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एवं मोजाम्बिक ट्रांस फ्रंटियर कंजरवेशन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) का फोकस सिर्फ पर्यटन पर है और सैकड़ों अन्य में पर्यटन के घटक शामिल हैं। लेकिन पर्यटन में बैंक के फिर से प्रवेश के संभावित असर क्या हैं? क्या बैंक को अपने पूर्व अनुभवों से सीख मिली है और क्या पर्यटन में संभावित विपरीत सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय असरों के लिए कोई ज्यादा जागरूक हस्तक्षेप है?

इस सवाल का जवाब पर्यटन में बैंक की विभिन्न चरणों में गतिविधियों के मूल्यांकन के माध्यम से दो भागों – वैचारिक स्तर पर एवं क्रियान्वयन के स्तर पर प्रस्तुत है।

पर्यटन पर बैंक की बदलती विचारधारा एवं सोच : टूटती कड़ी

अपने पहले चरण (1969–1979) की गतिविधि में, पर्यटन में बैंक समूह का जुड़ाव प्रारम्भिक तौर पर विकासशील देशों में विकसित देशों से पर्यटक आकर्षित करने के लिए पर्यटन अधोसंरचना बनाने की आवश्यकता पर निर्भर होता था। इन देशों में मुख्य ध्यान विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं मोटे तौर पर अधोसंरचना विकास के लिए पर्यटन की क्षमता पर था। घोषित ठहराव के बाद दूसरे चरण (अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध एवं नब्बे के दशक में) में यह विचारधारा बदल गई और इसका स्थान जैवविविधता संरक्षण के नाम पर इकोटूरिज्म एवं प्रकृति आधारित पर्यटन ने ले लिया। साथ ही मुख्य ध्यान संरक्षण एवं वैकल्पिक सामुदायिक आजीविका के लिए इकोटूरिज्म की संभावना पर था। मौजूदा चरण में (2000 के बाद), हालांकि इकोटूरिज्म कायम है, लेकिन पर्यटन से संबंधित प्रारम्भिक विचारधारा इसकी गरीबी निवारण की संभावना पर है। इस प्रक्रिया में गरीब अनुकूल पर्यटन एवं समुदाय आधारित पर्यटन उपकरण हैं।

विचारधारा के स्तर पर, पर्यटन पर विश्व बैंक समूह की नीति काफी बदल गई है। पूर्व के चरण में इसकी असफल परियोजनाओं और उनके विपरीत असरों की सीख के नतीजों की वजह से हो सकता है। हालांकि पर्यटन पर बैंक की नीति में दो प्रमुख कमियां कायम हैं, जो कि निम्नलिखित हैं :

- पर्यटन इलाकों में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देना। जबकि पहले चरण में यह पहलू पूरी तरह अनुपस्थित था, दूसरे चरण में संरक्षण के मामले में समुदायों के अधिकारों को कमजोर किया गया। मौजूदा चरण में, बैंक समूह द्वारा पर्यटन में समुदायों को शामिल करने की बात करने के बावजूद, अधिकार की भाषा अब भी अनुपस्थित है।
- पर्यटन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में नहीं के बराबर जिक्र किया गया है, जबकि बैंक के कुछ दस्तावेजों के अनुसार ये समुदायों के लिए पर्यटन से प्रत्यक्ष लाभ के आधार हैं।

दुनिया भर में पर्यटन विकास का दोषपूर्ण मॉडल प्रस्तुत करने में बैंक की भूमिका

यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इन चरणों में बैंक द्वारा पर्यटन के लिए निभाई गई भूमिका सिर्फ उसकी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं थीं। बैंक एजेंसियों की गहरी एवं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विकासशील देशों में क्रियान्वयन के लिए पर्यटन विकास के कुछ खास मॉडलों का विकास एवं प्रोत्साहन करना रहा है। पहले चरण में (70 के दशक में) यह मॉडल ज्यादातर पर्यटक आधारित, सहकारी व शोषणकारी था। पर्यटन विकास का असमान मॉडल बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में परिलक्षित होता था। इकोटूरिज्म के दूसरे चरण में (80 के दशक के अंत एवं 90 के दशक में), बैंक ने बहुत ज्यादा संरक्षित इलाके तैयार करने के लिए संरक्षण करने और तब उन इलाकों को इकोटूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देने का मॉडल अपनाया। मौजूदा चरण में, यह बहुत स्पष्ट है कि बैंक पर्यटन के लिए कौन सा प्रमुख मॉडल अपनाने जा रहा है। हालांकि इकोटूरिज्म

मॉडल को पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है, लेकिन गरीब अनुकूल विचारधारा अब तक मॉडल के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हुई है।

बैंक द्वारा पर्यटन के विकासशील मॉडल के लिए इन विभिन्न चरणों में निभाई गई भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्रमवार इस प्रकार हैं।

पहली यह कि, ये मॉडल बैंक या इसके सरकारों द्वारा पहले उनके संभावित असरों पर सोचकर संचालित किए जाते थे। पहले चरण में, बैंक ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित सहकारी मॉडल अपनाया, लेकिन बैंक ने पर्यटक आगमन वाले देशों में अर्थव्यवस्था, समाज एवं पर्यावरण पर ऐसे असमान मॉडल के असर का अनुमान किए बगैर ही ये मॉडल अपनाया। इसी तरह दूसरे चरण में, इकोटूरिज्म को आमतौर पर संरक्षण की आवश्यकता के लिए स्वीकार किया गया लेकिन उसकी वजह से उन जंगलों से विस्थापित होने वाले समुदायों को होने वाले नुकसानों का आकलन किए बगैर ऐसा किया गया।

दूसरी बात कि, इन मॉडलों में यह स्पष्ट नहीं था कि पर्यटन से गंतव्य स्थलों पर स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण और उनका विकास कैसे होगा। आज गरीब अनुकूल पर्यटन के माध्यम से बैंक गरीबी निवारण की उम्मीद करता है। लेकिन वास्तव में दुनिया में निर्धनतम लोगों के पास पर्यटन का लाभ कैसे पहुंचेगा यह नहीं बताया गया है। बैंक के व्यक्तिगत सदस्य देशों – खासकर अफ्रीका एवं मध्य पूर्व के पेपर्स (गरीबी निवारण रणनीति पत्र) में पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती है। लेकिन इस विषय पर बैंक के साहित्य को पढ़ने से अनुमानित पर्यटन रणनीति एवं गरीबी निवारण के बीच वास्तविक कड़ी नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी क्षेत्र में बैंक के निजी क्षेत्र की इकाई के एक नोट “टूर्वाईस ए स्ट्रेटेजी फॉर प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट” में मुख्यतः इथोपिया के पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों द्वारा सामना किए जाने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान दिया गया है एवं उनके लिए केन्द्रित उत्पाद विकास एवं ढांचागत सहयोग के माध्यम से हल प्रदान किया गया है। यह वास्तव में अश्चर्यजनक बात है कि बैंक पर्यटन का लाभ निजी क्षेत्र के विकास के माध्यम से समाज के निर्धनतम लोगों तक पहुंचाना चाहता है।

इस तरह विचारधारा एवं क्रियान्वयन दोनों के ही स्तर पर बैंक ने पर्यटन क्रियाकलाप में गंभीर गलतियां की हैं। जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि, पर्यटन में प्रत्यक्ष जुड़ाव से इनकार करने के बावजूद बैंक समूह का पर्यटन नीति एवं मॉडलों पर बहुत ज्यादा दबाव है। आज, बैंक पर्यटन में अपने जुड़ाव में तेजी लाना चाहता है तो, पर्यटन में उसके वित्तपोषण को मजबूत करने वाले सिद्धान्तों के परीक्षण की भी प्रबल आवश्यकता है।

क्या पर्यटन आधारित कार्य के पोर्टफोलियो में विस्तार के परिणामस्वरूप वास्तव में गरीबों को लाभ होगा, और क्या उन पर विचार हो सकता है?

यदि पर्यटन से लाभान्वित होने वाले स्थानीय समुदाय हैं तो, वास्तव में कितनी रकम की आमदनी होगी और वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

क्या ज्यादा पर्यटन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संरक्षित इलाकों के टिकाऊपन के लिए खतरा बनेगा या संभावित नकारात्मक असरों को कम करने के सरकारी प्रयासों से सुरक्षा मिल सकती है?

एक संस्था जिसने अतीत में पर्यटन के मामले में गलतियां की हैं, जिसकी कीमत समुदायों और पर्यावरण को चुकानी पड़ी है तो, पर्यटन में बैंक के मौजूदा हस्तक्षेपों की समीक्षा एवं मूल्यांकन की ज्यादा जरूरत है।

संदर्भ

1. “इकोटूरिज्म एंड कंजरवेशन : ए रिव्यू ऑफ़ की इश्यूज”, कटरीना ब्रांडों, एनवायर्मेंट डिपार्टमेंट पेपर्स, (पेपर संख्या 033), विश्व बैंक, अप्रैल 1996
2. “आईएफसी टूरिज्म सेक्टर रिव्यू”, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, फरवरी 1995
3. “सोशल एंड कल्चरल डाइमेंशन ऑफ़ टूरिज्म”, रेयमंड नोरोन्हा, वर्ल्ड बैंक स्टाफ वर्किंग पेपर संख्या 326 (एसडब्ल्यूपी 326), विश्व बैंक, अप्रैल 1969

4. "टूरिज्म इन आफ्रीका", इनान टी क्रिस्टी एवं डोरीन. इ क्रॉम्पटन, आफ्रीका रीजन वर्किंग पेपर सीरीज संख्या 12, विश्व बैंक, फरवरी 2001
5. "जीईएफ बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी इन एक्शन", ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जुलाई 2006
6. "एमआईजीए : सपोर्टिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इनवेस्टमेंट्स", एमआईजीए, जून 2006
7. "फाइनेसिंग टूरिज्म वर्ल्डवाइड", आईएफसी
8. "दि वर्ल्ड बैंक्स रोल इन टूरिज्म डेवलपमेंट", दिनाल्ड. ई हॉकिन्स एवं शॉउन मैन, ऐनल्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च, वॉल्यूम 34, संख्या 2, पेज 348–36, 2007
9. "टूरिज्म : एन अपॉर्च्युनिटी टू अनलीश शेयर्ड ग्रोथ इन आफ्रीका", नोट संख्या 16, अफ्रीका सेक्टर प्राइवेट डेवलपमेंट, विश्व बैंक, जुलाई 2006
10. "डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड टूरिज्म : पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लुएंसस इन सब-सहारा अफ्रीका", शेरिल एम एलियट एवं शॉउन मैन, ओकेजनल पेपर सीरीज, जॉर्ज वॉशिंगटन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन (जीडब्ल्यूसीएसजी), 2005
11. "टूरिज्म एंड सस्टेनबल डेवलपमेंट : लेसनस फ्रॉम रीसेंट वर्ल्ड बैंक एक्सपीरियेन्स", अनिल मार्कंड्या, टीम टेलर एंड सुजेट्टे पेड्रोसो, www.worldbank.org
12. "इथोपिया : टूवार्ड्स ए स्ट्रेटजी फॉर प्रो-पुवर टूरिज्म डेवलपमेंट", नोट संख्या 24, विश्व बैंक समूह, अफ्रीका क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर यूनिट, अगस्त 2006
13. "एनुअल रिपोर्ट 1966/67, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन" रिपोर्ट संख्या 21370
14. "प्रोटेक्टेड एरिया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी : लिंकिंग कंजरवेशन एंड सस्टेनबल डेवलपमेंट" मोहन मुनासिंघे एवं जेफ्री मैक्नीली द्वारा संपादित, वर्ल्ड बैंक एवं वर्ल्ड कंजरवेशन यूनियन, 1994
15. "डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन नॉर्थइस्ट इंडिया : दि नैचुरल रिसोर्सेज, वाटर एंड इनवायरमेंट नेक्सस", रिपोर्ट संख्या 36397-आईएन, विश्व बैंक, 28 मई 2007
16. "अनलॉकिंग अपॉर्च्युनिटिज फॉर फारेस्ट डिपेंडेंट पिपुल इन इंडिया", रिपोर्ट संख्या 34481-आईएन, विश्व बैंक 28 दिसंबर 2005
17. "टूरिज्म सेक्टर वर्किंग पेपर", विश्व बैंक, जून 1972

वेबसाइट :

www.worldbank.org/archives
www.ifc.org
www.miga.org

मीकांग पर्यटन - मॉडल या उपहास

‘टिकाऊ पर्यटन’ संबंधी एक केस स्टडी¹

अनीता प्लीमैरम, *पर्यटन जांच एवं निगरानी दल*, 2001

¹ थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क द्वारा प्रकाशित, इनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सीरीज संख्या 3, पेनाग, मलेशिया 2001

अपने अनोखे इतिहास एवं अत्यधिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों के साथ मीकांग नदी घाटी² ऐसा क्षेत्र है जिसमें पर्यटन विकास से जुड़े कई मुद्दों के साथ समस्याएं भी महसूस की जा सकती हैं। अस्सी के दशक तक थाइलैंड मीकांग क्षेत्र में अकेला देश था जो वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से पूरी तरह जुड़ गया था। उसने उपलब्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के बदले में विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ाने के अलावा निवेश और सम्मान अर्जित करने के लिए व्यवस्थित रूप से पर्यटन उद्योग का विकास किया। पिछले 20 साल में थाइलैंड आने वाले पर्यटकों की संख्या 10 लाख से बढ़कर करीब एक करोड़ सालाना तक हो गई है।

उपनिवेशवादी दौर की समाप्ति पर हुए उठापटक, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के उदय तथा हिंद-चीन में कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिकी कार्रवाई की वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अन्य मीकांग देश बाकी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कटे रहे। जहां बर्मा ने अपने स्वयंभू 'समाजवाद के बर्मी तरीके' का अनुसरण किया वहीं चीन और बाद में लाओस, कंबोडिया तथा विएतनाम समाजवादी खेमे का हिस्सा बन गए। इन देशों की यात्राएं करने पर प्रतिबंध था। पर्यटन से जुड़े आधारभूत ढांचे की स्थिति ठीक नहीं थी और वे उपनिवेश काल के ही थे।

अस्सी के दशक के आखिरी सालों में समाजवादी खेमा के ढह जाने के बाद सभी मीकांग देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाने और पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से वे जल्दी ही एशिया के नए औद्योगिकीकृत देशों (एनआईसीज) के समकक्ष आ जाएंगे। नब्बे के दशक की शुरुआत से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रवाद मीकांग घाटी क्षेत्र में कई सहयोग प्रारूप तैयार करने में अहम रहा। इन सब में पर्यटन तथा उससे जुड़े आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। इससे साफ होता है कि मीकांग क्षेत्र में पर्यटन का विकास संयोगवश या स्वाभाविक नहीं है बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और जोरदार प्रयासों का परिणाम है।

मीकांग घाटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है। क्षेत्र में विकासोन्मुखी आर्थिक विकास से संबंधित मौजूदा नीतियों को लेकर साफ मतभेद हैं। मुख्य सवाल यह है कि पर्यटन से होने वाले फायदे वास्तव में वंचित सामाजिक वर्गों तथा मूल निवासियों के जीवन स्तर के सुधार में योगदान दे सकता है या उनकी समस्याएं कम कर सकते हैं। वंचित वर्ग, धन का असमान वितरण, सामाजिक असमानता तथा प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से क्षय होने से मीकांग देशों में राजनीतिक, सामाजिक, जातीय और पारिस्थितिकी संबंधी संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन परिस्थितियों ने पर्यटन को अत्यधिक असुरक्षित उद्योग बना दिया।

थाइलैंड को अकसर नकारात्मक पर्यटन मॉडल कहा जाता है क्योंकि लापरवाह विकास से कई स्थानों पर पर्यावरण विनाश हुआ है। इससे आर्थिक असमानता बढ़ी और समाज में कई अवांछनीय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों में सेक्स उद्योग का प्रसार, एड्स, नशीली दवाइयों का उपयोग, जुएबाजी, अपराध एवं सांस्कृतिक ह्रास शामिल हैं।³ मीकांग पर्यटन विकास के योजनाकारों – अधिकारी एवं उद्योगपति – ने स्वीकार किया है कि उद्योग में कई समस्याएं भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी नीतियों एवं योजनाओं में 'सतत पर्यटन' की अवधारणा को शामिल किया। उनका मानना है कि बेहतर योजना एवं प्रबंधन से नए स्थानों में पुरानी गलतियों से बचा जा सकता है।

सवाल उठता है कि क्या पर्यटन विकास में नया युग शुरू हो गया है जिसमें नकारात्मक प्रवृत्ति में बदलाव आ सके तथा मीकांग पड़ोसी देश, उन अनुभवों से बच सकेंगे जो थाइलैंड में पर्यटन के कारण महसूस किए गए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम पहले क्षेत्रीय पर्यटन योजनाओं की पड़ताल करेंगे जिसमें एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू ग्रेटर मीकांग उपक्षेत्र (जीएमएस) योजना शामिल है। इसका अगला हिस्सा विभिन्न केस स्टडी पेश करेगा जिसमें कहा गया है कि विनाशकारी पर्यटन परियोजनाएं जारी हैं तथा इकोटूरिज्म या टिकाऊ पर्यटन की लगातार चर्चा के बावजूद मीकांग घाटी क्षेत्र में इसका प्रसार हो रहा है। आखिरी हिस्से में वैश्वीकरण का प्रभाव तथा एशियाई आर्थिक संकट से सीख जैसे व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निरंतरता के मुद्दे पर चर्चा है। इसमें दलील दी जाएगी कि अगर बेहतर भविष्य के लिए काम करने का लक्ष्य है तो अकसर गलत परिभाषित टिकाऊ पर्यटन नीतियों के स्थान पर कारगर एवं लोक केंद्रित विकास पहल करने की आवश्यकता है।

² मीकांग उपक्षेत्र में बर्मा, कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड, विएतनाम एवं दक्षिणी चीन का यूनान शामिल है।

³ थाइलैंड में पर्यटन के सामान्य असरों के लिए, उदाहरण के तौर पर देखें मीएर 1988; टीडीएससी 1991/91; टीआईआई 1994; कोहेन 1996; मीकांग उपक्षेत्र में पर्यटन, विकास एवं पर्यावरण पर द्विमासिक समाचार बुलेटिन न्यू फ्रंटियर्स के विभिन्न अंक।

पर्यटन एवं क्षेत्रीय विकास

पिछले दशक में चीन को छोड़कर सभी मीकांग देश दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एसोसिएशन (आसियान) के सदस्य हो गए हैं। इस समूह ने तथाकथित 'विकास त्रिकोण' के रूप में सीमाओं के पार आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तैयार किए हैं जिसमें पर्यटन विकास की अहम भूमिका है। आसियान का अपना ट्रवेल एसोसिएशन (आसियानटा) भी है। उसने आसियान-एशियाज परफेक्ट 10 पैराडाइज थीम के तहत 2002 को 'विजिट आसियान ईयर' घोषित किया⁴। आसियान ने 1996 में मीकांग नदी घाटी विकास निगम से संबंधित अपना एक कार्यदल भी स्थापित किया। इस पहल के तहत मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय माल ढुलाई तथा यात्री यातायात के लिए रेल नेटवर्क स्थापित करना है जो सिंगापुर को यूनान से वाया कुआलालंपुर, बैंकॉक, नोमपेन, हो ची मिन्ह सिटी तथा हनोई को जोड़ेगा⁵।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के तत्वाधान में मीकांग नदी आयोग (एमआरसी) ने मीकांग उपक्षेत्र के लिए योजनाएं पेश की हैं। इसमें पर्यावरण सुरक्षा तथा सांस्कृतिक संवर्धन के साथ आर्थिक विकास का प्रावधान किया गया है, जिसमें पर्यटन और संबंधित बुनियादी ढांचा विकास शामिल है।

एक अन्य पहल 'क्वाड्रैंगल फॉर इकोनोमिक कोआपरेशन' (क्यूईसी) है जो स्थल, जल और वायु यातायात में सुधार पर जोर देता है ताकि पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा मिल सके। थाई कारोबारियों के एक दल द्वारा 1993 में स्थापित क्यूईसी को थाइलैंड एवं चीन के प्रभावशाली राजनेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। क्यूईसी को बढ़ावा देने वाले निवेशक थाइलैंड, लाओस, बर्मा और यूनान के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन परियोजनाओं के विकास तथा सड़कों के निर्माण के लिए कोष जुटाने तथा रियायत प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक हैं। उनकी योजनाओं में साहसिक 'इकोटूरिस्ट' के मददेनजर आदर्श सांस्कृतिक गांव के अलावा होटल, रिजॉर्ट, कैसिनो, शॉपिंग सेंटर स्थापित करना शामिल है⁶।

बहरहाल, मीकांग टूरिज्म का प्रमुख ढांचा और मुख्य घटक एडीबी की जीएमएस योजना है।

जीएमएस पर्यटन कार्यक्रम

साल 1992 में स्थापना के बाद जीएमएस ने परिवहन, उर्जा, पर्यटन, दूरसंचार, पर्यावरण एवं मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 100 से अधिक योजनाओं की मदद की है। सात प्राथमिक परियोजनाएं सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़ी हैं, 34 परियोजनाएं सड़क, रेलवे, जल एवं वायु यातायात से संबंधित हैं वहीं 50 से अधिक परियोजनाएं पनबिजली उत्पादन से संबंधित हैं। जीएमएस पर्यटन कार्यसमूह सरकारों, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों, बड़े उद्योग एसोसिएशन तथा निगमों से समर्थन हासिल करने में सफल रहा है ताकि उपक्षेत्र को एकल पर्यटन बाजार के रूप में बढ़ावा दिया जा सके (एडीबी 1996, पीएटीए 2001)।

एडीबी के अलावा मीकांग के छह देशों के राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों (एनटीओएस) तथा कई अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन में वर्ल्ड टूरिज्म आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) पैसिफिक एशिया ट्रवेल एसोसिएशन (पीएटीए), आसियानटा, यूएन इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड दि पैसिफिक (ईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां शामिल हैं। थाइलैंड को अन्य मीकांग देशों के द्वार के रूप में प्रचारित करने वाले टूरिज्म अथॉरिटी आफ थाइलैंड (टीएटी) ने भी कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा की है। साल 1996 से बैंकाक में टीएटी के कार्यालय में जीएमएस पर्यटन कार्यदल का सचिवालय स्थित है जिसे एजेंसी फॉर कोआर्डिनेटिंग मीकांग टूरिज्म एक्टिविटीज (एमएटीए) के नाम से जाना जाता है⁷।

थाइलैंड ने ही पहले मीकांग टूरिज्म फोरम (एमटीएफ) की मेजबानी की। यह सालाना आयोजन है जिसे जीएमएस पर्यटन कार्यदल ने अप्रैल 1996 में पीएटीए के सालाना सम्मेलन के मौके पर पट्टाया में शुरू किया था।⁸

⁴ बैंकॉक पोस्ट, 'विजिट आसियान इयर टू बी ए ज्वाइंट एफोर्ट', 15.01.2001

⁵ न्यू फ्रंटियर्स, 'आसियांश मीकांग ग्रुप गेट्स ऑफ टू ए टेंटेटिव स्टार्ट', 2(6), जून 1996

⁶ दि नेशन, 'यूनान कांफ्रेंस : कोऑपरेटिंग ऑन ग्रोथ', 15.12.1995; न्यू फ्रंटियर्स, 'लिंगिंग लाओस टू दि वर्ल्ड', 1(6) अक्टूबर 1995; दि नेशन, 'फोर कंट्रीज इसक्वायर ऑफ ऑन दि बैंक्स ऑफ दि माइटी मीकांग', 27.05.1997; दि नेशन, 'बिजनेसमेन वांट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स', 28.07.1997

⁷ एएमटीए एक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित करती है और इसने हाल ही में जीएमएस टूरिज्म वेबसाइट www.visit-mekong.com जारी की है।

⁸ पीएटीए विश्व का सबसे मजबूत व्यवसाय समूह है जिसमें यूएस के निजी क्षेत्रों का बोलबाला है। इसने पिछले चार दशक में कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पर्यटन नीति में जबरदस्त हस्तक्षेप किया है। इसमें दुनिया भर के पर्यटन एवं ट्रवेल में लगे करीब 2000 संगठन शामिल हैं। इनमें 84 सरकारी प्रोत्साहन एजेंसियां हैं, 61 एयरलाइंस हैं, 600 बिजनेस होटल हैं, 400 पर्यटन ऑपरेटर

एमटीएफ 'मीकांग ड्रीम्स' को पूरा करने पर जोर देता है। मीकांग ड्रीम्स का विचार पीएटीए का है जिसमें मीकांग देशों के बीच बाधा रहित वायु एवं भूतल यात्रा का प्रावधान है क्योंकि पहुंच की कमी, सुरक्षा के अपर्याप्त प्रावधान और सख्त आप्रवासन कानूनों को उद्योग व क्षेत्रीय पर्यटन विकास में प्रमुख बाधा माना जाता है। (चांडलर 1995) इसके अतिरिक्त उपक्षेत्र के पर्यटन संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एमटीएफ 1996 में विश्वव्यापी अभियान शुरू किया था जिसमें 30 सांस्कृतिक और प्राथमिक पर्यटन स्थलों को "ज्वेल्स आफ मीकांग" बताया गया था।⁹

मीकांग नदी घाटी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों एवं विदेशियों को अब तक हतोत्साहित करने वाले भौतिक, आर्थिक, सांगठनिक तथा कानूनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए जीएमएस ने सतस विकास और इकोटूरिज्म पर महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में जोर दिया है। 'दि कंसेप्ट प्लान फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन दि ग्रेटर मीकांग सबरीजन 1999–2018' में जीएमएस की अगले 20 साल की रणनीति का जिक्र किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य मीकांग सांस्कृतिक पर्यटन, इकोटूरिज्म और साहसिक पर्यटन को 2006 के अंत तक गंतव्यों, सर्किट और मार्गों से जोड़कर एकजुट करना है। सन 2018 तक का अनुमान है कि जीएमएस क्षेत्र 'विश्व के प्रमुख इकोटूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों में से एक' होगा। मीकांग/लैंकांग नदी के किनारे के स्थान और लोगों की समृद्ध, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और विविध सांस्कृतिक धरोहरों का अनुभव करने के लिए 'सुरक्षित, सुगम' तथा 'अच्छे मूल्य' वाला गंतव्य होगा।¹⁰ (एमटीए 1998)

इकोटूरिज्म ने लघुस्तरीय एवं नियंत्रित विकास की अवधारणा को बढ़ावा दिया है, इसलिए इस योजना में मीकांग उपक्षेत्र की ओर लाखों अतिरिक्त विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने पर जोर दिया गया है।¹¹ इसके अलावा अध्ययन में प्रस्तावित वरीयता वाली परियोजनाओं की सूची एडीबी के जीएमएस बृहद आधारभूत ढांचा कार्यक्रम के अनुरूप है जिसमें नौकागम्यता, राजमार्ग निर्माण और वायुमार्ग के विस्तार सहित परिवहन व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है।¹²

अध्ययन के अनुसार "लंबे काल में नेटवर्क, गेटवे, परिवहन सुविधाओं के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं जुटाने पर जोर दिया जाएगा ताकि पूरे क्षेत्र में पर्यटन बाजार के सभी घटकों को शामिल किया जा सके" (एमटीए 1998)। दूसरे शब्दों में बृहदस्तरीय पर्यटन को बाधित करने वाले आधारभूत ढांचे की कमी रहेगी। इकोटूरिज्म तथा ग्राम पर्यटन जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर ध्यान रहेगा। एक बार जब द्वार खोल दिए जाएंगे तथा सभी आवश्यक सुविधाएं स्थापित हो जाएंगी तो सभी प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसका मतलब मुख्यधारा के मुख्य पर्यटन के विकास से हटना है।

इस बीच यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि बैंक की अधिकतर परियोजनाएं न सिर्फ अपने मानक को पूरा करने में विफल रही हैं बल्कि स्थानीय समुदाय और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार हैं।¹³

हैं, एवं 360 गंतव्य ऑपरटर व कॉरपोरेशन हैं। 1988 में, पीएटीए ने इस क्षेत्र में अपने हितों को मजबूत करने के लिए अपने मुख्यालय को सैनफ्रांसिस्को से बैंकॉक स्थानांतरित किया। ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट www.pata.org.

⁹ "ज्वेल्स ऑफ मीकांग" जिन स्थानों पर प्रोत्साहित किए जाते हैं वे हैं – बर्मा में : रंगून (श्वेडागोन पगोडा), क्याइखितियो (गोल्डन रॉक), मंडाले (मिगुन पगोडा), ताउंगीई (इनले लेक), पगान (आननंदा मंदिर); कंबोडिया में : अंकोरवाट, फूम पेन्ह एवं आस पास के इलाके, सिहानाउकविले, टोनले सैप लेक, रत्नाकिरी; चीन के यूनान प्रांत में : कनमिंग, स्टोन फारेस्ट, जिहुअंगबाना, दाली, लिजियांग; लाओस में : लुआंग प्रबंग, चंपासक, विएंतिन, जिएंग खोउंग (जार के मैदान), लैंक साओ; थाइलैंड में : ओल्ड रॉयल सिटी, रत्तनाकोसिन द्वीप-बैंकाक, बान चियांग, प्रसत हिन खाओ फानोम रुंग हिस्टोरिकल पार्क, उबोन रतथाथानी प्रांत, चियांग राई प्रांत; विएतनाम में : हलॉंग बे, हनोई सिटी, निन्ह बिन्ह प्रांत, थुआ थीन ह्वे क्वांगम-दनाग प्रांत (एडीबी 1996)

¹⁰ लैंकांग मीकांग नदी का चीनी नाम है।

¹¹ सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएमएस ने सन 2000 में 141 लाख पर्यटक हासिल किया, जिसमें थाइलैंड का सबसे बड़ा हिस्सा 67.76 प्रतिशत रहा; इसके बाद विएतनाम (15.14), यूनान (7.12), लाओस (5.22), कंबोडिया (3.3) एवं बर्मा (1.47) रहे (एमटीए न्यूजलेटर, 'विजिटर एराइवल्स टू जीएमएस रीच 14.1 मिलियन इन 2000' अप्रैल 2001)। विचार पेपर ने सन 2006 के अंत तक जीएमएस देशों में 20 से 25 लाख अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय पर्यटक लाने की योजना बनाई और आगामी वर्षों में ढांचागत परियोजनाएं पूरी हो जाने पर और भी ज्यादा विकास दर संभव है (एमटीए 1998)।

¹² यह भी देखें : एडीबी 1996 एवं दि नेशन, 'ट्रांसपोर्ट रूट्स होल्ड की टू मीकांग', 01.03.1996।

¹³ कुछ सीमा तक, एडीबी अपनी वित्तपोषित परियोजनाओं की असफलता स्वीकार करता है, यहां तक कि बैंक के आंतरिक मूल्यांकन अपने निष्कर्ष में रूढ़िवादी माने जाते हैं (टीइआरआरए 2000)। मनीला स्थित फिलीपींस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ के निदेशक वाल्डेन बेलो ने एडीबी की रणनीति एवं नीति दस्तावेज के मूल्यांकन का संदर्भ दिया है, जिसके अनुसार, "ज्यादातर मामलों में क्रियाकलापों का कार्यप्रदर्शन अनुमान से काफी कम था।" यह प्रोजेक्ट डिजाइन में कमी, खासकर वहां पर जहां कि संस्थागत क्षमता कमजोर थी और वहां पर नीतियां अपर्याप्त थीं। ज्यादातर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रवृत्ति संस्थागत विकास व सहयोगी सेवाएं एवं नीति सुधार के बजाय उनके भौतिक ढांचे के पूरा

उदाहरण के तौर पर एडीबी ने 1996 में वाटरशेड क्षेत्रों में संरक्षण प्रबंधन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उपक्षेत्र के करीब छह करोड़ पहाड़ी लोगों को धीरे-धीरे पुनर्वासित करने की बात है। इस विशाल पुनर्वास कार्यक्रम को इस दावे के साथ वैध ठहराया गया कि बड़े पैमाने पर झूम खेती से पर्यावरण के विनाश का खतरा है।¹⁴ इसके अलावा बैंक की 50 से अधिक बड़ी परियोजनाओं से अनगिनत लोगों के विस्थापित होने और उनकी पारंपरिक आजीविका के छिन जाने का खतरा है।

एडीबी की धारणा है कि विकास एवं गरीबी निवारण¹⁵ के नाम पर स्थानीय समुदायों को अपनी पारंपरिक आत्मनिर्भर जीवनशैली तथा आर्थिक गतिविधियों को छोड़ देनी चाहिए और उन्हें नए स्थानों पर आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इकोटूरिज्म की ओर मुड़ना चाहिए। जीएमएस आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की जनवरी 2000 में मनीला में संपन्न नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर एडीबी के पर्यावरण विभाग के प्रबंधक वारेन इवांस ने कहा कि, “हमें पहाड़ी समुदायों को यह समझाने की जरूरत है कि इकोटूरिज्म से उद्यमों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना उनके हित में है। वे शिकार और अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित कर सकते हैं और बेहतर पर्यटन सुविधाओं का परिचालन कर सकते हैं”¹⁶।

जीएमएस योजना की यह गंभीर विडंबना है कि ऐसा व्यापक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और देशी समाज तथा संस्कृति का अवश्यभावी विनाश होना है। इसके मुआवजा के तौर पर पर्यटन की पेशकश की जाने की बात है।¹⁷ इतना ही नहीं पर्यटन अध्ययन से खुलासा होता है कि पर्यटन के आमदनी का मामूली हिस्सा ही ग्रामीणों तक पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए वर्ल्डवाइल्ड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) का प्रतिनिधित्व कर रहे एक नेपाली मिंग्वा नोरबूशेरपा ने एडीबी के पहले गरीब समर्थक सेमिनार में दलील दी कि कई मामलों में पर्यटन का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता जहां पर्यटन का प्रभाव होता है। उन्होंने नेपाल के प्रसिद्ध ट्रेकिंग क्षेत्रों का जिक्र किया जहां पर्यटन आमदनी का दो प्रतिशत हिस्सा ही स्थानीय लोगों को मिल पाता है।¹⁸

होने पर केन्द्रित होते थे।” बेलो ने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कहा कि, “लगभग सभी वनीकरण परियोजनाएं असफल रहीं”, और कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में केवल 36 प्रतिशत एवं सामाजिक ढांचागत क्षेत्र में केवल 33 प्रतिशत परियोजनाओं को “आमतौर पर सफल” का दर्जा दिया गया (बेलो 2000)। एडीबी के 2001 के सलाना बैठक में, पश्चिमी डोनर देशों एवं शेरधारकों ने बैंक पर उसके विकास नीतियों को सुधारने, काम का दोहराव न करने और दुर्लभ संसाधनों को बरबाद न करने का दबाव बनाया (एफपी रिपोर्ट 12.05.2001)।

¹⁴ अगस्त 1996 में पर्यावरण पर जीएमएस वर्किंग समूह के एडीबी की दूसरी बैठक से संबंधित प्रेस सम्मेलन में, एडीबी के कार्यक्रम विभाग में तब के निदेशक नोरितादा मोरिता ने पुनर्वास योजना का बचाव करते हुए कहा कि, “हमें पहाड़ी इलाकों में लोगों की आबादी कम करने एवं उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने की जरूरत है। वे एक जगह बसाए जाएंगे।” (दि नेशन 04.08.1996)। पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किया कि गरीब समुदाय सतत विकास के प्रमुख बाधक हैं। मीकांग टूरिज्म के बारे में पीएटीए में छपे एक हाल के लेख में कहा गया है कि, “इन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कई हिस्सों में अति गरीबी के कारण, स्थानीय लोग न तो सतत विकास को समझते हैं और न ही उस पर ध्यान देते हैं। विकास प्रक्रियाओं में पीछे छोड़ दिए गए लोगों के जल्दी धनी बनाने के सुझाव से गंतव्य द्वारा अंतिम कीमत चुकाने की दीर्घकालीन अवधारणा के मुद्दे से टकराव हो सकता है।” (पीएटीए 2001)

¹⁵ आईसीटी के एवं विश्व बैंक के नीतियों के अनुसार सन 2015 तक विश्व में गरीबी आधा करने के लिए, हाल के सालों में एडीबी ने गरीबी निवारण को अपने प्रमुख लक्ष्य के तौर पर अधिसूचित किया। इस संबंध में मई 2001 में होनोलुलु में हुए सलाना बैठक में, इसने ‘एशिया प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन एवं गरीबी निवारण’ शीर्षक से पहली बार एक सेमिनार आयोजित किया। बैंक के कई अधिकारियों के कथन से स्पष्ट होता है कि एडीबी की ‘नई’ गरीब अनुकूल पर्यटन रणनीति वास्तव में पुरानी संशोधित विचारधारा पर आधारित है; यह इस अनुमान पर चलती है कि निजी क्षेत्र के निवेश से बढ़ने वाले पर्यटन से नौकरियों के अवसर एवं आर्थिक लाभों का बटवारा बढ़ेगा, एवं इस तरह इससे अंततः गरीबी निवारण एवं सतत विकास होगा। एडीबी के गरीब-अनुकूल पर्यटन सेमिनार पर ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट <http://www.adb.org>, न्यू फ्रंटियर्स, ‘एडीबी : टूरिज्म एज टूल इन वार अगेंस्ट पोवर्टी’, 7[2], मार्च-अप्रैल 2001; होनोलुलु एडवरटाइजर, ‘पुअर बेनिफिट लिटिल फ्रॉम टूरिज्म, समीक्षा सहित, 9.05.2001

¹⁶ देखें न्यू फ्रंटियर्स, ‘जीएमएस प्रोजेक्ट्स सेट टू रोल अगेन’, 6[1], जनवरी-फरवरी 2000

¹⁷ उदाहरण के लिए, कनाडा के संगठन प्रोब इंटरनेशनल के नीति निर्देशक ने दि नेशन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि, “एडीबी के लिए लोगों के विस्थापन का मतलब है गरीबी निवारण। एडीबी सबसे पहले लोगों को गरीब बताती है एवं उन्हें वाटरशेड एवं बांध निर्माण योजनाओं का बाधक बताती है, इसलिए उन्हें विस्थापित होना चाहिए; इसके बाद पर्यटन गाइड, वनरक्षक या पौधरोपण कर्मचारी के तौर पर नौकरिया उपलब्ध हो सकते हैं।” (देखें न्यू फ्रंटियर्स, “एडीबीज अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड ‘पोवर्टी रिडक्शन’, रेटरिक एक्सपोज्ड” 6[3], मई-जून 2000)।

¹⁸ देखें- होनोलुलु एडवरटाइजर, ‘पुअर बेनिफिट लिटिल फ्रॉम टूरिज्म, समीक्षा सहित, 9.05.2001। उत्तरी थाइलैंड में किए गए शोध में शेरपा के निष्कर्षों को सही ठहराया गया है। कनाडा के मानवशास्त्री जीन मीचाउद ने चियांग मेई गांव में हमांग समुदाय बैन सुआय में देखा कि, पर्यटन व्यवसाय में कदम रखने से कुछ ग्रामीण अपनी आमदनी एकाएक बढ़ा पाए। हालांकि, कुल मिलाकर देखा जाय तो केवल करीब 3 प्रतिशत पर्यटकों का धन गांवों में रहता है, बाकी शहरों के पर्यटन एजेंसियों एवं बाहर के

कंबोडिया में विकास सलाहकार शिव कुमार के अनुसार एडीबी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्राथमिक जोर कमजोर एवं गरीब तबकों के उत्थान के बदले निगमों के लिए मददगार माहौल बनाने पर है। “आमतौर पर एडीबी और जापान जैसे दाताओं द्वारा विकसित अधिकतर परियोजनाएं बड़ी पूंजी वाली हैं, जबकि इन देशों में गरीबी से मुकाबला करने के लिए श्रम प्रधान परियोजनाओं की आवश्यकता है, कम से कम लघु अवधि में। वे ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं कर सके जिसमें कल्याण के साथ आर्थिक वृद्धि, सशक्तीकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक परिवर्तन और अस्तित्व को एक साथ संतुलित एवं प्रभावी तरीके से शामिल किया जा सके। इन अनुभवों से यह नतीजा निकलता है कि गरीबी निवारण इन परियोजनाओं की प्राथमिकता में नहीं है...” (शिव कुमार 1997, 11)

निम्नलिखित उदाहरणों से साफ होगा कि पर्यटन गतिविधियों से पिछले दशक में किस प्रकार पूरे मीकांग क्षेत्र को नुकसान हुआ है और पर्यावरण तथा स्थानीय लोगों पर गंभीर दबाव बन गया है।

वास्तविक पर्यटन कहानियां

1. ‘व्यापक इकोटूरिज्म’ – थाई स्टाइल

थाइलैंड में 1970 और 1980 के दशक में पर्यटन का तेजी से विकास हुआ, खासकर सेक्स पर्यटन का। थाई समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव की वजह से इसकी तीखी आलोचना हुई।

“व्यापक पर्यटन का थाइलैंड में स्थानीय लोगों, उनकी संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर गंभीर असर हुआ है। अति उत्साही लाभोन्मुखी पर्यटन विकास प्रयासों के दो गंभीर परिणाम हुए हैं – (1) स्थानीय कृषि एवं लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों की कीमत पर पूंजी का पर्यटन से संबंधित निर्माण एवं रियल इस्टेट में भारी स्थानांतरण और (2) अधिक खपत को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव।” (फोलपोक 1997, 11)

थाइलैंड के पर्यटन उत्पादों को विविधता प्रदान करने तथा अपनी खराब हो चुकी छवि में सुधार के लिए सरकार एवं उद्योगों के प्रयासों के साथ इकोटूरिज्म में दिलचस्पी बढ़ी है।¹⁹ टीएटी के पूर्व गवर्नर सेरे वांगपाइचित्र ने जून 1998 में बैंकाक पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि “इकोटूरिज्म दीर्घावधिक पर्यटन विकास का केन्द्र है।” उन्होंने दलील दी कि टीएटी द्वारा व्यापक पर्यटन को बढ़ावा देना इकोटूरिज्म के अनुरूप नहीं है। “रणनीति यह है कि पर्यटन को अधिक स्थानों तक पहुंचाना है जिससे संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं हो और आर्थिक लाभ अधिक लोगों के बीच वितरित हो।”²⁰

दुर्भाग्य से थाइलैंड को वनों, समुद्र तटों, समुद्री क्षेत्रों तथा प्राकृतिक संपदा के कुप्रबंधन का अनुभव रहा है। कई होटलों, रिजॉर्ट तथा अन्य ऐसी इमारतों ने आधिकारिक संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया है।²¹ राष्ट्रीय उद्यानों

व्यवसायियों के पास जाता है, जैसे गाड़ियों के ड्राइवर या हाथियों के सवारी कराने वाले या बांस-राफ्टिंग कराने वालों के पास जाता है। मीचाउद ने यह भी पाया कि, “ज्यादातर ग्रामीणों के विचार से फिलहाल तो पर्यटन व्यवसाय अनुमान से कहीं ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा पर्यटकों के आने से एवं ज्यादा मांग दोनों से घरों में पारंपरिक हमोंग जीवन लुप्तप्राय हो रहे हैं.... जो ऐसी परिस्थिति का सामना कर ले जाते हैं सिर्फ उनका ही कुछ नुकसान नहीं होता है” (मिचाउद 1993)। इस लेखक द्वारा चियांग मेई के आदिम लोग दारा-अंग समुदाय के बीच एक अध्ययन में ऐसे ही नतीजे सामने आए हैं (प्लीमैरम 1997/98)।

¹⁹ थाइलैंड की सरकार अंतरराष्ट्रीय मीडिया के रिपोर्टों के प्रति संवेदनशील है कि थाइलैंड वेश्यावृत्ति, ड्रग एवं एड्स का केन्द्र है और अक्सर इन नकारात्मक बातों पर दलील देती है कि देश में नाइटलाइफ के अलावा भी दूसरे आकर्षण हैं। उदाहरण के तौर पर, बैंकॉक में ‘सोशल आर्डर’ कायम करने के सरकार के अभियान के संबंध में आंतरिक मंत्री पुराचाई प्लूमसोमबुन ने दावा किया कि विदेशी लोग थाइलैंड में इसलिए आते हैं क्योंकि वे यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहते हैं न कि वेश्यावृत्ति या ड्रग के लिए। बदनाम मनोरंजन स्थलों का समाप्त करने के थाइलैंड सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाते हुए, टाइम पत्रिका ने अपने एक लेख में अनुमान लगाया है कि बैंकॉक बहुत जल्द ही सेक्स पर्यटकों का स्वर्ग बन जाएगा। इसके जवाब में प्रधानमंत्री थैकसिन हैर्सली ने टाइम पत्रिका की आलोचना करते हुए लोगों से आग्रह किया कि जो लेख थाइलैंड के लिए “रचनात्मक” नहीं हैं उस पत्रिका को न पढ़ें। (दि नेशन, ‘पीएम लैशेज आउट एट टाइम’, 10.09.2001)।

²⁰ देखें बैंकॉक पोस्ट, ‘इन चार्ज ऑफ टैपिंग दि टूरिस्ट्स’, 29.06.1998।

²¹ ‘संरक्षित इलाकों की निगरानी करने वाला रॉयल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट (आरएफडी) थाई मीडिया, पर्यावरणीय संगठनों एवं अकादमिकों द्वारा इकोसिस्टम एवं प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधन न कर पाने के कारण नियमित निशाने पर रहा है; उदाहरण के लिए नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दि पुअर इन थाइलैंड’ (संख्या 24, 1994) पर थाई डेवलपमेंट न्यूजलेटर का विशेष अंक देखें; वाटरशेड 1[2] 1995/96 एवं हिर्स 1998। आरएफडी के राष्ट्रीय पार्क विभाग के पियाथिप पिपिथ्वानिचदैम के अनुसार, पार्क में प्रमुख रूप से समस्याएं हैं : अस्पष्ट सीमाएं, प्रबंधन योजनाओं एवं दिशानिर्देशों का अभाव, अपर्याप्त कर्मचारी, शोध एवं

को निजी पर्यटन कारोबार के लिए खोलने के टूरिज्म अथॉरिटी आफ थाइलैंड (टीएटी) और रॉयल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रयासों ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। 1997 से आरएफडी ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसमें रिजॉर्ट द्वीपों पर अवैध पर्यटन सुविधाओं के संचालकों को लीज देने की बात की गई है— यह अति विवादित योजना है जिसके निकट भविष्य में सरकार से अनुमति मिल जाने की संभावना है।²²

कई पर्यवेक्षक 1999 में दक्षिणी थाइलैंड में फी फी द्वीपसमूह राष्ट्रीय उद्यान में 20 वीं सदी की फिल्म 'दि बीच' की शूटिंग का स्थानीय नागरिकों और पर्यावरणविदों द्वारा जोरदार विरोध किए जाने से चकित थे। लियोनार्डो डि कैपेरियो अभिनीत इस फिल्म में माया बे में भौगोलिक परिवर्तन को शामिल किया गया था। लेकिन विरोध और इस संबंध में सरकारी एजेंसियों तथा लोगों द्वारा फिल्म कंपनी तथा अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमे को थाइलैंड के राष्ट्रीय पार्क कानूनों की रक्षा एवं उन्हें लागू कराने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस मामले में अधिकारियों ने पार्क के एक हिस्से के 'डिजाइन में परिवर्तन' करने की अनुमति दी थी। विरोधी बार-बार 'दि बीच' मुद्दे को उठाते रहे हैं कि वह अभूतपूर्व मामला है। इस माया बे को बचाने का संघर्ष सिर्फ एक द्वीप का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के सभी उद्योगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हालीवुड की फिल्म के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार अभियान भी चलाया गया था। थाई अधिकारियों ने विवादित फिल्म परियोजना को अनुमति देने का कारण बताया कि यह देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों की आय के लिए था। लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं संरक्षण प्रयासों और कानून प्रणाली का मजाक है। इससे गलत उदाहरण सामने आता है कि थाइलैंड में व्यवसायवाद अन्य मुद्दे को पीछे छोड़ सकता है।²³

स्थिति निश्चित रूप से खराब है। इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर आरएफडी ने हाल ही में विशाल पर्यटन आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश भर के उद्यानों में कार्यान्वयन कराया है जिसके लिए विश्व बैंक तथा जापान ने कर्ज दिए हैं। आरएफडी के विजिट नेशनल पार्क ईयर 2000 के साथ ही सड़कों, पार्किंग, विजिट सेंटर, बंगला आदि का निर्माण किया गया। इनका उद्देश्य उस साल दो करोड़ से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना था।²⁴

थाइलैंड में प्राकृतिक अभयारण्यों के इकोटूरिज्म विकास में नजदीकी स्थानीय समुदायों को नीति निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर किसका स्वामित्व है, भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जाना है, कहां और कैसे पर्यटन सुविधाएं तैयार की जाएंगी — इन सब पर भी पर्याप्त चर्चा नहीं की जाती है। इन सब से पारिस्थितिकी समस्याएं पैदा हुई या गंभीर हुई हैं। सरकार निजी उद्योग एवं समुदायों के बीच संघर्ष तेज हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले आरएफडी ने उत्तरी थाइलैंड में राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रस्ताव किया, करीब दस हजार लोगों — जो जातीय अल्पसंख्यक समूहों के थे — ने अपनी भूमि से हटने की आरएफडी की योजनाओं को खारिज कर दिया और चियांग माई की सड़कों पर प्रदर्शन किया। (प्लीमैरम 1997/98)

शिक्षा के लिए संसाधनों का अभाव और बहुत सारी विकास परियोजनाओं का होना। वे जोर देती हैं कि, "हालांकि बजट व्यवस्था पार्क के अन्दर शैक्षिक कार्यक्रमों के शोध के लिए बहुत कम धन आबंटित करती है और सलाना बजट का ज्यादातर हिस्सा भवनों के निर्माण, सड़कों को पक्का करने, वाहन खरीदने, कर्मचारियों के व्यय एवं प्रशासनिक मदों में खर्च होता है।" जंगलों में अतिक्रमण और पार्क अधिकारियों व स्थानीय निवासियों के बीच विवाद के बारे में उनका कहना है कि रिजॉर्ट एवं गोल्फ कसोर्टियम बनाने वाले भ्रष्ट डेवलपर्स एवं वोट के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा परेशानी पैदा की जाती है।... राजनीतिज्ञों एवं स्थानीय अथॉरिटी द्वारा कोई सहयोग न होने के कारण इन समस्याओं ने आरएफडी के प्रयासों को बाधित किया है (पिपिथ्वानिचदैम 1997)।

²² न्यू फ्रंटियर्स, 'फाइट अगेस्ट पार्क इनक्रोचर्स एपियर्स लॉस्ट', 6[4], जुलाई-अगस्त 2000।

²³ कृषि एवं सहकारिता मंत्री को 12 जनवरी 1999 को दिए एक याचिका में कानून के 41 थाई प्रोफेसरों ने कहा है कि : "कानून के प्रोफेसर होने के नाते, कृषि मंत्री (जो कि राष्ट्रीय पार्क अधिनियम के अनुसार पार्क के रक्षक हैं) से आग्रह करते हैं कि, दि बीच इनसाइड नोपैरेट — फी फी थाइलैंड नेशनल पार्क नाम से फिल्म बनाने की अनुमति को जल्द से जल्द वापस लें, ताकि यह मामला एक मानक बने और अन्य राष्ट्रीय पार्कों में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाया जा सके कि थाइलैंड नैतिकता के आगे धन को महत्व नहीं देता है; यह कि किसी बाहरी देश या कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि वे थाई राष्ट्रीय पार्कों, थाई नैतिकता और थाई कानून को खरीद सकें। 'दि बीच मामले' पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यू फ्रंटियर्स के विभिन्न अंकों (1999-2000) एवं जस्टिस फॉर माया बे इंटरनेशनल एलाएंस (जुम्बिया) के वेबसाइट <http://www.uq.edu.au/~pgrredde> को देखें।

²⁴ एशियन वाल स्ट्रीट जर्नल, 'इकोटूरिज्म बुलडोजेस अहेड', 30.06.2000; दि नेशन, 'नेशनल पार्क्स थ्रीटेंड बाई टूरिस्ट टाइड', 14.05.2000, टिम-टीम 2000।

पर्यटन सह संरक्षण परियोजनाओं में स्वाभाविक सामाजिक अन्याय जगजाहिर है क्योंकि इससे एक सामाजिक वर्ग, जो उन क्षेत्रों में सालों से रहता आ रहा है, का भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच नहीं रह गई और दूसरे वर्ग निवेशकों तथा भुगतान करने वाले इकोटूरिस्टों के लिए वह क्षेत्र खोल दिया गया।²⁵

जब भी थाई अर्थव्यवस्था मुश्किल में होती है, सरकार निजात पाने के लिए पर्यटन का सहारा लेती है। 1980 के दशक में जब खेती और उद्योग मंदी से गुजर रहे थे, उसने सेवाओं को रोक दिया और 1987 को 'विजिट थाइलैंड ईयर' घोषित किया। 1997 की वित्तीय मंदी के बाद तत्कालीन चुआन लीकपाई सरकार ने 'अमेजिंग थाइलैंड' प्रोत्साहन अभियान शुरू की। नयी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे थकसिन शिनावतरा की सरकार ने 2001 में पर्यटन से पांच अरब भात (यानी 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर) की विदेशी मुद्रा हासिल करने की ठानी।²⁶ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को अतिरिक्त 19 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की जरूरत थी। योजना के तहत कई हजार अविकसित गांवों को समुदाय आधारित इकोटूरिज्म परियोजनाओं के लिए चुना गया। इस बीच पर्यटकों की बढ़ती संख्या और पर्यटन के विस्तार का मुकाबला करने के लिए बेहतर संरक्षण नीति का अभाव रहा।²⁷ इससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि देश के प्राकृतिक संसाधन का अल्पावधिक लाभ के लिए आगे भी दोहन होता रहेगा।

2. गोल्फरों का स्वप्न – किसानों की मुसीबत

गोल्फ को 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही आकर्षक पर्यटन व्यवसाय के रूप में जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। थाइलैंड से शुरू गोल्फ कोर्स का दौरा मीकांग के अन्य देशों में भी पहुंच गया है। इससे पर्यावरण एवं सामाजिक संघर्ष में काफी वृद्धि हुई है।²⁸

थाइलैंड में 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में गोल्फ कोर्स बनाए गए। गोल्फ कॉम्प्लेक्सों के निर्माण की पर्यावरण कारणों से काफी आलोचना हुई। ऐसे कॉम्प्लेक्सों में होटल, रिहायशी मकान, शापिंग सेंटर, मनोरंजन केंद्र, बिजली संयंत्र, संपर्क सड़क और यहां तक कि हवाई अड्डे भी होते हैं। कई परियोजनाओं पर उद्यानों की भूमि का अतिक्रमाण करने तथा किसानों को उनकी भूमि से हटाने का आरोप लगा। (प्लीमैरम 1994)

गोल्फ कोर्स के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इससे जैवविविधता वाले क्षेत्र एवं उर्वरा भूमि प्रभावित होती है। इसके अलावा ऐसी परियोजनाओं में पानी की काफी खपत होती है। बैंकाक के महीदोल विश्वविद्यालय के अनुसार 18 होल के अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स के टर्फ के लिए प्रतिदिन 650 घनमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इतने जल से शहर में छह हजार निवासियों की घरेलू जरूरतों या 60 हजार ग्रामीणों की आवश्यकता पूरी हो सकती है।²⁹ जलाशयों के पानी का इस्तेमाल कोर्स को हरा-भरा रखने में किया जाता है। वहीं पास के समुदायों को पेयजल तथा सिंचाई की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रजाति के घासों के लिए एवं कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से वायु, मिट्टी एवं जल के प्रदूषित होने की आशंका पैदा हो जाती है। जिससे वन्यजीव तथा मानव स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो जाता है। इस संबंध में चौंकाने वाली खबरों थाई मीडिया में आई थी। इसमें कोर्स की देखभाल करने वाले लोगों में सरदर्द, मिचली, सांस संबंधी परेशानी, चर्म रोग जैसी रासायनिक विषाक्तता से प्रभावित होने का जिक्र है।³⁰

²⁵ यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (यूएनआरआईएसडी) के कृष्ण घिमिरे का मानना है कि थाइलैंड में ज्यादातर सरकारी पर्यटन व संरक्षण प्रयास मुख्यतः स्थानीय लोगों को संरक्षित इलाकों से खदेड़ने पर केन्द्रित दिखता है। संरक्षित इलाके तैयार करने एवं उनके प्रबंधन में कई स्थानों पर लम्बा असंतोष पैदा हुआ है, जबकि बाहरी राजनैतिक सहयोग न होने के कारण कई विरोध कम समय के लिए एवं अनियमित रहे।... इसके परिणामस्वरूप आज थाइलैंड में बहुत सारे कमजोर सामाजिक समूह खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और बैंकॉक में आरएफडी और अफसरशही के दया पर निर्भर हैं।" (घिमिरे 1991)।

²⁶ बैंकॉक पोस्ट, 'अर्निंग टारगेट अप बीटी 50 बिलियन', 22.04.2001।

²⁷ दि नेशन, 'ए क्वीक फिक्स इज नॉट दि एंशर', 24.04.2001; दि नेशन, टूरिज्म प्लान इग्नोर्स थ्रीट्स टू दि इनवायमेंट', 25.05.2001।

²⁸ नब्बे के दशक के शुरुआत में थाइलैंड एवं अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अभूतपूर्व गोल्फ उभार के कारण, गोल्फ कोर्सों के पर्यावरणीय एवं समाजिक असर वैज्ञानिक अध्ययनों, एनजीओ प्रकाशनों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के मुख्य मुद्दे बन गए। उदाहरण के लिए देखें एमओएसटीई 1993; दि इकोनॉमिस्ट, गोल्फोनोंमिक्स : एशिया इन दि रफ', 20.12.1997–02.01.1998।

²⁹ देखें – एशिया मैगजीन, 15–17.04.1994।

³⁰ दि नेशन, 'दि हजार्ड्स ऑफ गोल्फ कोर्स केमिकल्स', 25.2.1995।

दक्षिणी लाओ प्रांत चंपासक में निवेशकों ने मीकांग नदी के प्रसिद्ध ली पी जलप्रपात क्षेत्र में एक मेगा रिजॉर्ट परियोजना की योजना बनाई थी।³¹ इसमें गोल्फ कोर्स, होटलों, कैसिनो, एक बिजलीघर और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल था। डेवलपर्स ने रिजॉर्ट को इकोटूरिज्म उद्यम के रूप में प्रोत्साहित किया था लेकिन लाओ और थाई पर्यावरणविदों तथा स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इससे वन कटाई, नाजुक मीकांग नदी तंत्र की पारिस्थितिकी में अंतर, ग्रामीणों का विस्थापन और नजदीकी समुदायों में अवांछनीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव भी संभव था। बहरहाल, बढ़ते जनविरोध तथा वित्तीय समस्याओं के कारण विवादित परियोजना रोक देनी पड़ी।³²

वियतनाम में भी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई गोल्फ कोर्स बनाए गए। नागरिकों ने इसका उस समय विरोध किया जब डेवलपर्स ने गोल्फ विएतनाम क्लब बनाने के लिए हो ची मिन्ह सिटी के पास थू दक में सार्वजनिक वनों को नुकसान पहुंचाया।³³ किंग्स आईलैंड गोल्फ रिजॉर्ट के थाई डेवलपर्स ने हनोई के पास दोंग मों बांध जलाशय के पास एक गोल्फ कोर्स बनवाया। इसे बनाने में पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने की स्थिति पर विचार नहीं किया गया। वर्ष 1994 में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान प्रांतीय अधिकारियों ने गोल्फ रिजॉर्ट को बचाने के लिए जलाशय से भारी मात्रा में पानी छोड़ने की इजाजत दे दी। इससे पास के क्षेत्रों में धान की फसल नष्ट हो गई।³⁴ 1995 में सरकार ने एक आदेश में धान के और खेतों को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर रोक लगा दी। लेकिन दक्षिण कोरियाई कंपनी देवू ने हनोई के पास किम नो गांव में धान खेतों में गोल्फ कोर्स बनाने के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया।³⁵ इस संबंध में किसानों को उचित जानकारी भी नहीं दी गई। परियोजना के विरोध में निर्माण स्थल पर उस समय हिंसा हुई जब नाराज किसानों ने सेना की एक इकाई को गोल्फ कोर्स में निर्माण करने से रोका।³⁶

कंबोडिया में नाम पेन्ह में अंकोरवाट मंदिर परिसर के पास कई गोल्फ कोर्स परियोजनाएं सामने आईं। इसके अलावा सिंहानौक विले में मलेशिया की एक कंपनी ने विशाल कैसिनो रिजॉर्ट का प्रस्ताव किया था।³⁷ नोम पेन्ह के नजदीक बांग ता यब झील के समीप सिंगापुर वित्तपोषित कंबोडियाई कंट्री क्लब के निर्माण के लिए डेवलपर बड़े पैमाने पर भूमि तथा झील के पास के 450 परिवारों को हटाना चाहते थे जो सब्जी तथा फल उत्पादक थे। लेकिन ग्रामीणों ने हटने से इनकार कर दिया और अधिकारियों का विरोध किया। अधिकारियों की नजर में वे अतिक्रमणकारी थे और उन्होंने मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया।³⁸

सैन्य शासित बर्मा में भी पर्यटन केंद्रों पर गोल्फ कोर्स बन गए हैं। इनमें दक्षिण में थाथाय क्यून द्वीप में अंडमान क्लब और गोल्डन ट्राइएंगल में ताचीलेक के पास गोल्डन पैराडाइज रिजॉर्ट जैसे गोल्फ सह कैसिनो रिजॉर्ट शामिल हैं।³⁹ रंगून में म्यामांर गोल्फ क्लब तैयार करने के लिए सेना ने वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए कई उपाय किए। लेकिन जब वे नाकाम रहे तो सरकार ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परिवार के बाकी सदस्यों को अपनी इच्छा के खिलाफ नगर के बाहर 'नई बस्ती' जाना पड़ा।⁴⁰

3. बिकाऊ सांस्कृतिक विरासत – अंकोरवाट का मामला

सांस्कृतिक धरोहर बिक्री के लिए उपलब्ध, पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनके मनोरंजन के लिए संस्कृति – जैसा ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में कहा गया है, रीति रिवाजों, त्योहारों, कला एवं शिल्प के साथ छेड़छाड़ किया गया है ताकि उसे पर्यटक उत्पाद के रूप में पेश किया जा सके। कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक तथा

³¹ फार इस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, 'आल दिस योर्स : थाई डेवलपर्स प्लांस कंट्रोवर्सियल रिजॉर्ट इन लाओस', 16.06.1994; दि नेशन, 'लाओ रिजॉर्ट पुट टू दि ग्रीन टेस्ट', 03.02.1995; बैंकॉक पोस्ट, 'वर्क टू स्टार्ट दिस मंथ ऑन 140 मिलियन डॉलर थाई लाओ रिजॉर्ट', 04.04.1995।

³² दि नेशन, 'वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कास्ट शैडो ओवर रिजॉर्ट प्लांड फॉर लाओस', 21.07.1995।

³³ मैनेजर मैग्जीन, 'एटीन होल्स एंड पब्लिक प्रोटेस्ट', अक्टूबर 1994।

³⁴ दि नेशन, 'वीएन डैबेल्स विद ए ह्यूज वाटर हजार्ड', 10.2.1995।

³⁵ बैंकॉक पोस्ट, 'दाएहा गोल्फ कोर्स एक्जैम्प्ट फ्रॉम डिफ्री ऑफ राइस फील्ड्स', 09.05.1995।

³⁶ न्यू फ्रंटियर्स, 'न्यू क्लेशेश ओवर देवू गोल्फ कोर्स', 3[1] जनवरी 1997।

³⁷ दि बिजनेस न्यूज, 'गेंबलिंग अवे पैराडाइज आइलैंड्स', 29.12.1994–11.01.1995; दि नेशन, 'कंबोडिया गेट्स इन टू स्वींग ऑफ गोल्फ बूम', 26.01.1996।

³⁸ फोम पेन्ह पोस्ट, 'लोकल्स पांडर दि प्राइस ऑफ गेम ऑफ गोल्फ', 20.10.1995–20.11.1995।

³⁹ न्यू फ्रंटियर्स, 'गोल्फ हेल्प्स स्वींग डील्स', 2[6] जून 1996।

⁴⁰ दि इरावाडी, 'गोइंग फॉर दि ग्रीन', 5[4–5] 1997।

सर्वाधिक पवित्र स्थल सीम रीप स्थित बारहवीं सदी का प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर परिसर स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर स्थानीय लोगों के लिए नहीं रह गया है और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसका व्यावसायीकरण किया जा रहा है।

कंबोडिया सरकार के अंकोरवाट आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 लाख करने के लक्ष्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इससे मंदिर क्षेत्र तथा इसके आसपास की इमारतें कुछ साल के अंदर ही नष्ट होने का खतरा है। 1995 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने अंकोर को अपनी संरक्षित स्थल की सूची से निकालने की धमकी दी क्योंकि कंबोडियाई अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया था। इनमें पुरानी वस्तुओं की चोरी तथा तस्करी रोकने के लिए सांस्कृतिक संरक्षण कानून लागू करना शामिल था।⁴¹ पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद मंदिर परिसर से हजारों पुरानी एवं कीमती वस्तुएं चोरी जा चुकी हैं। सरकार ने वादा किया है कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। अक्षम नौकरशाही, भ्रष्टाचार, प्रभावी कानून एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं नियंत्रण आदि की क्षमता के अभाव के कारण अंकोर को बचाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

विदेशी तथा कंबोडिया के पर्यावरणविद दो करोड़ अमेरिकी डालर के उच्चस्तरीय साउंड एंड लाइट शो से चकित थे। उनका कहना था कि इससे मंदिर मनोरंजन केंद्र या डिजनी जैसा मनोरंजन स्थल बन जाएगा।⁴² 1995 में मलेशिया की वाईटीएल कंपनी ने दावा किया कि वह विश्व में अपने तरह का अनोखा और बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस योजना में हर रात चार कार्यक्रम आयोजित होना था जिसमें मंदिर तथा उसकी भीतरी दीवारों को रंगीन रोशनी से सजाया जाता और लाउडस्पीकों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में आवाज सुनायी पड़ती। इस परियोजना के विरोधियों ने वैसी ही चिंता जतायी जैसी थाइलैंड में जतायी थी। थाइलैंड में ऐतिहासिक स्थलों पर ऐसे टूरिस्ट शो आयोजित होते हैं। अत्यधिक फ्लडलाइट और तेज आवाज से पुरानी नाजुक इमारत के जर्जर हो जाने का खतरा है।

वाईटीएल कंपनी उत्तर पश्चिमी मंदिरों के पास 1,095 हेक्टेअर भूमि पर पर्यटन जोन विकसित करना चाहती थी जिसमें कई लक्जरी होटल, गोल्फ कोर्स, एक कामर्शियल सेंटर, एक अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं शामिल की जानी थी। इस परियोजना में एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश होने की संभावना थी।⁴³ जनवरी 1996 में नरेश नोरोदोम सिंहानुक ने अंकोर के “व्यवसायीकरण” पर चिंता जतायी और वाईटीएल की लाइट एंड साउंड शो तथा पर्यटक परिसर की योजना की समीक्षा पर बल दिया।⁴⁴ लेकिन जुलाई 1997 में सह प्रधानमंत्री राजकुमार नोरोदम राणारिथ के खिलाफ प्रधानमंत्री हून सेन के खूनी विद्रोह के कारण कंबोडिया में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई और वाईटीएल की योजना शांत हो गई।

राजनीतिक उठापटक में बाद की सरकार ने देश के चौपट पर्यटन उद्योग को बहाल करने के लिए 1999 में “ओपेन स्काई” नीति शुरू की ताकि अंकोर मंदिरों के द्वार सीम रीप तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने भव्य “अंकोर 2000” शो का आयोजन किया।⁴⁵ पर्यटन अधिकारियों को उम्मीद है कि विदेशों से सीधे तौर पर उड़ानों से जुड़ जाने तथा ऐसे आकर्षक आयोजनों से अंकोर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा थाइलैंड से नए थल मार्गों से पर्यटकों एवं निवेशकों की संख्या बढ़ी है। अंकोर के आसपास अधिक पर्यटन सुविधाएं स्थापित होने लगी हैं।⁴⁶ इसके फलस्वरूप मंदिरों के खतरों को लेकर और आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। स्थानीय लोगों के पर्यटन के कुप्रभावों की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है।⁴⁷

⁴¹ न्यू फ्रंटियर्स, ‘अंकोरवाट में लूज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस’, 1[6], अक्टूबर 1995।

⁴² कंबोडिया डेली, ‘लेजर स्पेक्टेकल टू बीम अंकोरवाट टू 21 सेंचुरी’, 10–12.11.1995; फोम पेन्ह पोस्ट, ‘अंकोरवाट सिंक्रेट्स टू बी लॉस्ट इन ए साउंड एंड लाइट शो इंसल्ट’, 1–14.12.1995; न्यू फ्रंटियर्स, ‘डेवलपमेंट प्लांस फॉर अंकोरवाट केटास्ट्रोफिक’, 2[3] मार्च 1996।

⁴³ कंबोडिया डेली, ‘सिएम रीप डेवलपमेंट जोन : एमओयू साइंड विद मलेशियंस’, 10–12.11.1995; दि नेशन, ‘ए मोनूमेंटल मिस्टेक’, 06.03.1996।

⁴⁴ बैंकॉक पोस्ट, ‘सिंहानाउक क्यूश्चंश अंकोरवाट प्लांस’, 30.01.1996।

⁴⁵ न्यू फ्रंटियर्स, ‘अंकोरवाट इन फोकस’, 6[1] जनवरी–फरवरी 2000; न्यू फ्रंटियर्स, ‘टूरिज्म इंडस्ट्री गेनिंग स्टीम’, 6[2] मार्च–अप्रैल 2000; दि नेशन, ‘ओपेन स्काईस ब्रिंग फ्लॉक्स ऑफ टूरिस्ट्स टू कंबोडिया’, 13.12.2000।

⁴⁶ दि नेशन, ‘सिएम रीम होटल बूम’, 28.03.2000।

⁴⁷ उदाहरण के तौर पर, ऐसी आशंकाएं दिसंबर 2000 में सिएम रीप में विश्व पर्यटन संगठन के सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री हुन सेन ने घोषणा की कि : “संस्कृति पर बगैर ठीक से विचार किए हुए पर्यटन को बढ़ावा देने से ऐसी संस्कृति जन्म लेगी कि पर्यटन से संस्कृति नष्ट हो जाएगी।” (देखें – दि नेशन, ‘स्ट्राइकिंग ए बैलेंस’, 16.12.2000)

4. फासिस्ट डिजनीलैंड – बर्मा में पर्यटन एवं मानवाधिकार

मानवाधिकार हनन को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आलोचना का सामना कर रही बर्मा की सैन्य सरकार ने 1996 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी अभियान “विजिट म्यामार (बर्मा) इयर” शुरू की।⁴⁸ सैन्य सरकार को उम्मीद थी कि 1996-97 में ढाई लाख विदेशी पर्यटक आएंगे जिससे आय बढ़ेगी और 1988 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर रक्तंजित सैन्य कार्यवाई के बाद दशकों से अलगाव झेल रहे बर्मा को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पहचान मिलेगी। बर्मा के पर्यटन अधिकारियों और उद्योग जगत ने देश को ‘गोल्डन लैंड’ कहकर पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया। आलोचकों ने बर्मा को अपने नागरिकों के लिए जेल तथा विदेशी पर्यटकों के लिए “फासिस्ट डिजनीलैंड” के रूप में पेश किया। (लारेंस 2001)

बर्मा के विरोधी संगठनों तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बर्मा के पर्यटन बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि जहां लोगों को मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं, वहां पर्यटन से देश का भला नहीं हो सकता। लोकतंत्र समर्थक नेत्री और नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित आन सान सूकी ने बार बार विदेशी निवेशकों एवं पर्यटकों से आग्रह किया है कि लोकतंत्र बहाल नहीं होने तक वे दूर ही रहें।⁴⁹ दलील यह है कि पर्यटन से होने वाली आय से दमनकारी व्यवस्था को मजबूती मिलती है और वह इस आय का उपयोग हथियार खरीदने तथा अपने नागरिकों के खिलाफ ही सैन्य कार्यवाई में करती है। हरेक विदेशी पर्यटक को देश में प्रवेश करने पर 200 अमेरिकी डॉलर के बराबर का विदेशी मुद्रा प्रमाण पत्र खरीदना होता है। कई पर्यटन सुविधाएं सरकारी हैं। ऐसे में आय का एक बड़ा हिस्सा सैन्य सरकार के खजाने में जाता है। इसके अतिरिक्त सेना के सदस्य अपना पर्यटन आधारित व्यवसाय चलाते हैं या उन्होंने निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर लिया है ताकि निजी आय बढ़ाई जा सके।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और बर्मा एवं अंतरराष्ट्रीय नागरिक संगठनों जैसी आधिकारिक एजेंसियों ने पर्यटन उद्योग के विकास तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के आपस में जुड़े होने का जिक्र किया है।⁵⁰

रंगून, मांडले, पगान, तौगयी, नेमो तथा अन्य प्रस्तावित पर्यटन स्थलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि हजारों परिवारों को जबरन उनके घरों से बाहर किया गया ताकि खाली भूमि पर होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके।⁵¹ अधिकतर विस्थापित लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्हें ऐसे स्थलों पर शरण लेनी पड़ी जहां पर्याप्त साफ सफाई, बिजली और जलापूर्ति भी नहीं है। साथ ही लाचार आम लोगों को अमानवीय स्थिति में काम करना पड़ा ताकि पर्यटन स्थलों का उन्नयन हो सके एवं पर्यटन की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों का निर्माण हो सके।⁵²

⁴⁸ बर्मा में पर्यटन एवं मानवाधिकार पर बहस एवं ‘विजिट म्यामार इयर’, के खिलाफ अभियान के लिए उदाहरण के लिए देखें सकटिकलिफ 1994, टिम-टीम 1994; एनसीजीयूबी 195; पिलगर 1996; पर्नवेल 1998; न्यू फ्रंटियर्स, बर्मा इश्यूज एवं इरावाडी के विभिन्न अंक; स्वतंत्र बर्मा समन्वय के वेबसाइट <http://www.freeburma.org> एवं टूरिज्म कंसर्न के वेबसाइट <http://www.tourismconcern.org.uk> देखें।

⁴⁹ जुलाई 1996 में सिंगापुर स्थित सैटेलाइट नेटवर्क एशिया बिजनेस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सू की ने कहा कि : “हम चाहते हैं कि बर्मा में लोकतंत्र के आंदोलन के समर्थन में लोग ‘विजिट म्यामार इयर’ से दूरी बनाएं।” (देखें – न्यू फ्रंटियर्स 2[8], अगस्त 1996)। बाद में उन्होंने संवाददाताओं को कहा : “हां, मेरा मन किसी भी तरह से नहीं बदला है। पर्यटकों को बर्मा तब वापस आना चाहिए जब यहां लोकतांत्रिक समाज हो, जहां लोग सुरक्षित हों – जहां न्याय मिले, जहां कानून का शासन हो।” (देखें बर्मा न्यूज, स्प्रिंग 1997)।

⁵⁰ नवंबर 2000 में, आईएलओ ने बर्मा पर लगातार जोर जबरदस्ती से मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ‘न्यायेतर व्यवहार करने, मनमाने सजा देने, जबरदस्ती हत्या करने, बलात्कार, उत्पीड़न, अमानवीय उपचार, सामूहिक गिरफ्तारी, बच्चों सहित लोगों से जबरदस्ती मजदूरी कराने, जबरदस्ती विस्थापित करने एवं लोगों को स्वतंत्र एकत्रीकरण, संगठन, अभिव्यक्ति एवं आवागमन जैसे दुर्व्यवहार की निंदा के बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दिसंबर 2000 में बर्मा में घोर मानवाधिकार हनन के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया।” जुलाई 2001 में, इंटरनेशनल कांफिडिरेण ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ने बैंकॉक में हुए एक सम्मेलन में सैनिक सरकार के दावे का विरोध किया और कहा कि, “बर्मा अब भी दुनिया का सबसे बड़ा जबरिया श्रम शिविर” है। दि नेशन, ‘रिपोर्ट एक्ज्यूजेज बर्मा गवर्नमेंट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस’, 18.10.2000; दि नेशन, यूएन एक्ज्यूजेज जुंता ऑफ राइट्स एब्यूज’, 06.12.2000; दि नेशन, ‘यूएस एंड इयू बैक टफ स्टैंस ऑन फोर्स लेबर’, 22.03.2001; दि नेशन, ‘बर्मा अंडर स्क्रूटनी अगेन ओवर फोर्स लेबर’, 15.05.2001; दि नेशन, ‘बर्मा रिमेंस ‘वर्ल्ड्स बिग्रेस्ट फोर्स लेबर कैप’, 26.07.2001।

⁵¹ उदाहरण के लिए देखें सकटिकलिफ 1994, स्मिथ 1994; बर्मा इश्यूज, ‘टूरिज्म इंप्लोजन’, नवंबर 1996; पर्नवेल 1998।

⁵² सकटिकलिफ 1994; बर्मा पीस फाउंडेशन 1995; पिलगर 1996।

बर्मा में जातीय अल्पसंख्यक राज्य की नीतियों के कारण दशकों से पीड़ित रहे हैं। अब उन्हें उनके गांवों से होटलों या कथित 'मॉडल गांवों' में काम करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है।⁵³ इसके अतिरिक्त हजारों महिलाओं एवं लड़कियों को घरेलू सेक्स कारोबार में धकेला गया है और उन्हें वेश्याओं के रूप में काम करने के लिए थाइलैंड ले जाया जा रहा है।⁵⁴

बर्मा पर्यटन के खिलाफ जोरदार वैश्विक आंदोलन की सफलता के साथ ही 'विजिट म्यामांर ईयर' योजना असफल रही। एशियाई आर्थिक मंदी तथा देश के खिलाफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण 1997 से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 1998-99 में सिर्फ एक लाख बीस हजार विदेशी यात्री ही बर्मा आए।⁵⁵ यह संख्या सैन्य सरकार की उम्मीद से आधी थी हालांकि बर्मा के अधिकारियों को अभी उम्मीद है और हाल में उन्होंने एक नए अभियान की घोषणा की जिसका लक्ष्य 2001 तक पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाकर 10 लाख करना है।⁵⁶

विचार विमर्श – निरंतरता का सवाल

मीकांग क्षेत्र में पर्यटन नीतियों और उनके कार्यान्वयन की उपयुक्त पड़ताल से खुलासा होता है कि सतत पर्यटन के वैचारिक स्तर पर जैसी योजना बनाई गई थी और वास्तव में जो हुआ – उसके बीच काफी अंतर है। विभिन्न केस स्टडी में जो गंभीर स्थिति बताई गई है उससे इस बात के प्रति गंभीर आशंका पैदा होती है कि क्या पर्यटन विकास को दीर्घावधि तक बनाए रखा जा सकता है।

ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ऐसी पहल नहीं हुई जिसमें प्रमुख क्षति को दूर करने के लिए समुदाय आधारित और पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को शामिल किया गया। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ पर्यटन कंपनियों ने सकारात्मक स्वैच्छिक कदम उठाए ताकि प्रदूषण जैसे प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि ऐसे "सफल प्रयास" कुछ लघु परियोजनाओं तक ही सीमित हैं और निश्चित रूप से वे बड़ी चुनौती नहीं हैं तथा जिसने पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

समग्र स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारों, राष्ट्रीय पर्यटन अधिकारियों और एडीबी जैसी संस्थाओं की मीकांग पर्यटन संबंधी नीतियां पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्थानीय समुदाय की भलाई के बदले उद्योग को बढ़ावा देने के लिहाज से विशेष अनुकूल रही हैं। वाल के शब्दों के अनुसार पिछले वर्षों में एशिया में पर्यटन को बढ़ावा देने में "काफी पूंजी खर्च हुई है और यह टिकाऊ उत्पाद बनने में नाकाम रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी अव्यक्त धारणा रही है कि पर्यटन विकास उच्च गुणवत्ता वाले होटलों के निर्माण से हैं और एक बार उनके बन जाने के बाद बाकी सब तैयार हो जाएगा।" (वाल 1998)

गरीबी की आर्थिक परेशानी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षय एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पर नियंत्रण के मद्देनजर विकास के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में निश्चित तौर पर विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रबंध योजनाओं, अगर कोई हैं, की अकसर अनदेखी होती है और पर्यावरण जोन एवं निर्माण से संबंधित कानूनों को उचित तरीके से लागू नहीं किया गया। भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयां, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, स्थानीय एवं मूल निवासियों का विस्थापन, राजनीतिक दमन और मानवाधिकार हनन जैसे प्रमुख पर्यटन मुद्दे की नीति निर्माता अनदेखी करते रहे हैं। इस आधार पर आलोचकों के लिए यह कहना आसान है कि मीकांग क्षेत्र में सतत पर्यटन में सिर्फ वाकपटुता का इस्तेमाल किया गया है।⁵⁷

⁵³ न्यू फ्रंटियर्स, 'वेलकम टू पाइन कंट्री', 2[12], दिसंबर 1996;

⁵⁴ ह्यूमन राइट्स वाच 1994; इरावाडी के विशेष अंक 'सेक्स : दि फॉरगोटेन कमोडटी', फरवरी 2001; दि नेशन, 'आल रोड्स लीड्स टू माइजेरी', 09.04.2001।

⁵⁵ न्यू फ्रंटियर्स, 'विजिट म्यामांर ईयर 1996 : डेड ऑन एराइवल', 2[10], अक्टूबर 1996; न्यू फ्रंटियर्स, 'हिटींग बैंक एट टूरिज्म बॉयकाट कैंपेस', 6[5], सितंबर-अक्टूबर 2000।

⁵⁶ दि नेशन, 'बर्मा वोज वन मिलियन टूरिस्ट इन 2001', 28.10.2000।

⁵⁷ उदाहरण के लिए, एडीबी के जीएमएस टूरिज्म योजना के संबंध में, वांगपट्टन के टिप्पणी विचारणीय हैं : "एडीबी की 'विकास' की भाषा की शक्ति इस सत्य से परिलक्षित होती है कि उसकी भाषा अक्सर बहुत आलेचको द्वारा अपनाई जाती है जो कि बैंक की नीतियों एवं गतिविधियों में सुधार की मांग करती है।" आलोचना से सजग होकर वह विवादास्पद महाकायी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक आवाजों की बात कर रही है, "बैंक ने चालाकीपूर्ण तरीके से 'गरीबी निवारण' सामाजिक एवं पर्यावरणीय टिकाऊ विकास को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है।" (वांगपट्टन 2000)

ऐसी क्या बात है जिससे पर्यटन के लिए सतत विकास कठिन हो जाता है और कोई उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती। इस आखिरी खंड में कुछ स्पष्टीकरण और आगे विश्लेषण के लिए पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

सर्वप्रथम निरंतरता कोई तय एवं सहमत पद नहीं है और इसकी व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है। कई पर्यटन शोधकर्ताओं ने सतत पर्यटन के सिद्धांत एवं नीति की विवेचना करते हुए इसे अपूर्ण तथा दिग्भ्रमित करने वाला बताया है। “सतत पर्यटन ने व्यावसायिक एवं पर्यावरण हितों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचा है.....। एक एकल विचार के रूप में यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार करने में नाकाम रहा है।” (वाल 1997) शक्ति एवं निहित स्वार्थ जैसे मुद्दों की पर ध्यान देते हुए मोफोर्थ एवं मुंट ने कहा है कि, “सतत पर्यटन उद्योग में आपरेटरों की सेवा तथा अन्य गड़बड़ी के लिए खुला है” यह कहने की जरूरत नहीं है कि उद्योग में सिद्धांत की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है; लेकिन यह बताता है कि जो उनका कार्यान्वयन करते हैं, उनके इरादों पर नजर रखी जानी चाहिए।” (मोफोर्थ/मुंट 1998) व्हीलर की दलील है कि, “पर्यटन विकास, योजना और निरंतरता के लिए एक कारगर नजरिया की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। सही मायने में कारगर रवैया वह होगा जिसमें वास्तविकता को स्वीकार किया जाए। सतत पर्यटन दुर्भाग्य से व्यावहारिक स्तर पर नाकाम रहता है, यहां तक कि स्वीकार करने में भी।” (व्हीलर 1997)

वास्तव में मीकांग क्षेत्र में सतत पर्यटन की योजना मुख्य रूप से सैद्धांतिक अभियान रहा। इसमें वातावरण की ओर पर्याप्त विचार नहीं किया गया जिससे पर्यटन विकसित होता है। इस कारण मेजोन की टिप्पणी सही प्रतीत होती है, “एक व्यावहारिक समस्या का समाधान ऐसे सैद्धांतिक हल से नहीं हो सकता जिसमें व्यापक विचार नहीं किया गया हो। इस प्रकार वैकल्पिक नीति उपकरणों की तुलना या मूल्यांकन में मानक प्राप्त करना दिग्भ्रमित करने लायक होगा, मानक की उस विशेष संदर्भ में तुलना की जानी चाहिए जिसमें उस उपकरण का उपयोग किया गया हो। जिस संदर्भ में सार्वजनिक नीति बनी है, उसमें मूल्य, प्रावधान, अवधारणा तथा विचारधारा शामिल हैं, तकनीकी विचार विकल्प की प्रक्रिया के रूप में अपर्याप्त हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि “सतत पर्यटन” के विचार की जड़ें पश्चिमी पर्यावरणवाद से जुड़ी हैं जो अक्सर “ज्ञानार्जन” का रूप लेता है और एक स्तर तक संपन्नता एवं विकास हासिल करने पर निर्भर है। यह उस तीसरी दुनिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आजीविका आधारित पर्यावरणवाद के साथ अक्सर उलटा प्रतीत होता है, जहां गरीब किसान तथा वनों में रहने वाले निवासी आर्थिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा एवं दावा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। (हिरच/वारेन 1998) इन परस्पर विरोधाभासों की बेहतर समझ से यह वर्णन करने में सहूलियत हो सकती है कि पश्चिमी संरक्षण मॉडलों पर आधारित इकोटूरिज्म परियोजनाएं क्यों असफल हुईं और स्थानीय लोगों ने क्यों विरोध किया?

इस बात की भी अनदेखी की जाती है कि क्षेत्र में वैश्वीकरण का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, जो सतत विकास हासिल करने में बाधक है। इस संदर्भ में मीकांग पर्यटन संबंधी पर्नवेल का अध्ययन काफी मददगार साबित होता है। (पर्नवेल 1998) बर्मा में मानवाधिकार उल्लंघनों, थाइलैंड में एचआईवी/एड्स का संकट, सेक्स पर्यटन और क्षेत्र में गोल्फ पर्यटन का पर्यावरण पर प्रभाव का जिक्र करते हुए वह दलील देते हैं कि, “पर्यावरण का असर महत्वपूर्ण रूप से नियामक शक्ति के स्वामित्व पर निर्भर करता है।” वह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार बहुराष्ट्रीय एजेंसियों एवं निगम प्रभावशाली स्थानीय कारकों एवं संस्थानों के साथ काम करते हैं। इसको वह “पूँजीवाद का कचरा” बताते हैं। उनका निष्कर्ष है कि वैश्विक पर्यटन उद्योग के लिए नियमन को इसके विकास नियमन की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा रही है। इससे स्थानीय लोग खासकर निर्धन एवं वंचित लोगों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थिति की असुरक्षा बढ़ जाती है। (पर्नवेल 1998)

विभिन्न देशों खासकर निर्धन देशों में पर्यटन की आर्थिक व्यवहार्यता की निरंतरता के लिए प्रमुख शर्त के रूप देखा जाता है, इस पुराने सवाल को फिर से उठाए जाने की आवश्यकता है कि वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के दौर में सही अर्थों में किसे फायदा होता है। तीसरी दुनिया में पर्यटन मुख्य रूप से विदेशी उद्योगों के हितों से संचालित होते हैं और गंतव्य देशों के लिए आर्थिक लाभ के बारे में अक्सर अधिक आकलन कर लिया जाता है।

बैंकॉक स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 1990 में थाइलैंड के बारे में कराए गए अध्ययन से चौंकाने वाले नतीजे मिले – 1989 में पर्यटन आय का कम से कम 60 प्रतिशत यानी करीब चार अरब अमेरिकी डॉलर देश से बाहर चला गया। यह राशि वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात तथा विदेशी पर्यटन निगमों के लाभ एवं भुगतान में गई। (टीडीएससी 1991/92) विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की निरंतरता संबंधी अंकटाड के एक नए अध्ययन से तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। (अंकटाड 2001) इसमें कहा गया

है कि तीसरी दुनिया के देशों की पर्यटन उद्योग की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी निरंतरता के लिए “वित्तीय रिसाव” के बढ़ते स्तर से खतरा है जो आसानी से 75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मुख्यतया यूरोप व अमेरिका स्थित पर्यटन निगमों को बढ़ते “प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार एवं अनुचित तरीकों” से भी उन्हें खतरा है। अंकटाड की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन कारकों का सम्मिलित प्रभाव स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए जरूरी संसाधन आवंटित करने की देशों की क्षमता को कमतर कर देता है। (वही) ऐसी परिस्थिति में स्थानीय आर्थिक लाभ में वृद्धि करने और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत पर्यटन का घोषित लक्ष्य हासिल करना काफी कठिन है।

थाइलैंड में वित्तीय संकट के साथ ही जून 1997 में शुरू एशियाई आर्थिक मुश्किलों से पर्यटन उद्योग की नाजुकता के बारे में सीख ली जा सकती है (प्लीमैरम 1998/हाल 1998)। इससे स्पष्ट हुआ कि पर्यटन किस प्रकार अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है तथा वह ऐसा उद्योग है जिसमें उतार चढ़ाव का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इसमें बहुत कम संदेह है कि 1990 के दशक में शुरू में मीकांग उपक्षेत्र की प्रोत्साहनकारी पर्यटन नीतियों की 1997 के “संकट” में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तथाकथित “अर्थव्यवस्था में उछाल” के दौर में अंधाधुंध एवं असंगत निवेश से भूमि तेजी से आकर्षक पर्यटन रिजॉर्ट परिसरों में बदल गई। प्रगतिशील आर्थिक उदारीकरण के साथ ही रिएल इस्टेट एवं निर्माण उद्योग सभी मीकांग देशों में फले फूले और स्थानीय बैंकों तथा वैश्विक व्यावसायिक पूंजी ने उसे पूरी मदद दी।⁵⁸

आर्थिक मंदी के तत्काल परिणाम के रूप में एशियाई पर्यटन बाजार भी धराशायी हो गए।⁵⁹ थाइलैंड में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और प्रमुख निगमों जिनका कारोबार मीकांग के पड़ोसी देशों में फैला हुआ था, का कुप्रबंधन भारी ऋणग्रस्तता के रूप में सामने आया। कई पर्यटन डेवलपर {पर्यटन विकासकर्ता} दिवालिया हो गए या उन्हें अपनी परियोजनाएं छोटी करनी पड़ी। दक्षिण पूर्व एशियाई समाज में वैश्विक छुट्टी एवं पर्यटन जीवनशैली के नए प्रतीक के रूप में सामने आए, गोल्फ कोर्स एवं रिजॉर्ट कारोबार विशेष रूप से प्रभावित हुए और उनमें नाटकीय मंदी आई।⁶⁰

एडीबी सहित विभिन्न क्षेत्रीय निगमों की पहल से शुरू पर्यटन के बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाएं स्थगित कर दी गई क्योंकि एशियाई देशों की वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाए जाने की जरूरत थी।⁶¹ उदाहरण के लिए थाइलैंड में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और एडीबी ने 17 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया जिसमें सख्त संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) शामिल था।

उस समय, इस लेखक ने सुझाव दिया था कि कम से कम पर्यावरण के लिहाज से एशियाई संकट परोक्ष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। (प्लीमैरम 1998) यात्रियों की घटती संख्या के साथ ही विमानन कंपनियों ने गैर लाभकारी मार्गों को बंद कर दिया। कंपनियों ने अपने विमान बेच दिए, नए विमानों के आर्डर रद्द कर दिए, सरकारों ने हवाई अड्डा निर्माण तथा विस्तार के लिए बजट में कटौती की।⁶² इससे प्रदूषण के कम होने तथा नुकसान पहुंचाने वाले विकास में कमी आने की संभावना बनी। इसके अलावा पर्यटन परियोजनाओं में भूमि अतिक्रमण, पर्यावरण क्षय भी वैसा खतरनाक नहीं रहा जैसे पहले के समय में था। (वही)

⁵⁸ जिन ढांचागत समस्याओं की वजह से थाइलैंड आर्थिक संकट में घिर गया, उदाहरण के तौर पर उनका विश्लेषण निम्नलिखित में किया गया है फोंगपैचित पी., बैकर, सी. 1998; बेलो, डबल्यू कनिंघम, एस, लि खेंग पोह 1998; लैयर्ड 2000।

⁵⁹ न्यू फ्रंटियर्स, ‘ग्रिम टाइम्स फॉर एशियन टूरिज्म’, 4[1], जनवरी-फरवरी 1998।

⁶⁰ दि इकोनॉमिस्ट में छपे एक लेख (20.12.1997) का कहना है कि : “यह व्यक्त करने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि दक्षिण-पूर्व एशिया की आर्थिक प्रगति क्यों एकाएक चरमरा गई : वैश्वीकरण की ताकतें; विशिष्ट एवं गैरजिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था; पर्यावरण एवं गरीबों की आजीविका सहित किसी भी कीमत पर विकास की चाहत। गोल्फ इन सभी सिद्धांतों को एकजुट करता है.. .. ज्यादा जमीन की आवश्यकता एवं हमेशा बढ़ते धन पर उनकी निर्भरता के कारण गोल्फ कोर्स सबसे अनिश्चित निवेश थे। इसका बुलबुला सबसे पहले जापान में फूटा, जहां 100 से ज्यादा गोल्फ कोर्स नब्बे के दशक की शुरुआत में दिवालिया हो गए और सदस्यता शुल्क घटकर 20 प्रतिशत रह गया। थाइलैंड में, तीन गोल्फ कोर्सों की कीमत एक बार 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी जिसकी कीमत घटकर नवंबर [1997] में मात्र 1.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गई।

⁶¹ दि नेशन, ‘बैंक मुल्स एंड टू मीकांग कंट्रीज’, 18.04.1999। एडीबी की 100 से ज्यादा मंजूर उप-क्षेत्रीय ढांचागत परियोजनाओं में से केवल 10 ही सन 2001 तक पूर्ण हुए या पूर्ण होने को थे (पीएटीए 2001)।

⁶² न्यू फ्रंटियर्स, ‘एशियन एयर ट्रवेल इंडस्ट्री फाइटिंग फॉर सरवाइवल’, 4[4], जुलाई-अगस्त 1998।

स्थिति के बदलते ही मीकांग पर्यटन के प्रमोटर अपने पुराने रवैए पर लौट आए और विभिन्न सरकारों ने भारी कर्ज, आर्थिक वृद्धि में कमी और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की भरपाई के लिए अधिक “लालची” नीतियां तैयार ली।⁶³ थाइलैंड की मौजूदा नीति में देश के हरेक हिस्से को पर्यटन स्थल में तब्दील करने और पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि करने पर जोर दिया जाना गौर करने लायक है। इसके साथ ही वित्तीय संकट के कारण पर्यटन कार्यक्रमों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय कमी आई।

इसके साथ ही यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या पर्यटन ऐसे क्षेत्र में टिक सकता है जो राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार समस्याओं और सामाजिक आर्थिक संकटों से अत्यधिक प्रभावित हो? पर्यटन अधिकारियों ने “विजिट आसियान ईयर 2002” की तैयारियों के संदर्भ में स्वीकार किया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में राजनैतिक उठापटक और सामाजिक अशांति से आयोजन में गंभीर बाधा आ सकती है। हालांकि उन्होंने साथ ही समस्या को इस रूप में जतलाने का प्रयास किया कि उपभोक्ताओं के लिए “निश्चित” अवकाश की अवधारणा को प्रभावित करने के लिहाज से ऐसे मामले महत्वपूर्ण नहीं हैं।⁶⁴ रिक्टर लिखते हैं, –

“कमी, अभाव, असमानता, उपनिवेशवाद के अवशेष तथा महाशक्तियों के छद्म युद्धों ने हिंसा, जातीय संघर्ष, क्रांति और यहां तक कि अपहरण..... का मंच तैयार कर दिया। राजनीतिक मांगों से संबंधित प्रस्तावों का बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाला और आर्थिक आकांक्षाओं को हतोत्साहित करने वाला पिछड़ापन पर्यटन को आकर्षित करने के लिहाज से संभावित संपत्ति है। इस प्रकार हमारे सामने परस्पर विरोधाभासी बातें सामने आती हैं – ऐसा देश जहां अपने नागरिकों के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, उन्हें बाहरी लोगों के “बेहतरीन गंतव्य” के रूप में पेश किया जा रहा है। (रिक्टर 1995)

सतत पर्यटन के सिद्धांत की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता की बात निहित है और जनसहभागिता का मतलब है कि पर्यटन विकास प्रक्रिया में कुछ हद तक स्थानीय समुदायों का नियंत्रण होगा। (हाल 1994) बहरहाल सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द ‘स्थानीय सहभागिता’ और ‘समुदाय नियंत्रण’ अक्सर अविश्वसनीय एवं बेतुका लगते हैं जब उसे बर्मा जैसे देशों के संदर्भ में देखा जाता है जहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता नहीं है। शिव कुमार प्रश्न करते हैं – ‘क्या कुछ विशाल कंपनियां लोकप्रिय सहभागिता का स्थान ले सकती हैं?’ (1997) पर्यटन योजनाएं एवं प्रबंधन के संदर्भ में एडीबी नीत जीएमएस स्कीम जैसे क्षेत्रीय पहल विदेशी सलाहकारों पर काफी भरोसा करते हैं,⁶⁵ जिन्हें स्थानीय नीति के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती “जबकि प्रस्तावित उपक्षेत्रीय परियोजनाओं के प्रकार स्थानीय सहभागिता और सतत विकास की धारणा को नकारते हैं जिसके लिए अधिकतर दाता और बहुराष्ट्रीय संस्थान अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं” (वही)।⁶⁶

मीकांग देशों में खासकर बर्मा, चीन, विएतनाम और लाओस में जनसहभागिता की संभावना काफी क्षीण है हालांकि थाइलैंड में स्वतंत्र मीडिया और पर्यावरण आंदोलन एवं नागरिक अधिकारों की स्थिति बेहतर है। लोग नुकसानदेह विकास को लेकर सवाल कर सकते हैं और अपनी आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के बारे में बोल सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों ने भी कई वर्षों तक पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और लोगों को ध्यान में रखकर उन विकास नीतियों पर बल दिया है जो सिर्फ पर्यटन तक ही सीमित नहीं हैं।⁶⁷

⁶³ पर्यटन को नई ऊंचाई देने के अलावा थाइलैंड में ज्यादा विदेशी मुद्रा लाने के लिए, सरकार ने इमारती लकड़ी एवं झींगा जैसे लाभदायी निर्यात उत्पाद को प्रोत्साहित करना चाहा। इस तरह, अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में आए बाढ़ के बाद पेड़ों की कटाई पर लगी रोक को हटाया गया, और देश में झींगा फार्मिंग पर लगी रोक को हटाने की भी योजना थी, जोकि 8,00,000 हेक्टेअर मंग्रोव जंगलों के नष्ट होने के बाद लगाई गई थी (पून्यारत 2001)।

⁶⁴ न्यू फ्रंटियर्स, ‘विजिट आसियान कैपेन ऑन दि रोल’, 7[1], जनवरी-फरवरी 2001।

⁶⁵ एडीबी के उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर क्षेत्रीय तकनीकी सहायता के पर्यटन क्षेत्र घटक के लिए मूल अध्ययन (आरइटीए 5535) 1993 एवं 94 में टूरिज्म रिसोर्स सलाहकार अमेरिकन लेस्टर क्लार्क द्वारा कराया गया (एडीबी 1994)। बाद में, एडीबी की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ने पसिफिक कंसलटेंट इंटरनेशनल एशिया को जीएमएस टूरिज्म विकास की विचार योजना तैयार करने के लिए जापानी कंपनी को गठित किया (एएमटीए 1998)।

⁶⁶ जापानी संगठन मीकांग वाच के सैतोरु मात्सुमों के साथ इंटरव्यू में, एडीबी के कार्यक्रम विभाग के जीएमएस यूनिट के प्रबंधक तोउरो ततारा ने एडीबी की विकास परियोजनाओं में लोगों की भागीदारी को स्वीकार किया। “हालांकि काफी समय से भागीदारी के दावे किए जाते रहे, लेकिन एडीबी ने वास्तव में इसे क्रियान्वित नहीं किया।... हमें ज्यादा समय और ज्यादा संसाधन [नागरिक समाज की भागीदारी के लिए] देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमें उस तरीके को नजरअंदाज करना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ सलाहकारों के रिपोर्ट के आधार पर ही सड़क बनाते हैं।” (देखें वाटरशेड 5[3] मार्च-जून 2000)

⁶⁷ बैंकॉक में एक्यूमेनिकल कोआलिशन ऑन थर्ड वर्ल्ड टूरिज्म के 1986 से 1992 तक कार्यकारी सचिव रहे कोसोन श्रीसैंग ने प्रस्ताव किया कि तीसरी दुनिया में पर्यटन का हल खोजने के लिए हमें पर्यटन के विकल्प को बहस को शामिल करना चाहिए। “हमें पर्यटन विकास पर निर्भर रहने के बजाय अपना विकास करना चाहिए।... जहां पर्यटन न हो, इसे भूल जाएं। वास्तव में इसे शुरुआत से रोका जाय। और ऐसा कुछ किया जाय जिससे हमारे देश, हमारे समुदाय और हमारे लोगों का विकास हो। लोगों के स्वविकास की आवश्यकता को महत्व दिया जाय। जो कि मेरा कहना है कि पर्यटन का विकल्प; न कि वैकल्पिक पर्यटन।” (श्रीसैंग 1991/92)

पहले के खंडों में जैसा रेखांकित किया गया है कि पर्यटन विकास के मौजूदा स्वरूप के फलस्वरूप कई समस्याएं एवं संघर्ष उभरे हैं क्योंकि कई ग्रामीण एवं मूल समुदायों का अपनी भूमि, संस्कृति एवं प्राकृतिक संसाधनों से नियंत्रण खत्म हो गया। ऐसे में सबसे आवश्यक कार्यों में से एक ऐसी नीतियां तैयार करना है जिससे स्थानीय लोगों को अनियंत्रित एवं क्षति पहुंचाने वाले पर्यटन से बचाया जाए और उन्हें विकास एवं संरक्षण परियोजनाओं में और अधिक शक्ति प्रदान की जाए।

इस दिशा में जमीन से जुड़े कई संगठन काम कर रहे हैं और ऐसे प्रस्ताव पेश किए हैं जिनमें विकास एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी मूल समस्याओं से निबटने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए थाइलैंड में ऐसे संगठनों और स्थानीय समुदायों के नेटवर्क ने मिलकर एक 'पीपुल्स एजेंडा' तैयार किया जिसमें सरकार की नीतियों में व्यापक सुधार का आह्वान किया गया है और नीति निर्माताओं से निम्नलिखित कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है –

- प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में संप्रभुता पर जोर दिया जाए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उसका नियंत्रण नहीं छोड़ा जाए;
- ऐसी वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था विकसित की जाए जो स्थानीय समुदायों की आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों पर आधारित हो;
- नीतियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर आधारित हों जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, संस्कृतियां और ज्ञान प्रणालियों की विविधता और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखा जाए;
- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित नीतियों के प्रारूप में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए;
- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की गारंटी और उन्हें मजबूती प्रदान करना;
- प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय आर्थिक विकास के सतत प्रबंधन में स्थानीय समुदायों के नेटवर्क के प्रयासों का समर्थन करना। (राजेश 2001)

एजेंडा में उचित एवं न्यायसंगत ऐसे भूमि सुधार पर विशेष बल दिया गया जो लघु किसान समुदायों एवं उनकी मांगों का समर्थन करता हो। “विदेशी या थाई भूस्वामियों को गैर कृषि या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर खेती योग्य भूमि एकत्र करने या उनका नियंत्रण करने से अनिवार्य रूप से रोका जाना चाहिए।” (वही) बढ़ते भूमि संघर्ष को हल करने के नजरिए से यह प्रस्ताव होटलों, गोल्फ रिजॉर्ट और अधिक भूमि की जरूरत वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें ग्रामीणों की भूमि का स्वामित्वहरण होता है और छोटे किसानों की परेशानी बढ़ती है।

मौजूदा समय में ऐसा नहीं लगता कि पर्यटन विकास परियोजनाओं में पीपुल्स एजेंडा जैसे विकास विकल्पों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और जो आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक एकता और पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि जमीन से जुड़े ऐसे प्रस्ताव समस्याओं के हल में कारगर साबित हो सकते हैं। इसके लिए और परिचर्चा तथा जनदबाव की जरूरत है जिससे पर्यटन के लिहाज से कारगर एवं जनकेंद्रित नजरिया अपनाया जा सके और ‘संभावित शक्तियों’ को अपनी नीतियों में अपेक्षित बदलाव के लिए राजी किया जा सके। जैसा तियो और चांग ने लिखा है, “.....वैश्विक माहौल में स्थानीय लोगों की जरूरतों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। पर्यटन विकास की सफलता या विफलता अंततः उन्हीं के द्वारा तय होगी।” (तियो/चांग 1998)

संदर्भ

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), प्रमोटिंग सब रीजनल कोआपरेशन अमांग कंबोडिया, दि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लाओ पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यामांर, थाइलैंड एंड विएतनाम (अंतरिम रिपोर्ट)
2. एडीबी (1996), ग्रेटर मीकांग सबरीजन: सिकस्थ कांफ्रेंस ऑन सबरीजनल कोआपरेशन, कनमिंग, यून्नान, पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 28–30 अगस्त।
3. एडीबी की वेबसाइट <http://www.adb.org>
4. मीकांग पर्यटन का समन्वय करने वाली एजेंसी (एएमटीए) (1998), कांसेप्ट प्लांस फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन दि ग्रेटर मीकांग रीजन 1999–2018, बैंकॉक।
5. एएमटीए वेबसाइट www.visit-mekong.com
6. बेलो, डब्ल्यू कनिंघम, एस. ली खेंग पोह 1998, ए सियामीज ट्रेजेडी : डेवलपमेंट एंड डीसइंटिग्रेशन इन मॉडर्न थाइलैंड, लंदन/न्यूयार्क/ऑकलैंड, सीए/बैंकॉक

7. बेलो, डब्ल्यू. (2000), एडीबी 2000 : सिनियर ऑफिसियल्स एंड इंटरनल डॉकुमेंट्स पेंट इंस्टीट्यूशंस इन कंप्यूजन, फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ, बैंकॉक।
8. बर्मा पीस फाउंडेशन (1995), 'फोर्स लेबर इन टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स', फोर्स लेबर इन बर्मा – दस्तावेजों का संग्रह, 1987–1995, संख्या 4, न्यूयार्क।
9. चांदलर, एन. (1995), 'रिवर ऑफ दि ड्रीम्स : दि मीकांग एलाएंस', पीएटीए ट्रवल्स न्यूज, मार्च।
10. कोहन ई (1996), थाई टूरिज्म : हिल ट्राइब्स, आइलैंड्स एंड ओपन इंडेड प्रोस्टीट्यूशंस, बैंकॉक।
11. जीएजीएम अपडेट्स (1993–1996), वैश्विक गोल्फ विरोधी आंदोलन द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों की श्रृंखला
12. घिमिरे के. बी. (1991), पार्क्स एंड पिपुल : लाइवलीहूड इश्यूज इन नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट इन थाइलैंड एंड मेडागास्कर, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (यूएनआरआईएसडी), डीपी 29, जेनेवा।
13. हॉल, सी. एम. (1994), टूरिज्म एंड पॉलिटिक्स : पॉलिसी, पॉवर एंड प्लेस, चिचेस्टर।
14. हिर्स, पी. (1998), सीइंग फारेस्ट फॉर ट्रीज : इनवायरमेंट एंड इनवायरमेंटलिज्म इन थाइलैंड, चियांग माई।
15. हिर्स, पी. वारेन, सी (इडीएस) (1998), दि पॉलिटिक्स ऑफ इनवायरमेंट इन साइथ इस्ट एशिया : रिसोर्स एंड रेजिस्टेंस, लंदन/न्यूयार्क।
16. ह्यूमन राइट्स वाच (1994), ए मॉडर्न फोरम ऑफ स्लेवरी : ट्रेफिकिंग ऑफ बर्मीज विमेन एंड गर्ल्स इन टू ब्रोथेल्स इन थाइलैंड, एशिया वाच विमेंस राइट्स प्रोजेक्ट, न्यू यार्क।
17. लेयर्ड, जे (2001), मनी पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड क्राइसिस : दि केस ऑफ थाइलैंड, बैंकॉक
18. लॉरेंस एन (2001), नाइस कंट्री – शेम एबाउट दि डिक्टेटरशिप, दि इरावाडी, जनवरी 2001।
19. मेयर डब्ल्यू (1988), बियांड दि मास्क : ट्रांसडिसिप्लीनरी एप्रोच ऑफ सेलेक्टेड सोशल प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू दि इवोलुशन एंड कांटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इन थाइलैंड, सारब्रुइकेन/फोर्ट लाउडर डेल।
20. मीकांग रिवर कमीशन सेक्रेटिएट (1995), प्रिपेरेशन ऑफ दि मीकांग बेसिन डेवलपमेंट प्लान, बैंकॉक।
21. मीचाउद, जे. (1993), दि सोशल एंकरिंग ऑफ ट्रेकिंग टूरिस्ट बिजनेस इन ए हमोंग कम्युनिटी ऑफ नार्दन थाइलैंड, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 5–10 जुलाई 1993 को हुए थाई स्टडीज पर पांचवे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत पेपर।
22. मोउफोर्थ, एम/मुंट, आई (1998), टूरिज्म एंड सस्टेनिबिलिटी : न्यू टूरिज्म इन थर्ड वर्ल्ड, लंदन/न्यूयार्क।
23. यूनियन ऑफ बर्मा की राष्ट्रीय संयुक्त सरकार (एनसीजीयूबी) (1995), पोजिशन ऑन दि विजिट म्यामांर इयर – 1996', निष्काषित बर्मा सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, वाशिंगटन, 25 मई।
24. रिक्टर, एल (1995), पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी एंड टूरिज्म इन थर्ड वर्ल्ड', हैरिसन, डी. (एड), टूरिज्म इन लेस डेवलेप्ड कंट्रीज, चीचेस्टर/न्यूयार्क/ब्रिसबेन/टोरोंटो/सिंगापुर।
25. प्रशांत एशिया ट्रवेल एसोशिएशन (पीएटीए) (2001), 'ए रिवर रंस थ्रो इट', एशियन हॉस्पिटलिटी, 7 सितंबर
26. पीएटीए बेबसाइट <http://www.pata.org>
27. पर्वेल एमजेजी (1998), 'टूरिज्म ग्लोबलाइजेशन एंड क्रिटिकल सिक्यूरिटी इन म्यामांर एंड थाइलैंड', सिंगापुर जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल जियाग्राफी 19(2)।
28. फोंगपैचिट पी. बेकर, सी. (1998), थाइलैंड्स बूम एंड बस्ट, बैंकॉक।
29. फोलपोक, सी. (1998), दि चियांग माई केबल कार प्रोजेक्ट लोकल कंट्रोवर्सी ओवर कल्चरल एंड इकोटूरिज्म, हिर्स, पी. वारेन, सी. (इडीएस) (1998), दि पॉलिटिक्स ऑफ इनवायरमेंट इन साउथ इस्ट एशिया : रिसोर्स एंड रेजिस्टेंस, लंदन/न्यूयार्क।
30. पिल्लर जे. (1996), 'इन ए लैंड ऑफ फियर', दि गार्जियन-वीकेंड, 4 मई।
31. पिपिथ्वानिचदैम, पी. (1997), 'इश्यूज एंड चैलेंजेश ऑफ इकोटूरिज्म इन दि नेशनल पार्क्स ऑफ थाइलैंड', बॉर्नएमियर, जे., विक्टर एम, डस्ट पी. बी. (इडीएस) (1997), इकोटूरिज्म फॉर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, थाइलैंड के चियांग माई में 28–31 जनवरी 1997 को हुए अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के कार्यवृत्त, बैंकॉक।
32. प्लीमैरम ए. (1994), 'स्पोर्ट एंड इनवायरमेंट : थाइलैंड्स गोल्फ बूम रिव्यूड', टीआईआई त्रैमासिक पर्यावरणीय जर्नल, 2(4)।
33. प्लीमैरम ए. (1997/98), 'ट्रेकिंग टूअर्स वाकिंग ऑन दि राइट्स ऑफ लोकल पिपुल', वाटरशेड, 3(2)।
34. प्लीमैरम ए. (1998), टूरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड दि पॉलिटिक्स ऑफ इनवायरमेंट एजेंडा, 'लीजर इन एग्लोबलाइजेशन सोशायटी : इक्लुजन ऑर एक्सक्लुजन? पर लीजर एंड रिक्रिएशन एशोसिएशन (डब्ल्यूएलआरए) के पांचवे सम्मेलन का प्रमुख नोट, साओ पाओलो, ब्राजील 26–30 अक्टूबर।
35. प्लीमैरम ए. (1999), 'मीकांग टूरिज्म ब्रिंग्स डिजास्टर्स', दि नेशन, 2 फरवरी।
36. पून्यारत सी. (2001), मेगाप्लांस फॉर टूरिज्म ब्रिंग वरीज', इंटरनेशनल प्रेस सर्विस, 3 सितंबर।
37. राजेश एन. (2001), 'ए पिपुल्स एजेंडा फॉर चेंज', वाटरशेड 6(3)।
38. सेसर एन. (2000), 'इकोटूरिज्म बुल्डोजेश अहेड, एशियन वाल स्ट्रीट जर्नल, 30 जून।
39. शिकुमार एम. एस. (1997), सबरीजनल इकोनॉमिक इंटिग्रेशन एंड दि पुअर : ऐ क्रिटिक ऑन दि डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन दि मीकांग रिवर बेसिन, फॉम पेन्ड। स्मिथ एम (1994), दि इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड बर्माज कल्चरल हेरिटेज, लेख 19, सेंसरशिप के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय केन्द्र, लंदन।
40. श्रीसैंग के (1991/92), 'एन अल्टरनेटिव टू टूरिज्म', थाइ डेवलपमेंट न्यूजलेटर, संख्या 20।

41. सतक्लीफ एस. (1994), 'बर्मा : दि अल्टरनेटिव गाइड, बर्मा एक्शन समूह, लंदन।
42. तियो पी. चांग टी. सी. (1998), 'क्रिटिकल इश्यूज इन ए क्रिटिकल एरा : टूरिज्म इन साउथ इस्ट एशिया', सिंगापुर जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल जियोग्राफी 19(2)।
43. थाई डेवलपमेंट सपोर्ट कमेटी (1991/92), रिगार्डिंग टूरिज्म डेवलपमेंट इन थाइलैंड, थाई डेवलपमेंट न्यूजलेटर, संख्या 20।
44. थाइलैंड इनवायमेंट इंस्टीट्यूट (1994), 'टूरिज्म इकोलॉजी एंड 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट', टीआईआई त्रैमासिक जर्नल का विशेष अंक 2(4)।
45. दि इकोनॉमिस्ट (1997/98), 'गोल्फोनॉमिक्स : एशिया इन दि रफ', 20 दिसंबर-2 जनवरी।
46. टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाइलैंड (टीएटी) (1995), इकोटूरिज्म इन थाइलैंड, बैंकॉक में 7-8 दिसंबर 1995 को टीएटी एवं वाडेन मिल्स द्वारा आयोजित सेमिनार में इकोटूरिज्म पर प्रस्तुत पेपर।
47. टूरिज्म इंवेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग दल (टिम टीम) (1994), 'दि फोर्स टूरिज्म बूम इन बर्मा, बैंकॉक।
48. टिम टीम (2000), टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इन थाई नेशनल पार्क्स फंडेड बाई दि वर्ल्ड बैंक/ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड (ओइसीएफ), सोशल इंवेस्टमेंट प्रोग्राम, <http://www.twinside.org.sg/title/iy7.htm>
49. टूवाडर्स इकोलॉजिकल रिकवरी एंड रीजनल एलाएंस (टीआईआरआरए), 'एडीबी : डेवलपमेंट एज इफ कारपोरेशन मैटर', वाटरशेड 5(3)।
50. अंकटाड (2001), दि सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इन डेवलपिंग कंट्रीज, बर्लिन में 6-7 मार्च 2001 को पर्यटन नीति एवं आर्थिक विकास पर हुए सेमिनार में ओइसीटी के लिए प्रस्तुत पेपर, <http://www.oecd.org/dsti/sti/transport/tourism/news/UNCTAD.pdf>
51. वाल जी. (1997), 'इज इकोटूरिज्म सस्टेनेबल?' इनवायमेंटल मैनेजमेंट 21(4)।
52. वाल जी. (1998), 'रिफ्लेक्शन ऑन दि स्टेट ऑफ एशियन टूरिज्म', सिंगापुर जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल ज्योग्राफी 19(2)।
53. वांगपट्टना ए. (2000), 'डीकंसट्रक्टिंग दि एडीबी', वाटरशेड 5(3)।
54. व्हीलर बी. (1997), हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो इको, सेंटर फॉर अरबन एंड रीजनल स्टडीज, इनवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम।

अनछुआ¹ स्वर्ग – किस कीमत पर?

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आशय पर केन्द्रित व एसएसईसी क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक की पर्यटन विकास योजना से उठने वाले मुद्दों एवं आशंकाओं का विश्लेषण

विद्या रंगन, *इक्वेशंस*, मार्च 2006

¹ सन 2005 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मार्केटिंग एवं प्रचार अभियान जारी किया। उसके लिए शब्दावली इस्तेमाल किया गया 'अनछुआ स्वर्ग', जिसे एडीबी द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के अपने पर्यटन विकास कार्यक्रम में एसएसईसी के माध्यम से स्वीकार किया गया।

पर्यटन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों² के लिए नया विकास मंत्र है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास करना। पूर्वोत्तर के लिए विकास मंत्र के तौर पर पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करना, हालांकि कोई नई बात नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा तेजी हाल के सालों में आई है। देश के नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में इकोटूरिज्म एवं एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देकर एवं बुनियादी ढांचा, ठहरने की व्यवस्था और पर्यटन गाइड सुविधा में सुधार करके खासतौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन के दोहन की संभावना पर ध्यान केन्द्रित किया गया।³ सन 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति भी पूर्वोत्तर में भ्रमण पर्यटन, इकोटूरिज्म एवं ग्राम पर्यटन जैसे पर्यटन के विशिष्ट स्वरूप को बढ़ावा देना इस बात को मान्यता देती है। दसवीं योजना (2002–2007) में पूर्वोत्तर में दो नये होटल प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करके पर्यटन में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पर जोर दिया गया गया।

वित्तीय स्तर पर भी, राज्य एवं केन्द्र सरकारें पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास के लिए कोष बरसाती रही हैं। पर्यटन मंत्रालय के सालाना बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्रों की योजना के लिए आबंटित किया गया है।⁴ यह आंकड़ा 2003–04 में 34.48 करोड़ से बढ़कर 2004–05 में 65.59 करोड़ हो गया जो कि सिर्फ एक साल में 46 प्रतिशत वृद्धि थी।⁵ पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2006–07 के लिए पेश किए गए बजट में पूर्वोत्तर के लिए बजट में और बढ़ोतरी करके 83 करोड़ रुपये व्यय की योजना बनाई गई। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर के बजट आबंटन का एक बड़ा हिस्सा ढांचागत विकास के लिए है। यहां तक कि पर्यटन मंत्रालय के अंदर ही, पूर्वोत्तर के व्यय के आंकड़े बताते हैं कि आबंटित रकम का 75 प्रतिशत से ज्यादा पर्यटन संरचना तैयार करने, गंतव्य विकास एवं एकीकृत सर्किट विकास के लिए निवेश किया गया।⁶ यदि हम एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी संस्थाओं की क्षेत्रीय पर्यटन विकास में भूमिका का आकलन करें तो बुनियादी ढांचा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है।⁷ पर्यटन में निवेश के लिए पर्यटन उद्योग को भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। उदाहरण के लिए मेघालय के पर्यटन नीति में पर्यटन उद्योग के लिए निम्नलिखित छूटों को रेखांकित किया गया है – निवेश सब्सिडी, रखरखाव एवं संरक्षण सब्सिडी, बिक्री कर छूट, स्टॉप ड्यूटी छूट, प्रचार छूट, ऊर्जा उत्पादन एवं टेलीफोन सब्सिडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए सहयोग एवं विलासिता कर में छूट प्रमुख हैं।⁸

पूर्वोत्तर, एक आदर्श पर्यटन ब्रोसर बनाता है। निःसंदेह, वहां अलौकिक सुंदरता, संपन्न सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक महत्ता वाले क्षेत्र मौजूद हैं, जहां तक पहले बहुत कम लोग पहुंच सके हैं। इसी को ‘अनछुआ’ पर्यटन गंतव्य के तौर पर प्रचारित किया गया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर पर्यटन पर जारी प्रचार सामग्री में क्षेत्र को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है –

“बहुसंख्य आदिवासी परंपरा एवं हस्तशिल्प, मित्रतापूर्ण परंपरा, अंतहीन जैवविविधता से युक्त भूगोल, जीव-जंतु, भाषा, बौद्ध स्थलों के रीति रिवाज एवं वास्तुकला ने सैकड़ों लोगों को आकर्षित करना शुरू किया है।”⁹

पर्यटन के कुछ विविध रूपों को जिन्हें केन्द्र व राज्य सरकारें इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहती हैं उनमें इकोटूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन व वन्यजीव पर्यटन प्रमुख हैं, जबकि असम चाय पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहता है, सिक्किम एवं त्रिपुरा तीर्थयात्री पर्यटन एवं कुछ राज्य एडवेंचर एवं गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं।

² पूर्वोत्तर शब्द मूल रूप से भारतीय क्षेत्र के अंदर भौगोलिक स्थिति को संकेत करने लिए उपयोग किया गया। जबकि संवैधानिक रूप से पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम छठवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर परिषद द्वारा शासित किए जाते हैं, जिसका गठन संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1971 में किया गया है एवं यह उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। सिक्किम को इस परिषद में दिसंबर 2002 में शामिल किया गया।

³ वही। नौवीं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, भारत सरकार, अंक दो, पर्यटन पर भाग 7.6।

⁴ वार्षिक रिपोर्ट 2004–05, भारतीय पर्यटन, भारत सरकार।

⁵ वही

⁶ पर्यटन मंत्रालय के 2004–05 के आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए योजनावार कोष कुल 6559.418 लाख जारी किया गया, जिसमें 4028.4 लाख रुपये अकेले पर्यटन ढांचा के लिए व्यय किया गया। (वार्षिक रिपोर्ट 2004–04, भारतीय पर्यटन, भारत सरकार)

⁷ सन 2004 में, क्षेत्र में एडीबी के कर्ज के प्राथमिकता वाले सेक्टर (क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए दिए गए कर्ज की रकम के प्रतिशत के आधार पर) परिवहन एवं संचार (38.4 प्रतिशत), ऊर्जा (14.4 प्रतिशत), बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं (12.3 प्रतिशत) एवं कानून, आर्थिक प्रबंधन व सार्वजनिक नीति (11 प्रतिशत) थे।

⁸ मेघालय पर्यटन नीति 2001, मेघालय सरकार।

⁹ अतुल्य भारत! भारत का पूर्वोत्तर, अनछुआ स्वर्ग प्रचार सामग्री ब्रोसर

क्षेत्र में ठोस औद्योगिक आधार के अभाव एवं लाभकारी खेती में मुश्किल के कारण पूर्वोत्तर में पर्यटन को रोजगार के एक प्रमुख स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। मेघालय की पर्यटन नीति (2001) में खुले तौर पर खेती एवं औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के प्रति असमर्थता जताई गई है और इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को अपनी विकास रणनीति को पर्यटन पर केन्द्रित करना पड़ा।¹⁰ असम में पर्यटन की स्थिति एवं संभावना पर योजना आयोग की रिपोर्ट की दलील है कि पर्यटन से टूरिस्ट गाइड, प्रबंधित पर्यटन एवं होटल स्थापना के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।¹¹ भारत सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने के लिए पर्यटन को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ लेखकों द्वारा जोर दिया गया है (बेजबरूआ, 2005)¹²। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, रोजगार उत्पन्न करने एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पर्यटन को जोरदार प्रोत्साहन के प्रयास किए गए। इस पृष्ठभूमि के आधार पर, एडीबी द्वारा उपक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने की पहल सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास को पीठ थपथपाने जैसा प्रतीत होता है। चूंकि सभी राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा एवं चीन से लगती हैं, इसलिए उपक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में पूर्वोत्तर स्वाभाविक पसंद है। हालांकि, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, नैतिक एवं पर्यावरणीय स्वरूप काफी संवेदनशील है, जिन्हें किसी भी विकास योजना में ध्यान रखना होगा। शोध के माध्यम से यह कहा जाता है कि पर्यटन प्रदूषण रहित होता है और सतत विकास के लिए सर्वोत्तम विकल्प है, लेकिन मौजूदा प्रमाणों को देखते हुए जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। एक 'विकास बैंक' के तौर पर एडीबी की भूमिका पर भी अध्ययनों के माध्यम से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसने इसकी नवउदारवादी एजेंडा, निजीकरण के प्रति झुकाव एवं उपक्षेत्र को कर्ज में डुबोने का चरित्र उजागर किया है। इस आधार पर, यह पेपर एसएसएससी के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर इलाके पर जोर देते हुए उपक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की एडीबी की भूमिका का समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करता है।

हाथों में हाथ – एडीबी, क्षेत्रीय सहयोग एवं पर्यटन

एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसने सन 2004 में कुल 529.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज इस क्षेत्र को दिया था।¹³ एडीबी के काम करने का प्राथमिक तरीका है किसी देश को किसी परियोजना के लिए एवं नीति सुधार/आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए कर्ज देना, जो कि विकसित होने वाले संबंधित देश रणनीति एवं कार्यक्रम (सीएसपी) से जुड़े होते हैं। हालांकि, हाल ही में, एडीबी ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समन्वय स्थापित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसे एडीबी द्वारा 'क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकृत विकास' कहकर प्रचारित किया जा रहा है। वर्तमान में एडीबी 6 उपक्षेत्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, जो निम्नलिखित हैं¹⁴ –

- सीएआरईसीयू (केन्द्रीय एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग इकाई)
- जीएमएस (ग्रेटर मीकांग उपक्षेत्र)
- एसएसएससी (दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग)
- आईएमटी-जीटी (इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड विकास ट्राइएंगिल)
- बीआईएमपी-इएजीए (ब्रुनेई-इंडोनेशिया-मलेशिया-फीलीपींस ईस्ट एशियाई विकास क्षेत्र)
- क्षेत्रीय आर्थिक निगरानी इकाई

¹⁰ नीति का कथन है कि –“पिछले 20 सालों के दौरान, सरकार ने रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्योगों को विकसित करने, खेती एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने बहुतेरे प्रयास किए हैं। दुर्भाग्यवश, इच्छानुसार परिणाम नहीं मिले क्योंकि व्यावहारिक औद्योगिक आधार मौजूद नहीं है, और यहां तक कि पर्यटन क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे विकसित हुए हैं वे काफी बेतरतीब हैं और किसी उचित योजना या सोच के बगैर ही विकसित किए गए हैं। (मेघालय पर्यटन नीति 2001, मेघालय सरकार)

¹¹ असम में पर्यटन : स्थिति एवं संभावना, http://planningcommission.nic.in/plans/stateplan/sdr_assam/sdr_assch8.doc

¹² पर्यटन की संभावनाएं, एम पी बेजबरूआ, <http://www.india-seminar.com/2005/550/550%20m.p.%20bezbaruah.htm>

¹³ अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन ने सर्वाधिक 125.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज हासिल किया, जबकि भारत ने 125.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज हासिल किया, जो कि कुल वितरित कर्ज का क्रमशः 23.8 प्रतिशत एवं 23.7 प्रतिशत रहा। इसके अलावा तकनीकी सहायता अनुदान के तौर पर 15.427 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को 2.892 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज मिला, जबकि 1.12 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ भारत पांचवा सबसे ज्यादा रकम हासिल करने वाला देश रहा। स्रोत : एडीबी एट ए ग्लॉस, मई 2005

¹⁴ स्रोत : एडीबी वेबसाइट www.adb.org

उपरोक्त विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, प्रशांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में सहयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। एडीबी की दलील है कि क्षेत्रीय सहयोग को समर्थन करना दो कारकों पर निर्भर है – पहला यह कि सामूहिक पार-देशीय समस्याओं का सामूहिक रूप से हल करने के लिए देशों को मौका देना एवं दूसरा यह कि विशेषज्ञता, व्यापार, निवेश, सूचना एवं तकनीक की उपलब्धता में सुधार करना¹⁵ (एडीबी, 2004)। खास बात यह है कि, एडीबी को महसूस होता है कि व्यापार आदान-प्रदान को मुक्त करके, नियामक पर्यावरण में सुधार करके, प्रतियोगिता बढ़ाकर एवं देशों को अपने व्यापार उदारीकरण की प्रतिबद्धताओं के योग्य बनाकर क्षेत्रीय सहयोग रणनीति से गरीबी निवारण ठीक तरीके से हो सकता है¹⁶।

लेकिन आज एडीबी द्वारा जिसे 'क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समन्वय' कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में एवं नब्बे के दशक की शुरुआत में एडीबी एवं अन्य दानदाता एजेंसियों के अनुरोध पर क्षेत्र के कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रयोग किए गए 'विकास ट्राइएंगल' या 'उपक्षेत्रीय आर्थिक जोन' का बदला हुआ स्वरूप है। इन ट्राइएंगलों के सफल होने के कारक अतिविकसित शहरी इलाके होते थे जिसमें जमीन एवं मजदूर समाप्त कर दिए गए; आसपास के इलाके जमीन एवं मजदूर से भरपूर होते हैं; एवं इन दोनों के बीच इस अप्रत्यक्ष एवं परोक्ष बाधाओं को कम करने की यह राजनीति है¹⁷। इस तरह आज जीएमएस के अंतर्गत 5 देश एवं चीन का यूनान प्रांत शामिल हैं, जो कि गोल्डेन क्वाड्रिलैटरल (स्वर्णिम चतुर्भुज) से विकसित हुए हैं। इसमें उत्तरी थाइलैंड, म्यांमार, लाओस एवं यूनान शामिल हैं। इसी तरह एसएसईसी दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज का संवारा हुआ सोच है, जिसे एडीबी ने 2001 में शुरू किया है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं भारत शामिल हैं। दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज को प्रोत्साहित करने के लिए एडीबी की बढ़ती रुचि के पीछे गुप्त उद्देश्य पर गहरी नजर रखने वाले राघव नैरसले का कहना है कि, "..... एडीबी की दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज बनाने के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे महत्वपूर्ण कारणों से एक है यूएस के उद्योगों द्वारा यूएस सरकार के माध्यम से लगातार दबाव दिया जाना क्योंकि यूएस एडीबी की सबसे बड़ी डोनर है। दबाव देने वाले उद्योगों में खासकर वे उद्योग शामिल हैं जो ऊर्जा उत्पादन एवं उत्पादन उपकरण बनाने में संलग्न हैं।"¹⁸ इस तरह एडीबी के क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की विचारधारा¹⁹ पर चर्चा करते समय ग्रोथ ट्राइएंगल के संदर्भ में उठाए गए विदेशी पक्षों द्वारा निहित स्वार्थ एवं केन्द्रीय परिधि एवं अर्थिक हब तैयार करने के तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इसके तहत क्षेत्र विशेष पहलों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करते समय इसे अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बैंक²⁰ द्वारा व्यक्तिगत देश के आधार पर दिए जाने वाले कर्ज या मंजूर किए जाने वाले परियोजनाओं में पर्यटन प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं रहा है। जबकि नेपाल, लाओ पीडीबार, कंबोडिया एवं विएतनाम ने पर्यटन के लिए विशिष्ट कर्ज हासिल किया, जिसमें से नेपाल के अलावा अन्य तीन देशों ने जीएमएस के अंतर्गत कर्ज हासिल किया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि पर्यटन एडीबी के दायरे में नहीं है बल्कि बैंक से कर्ज लेने वाले 45 सक्रिय देशों के कई सीएसपी में इसका थोड़ा संदर्भ है। नीचे दिए गए सारिणी में एडीबी के सदस्य देशों के नवीनतम सीएसपी एवं सीएसपी अपडेट से आंकड़े एवं पर्यटन में रुचि व संदर्भ की सूची दी गई है।

¹⁵ एशियाई विकास बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 2004

¹⁶ एशियाई विकास बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 2004

¹⁷ उदाहरणतया सीजोरी दक्षिणी विकास ट्राइएंगल जो कि सिंगापुर को मलेशिया के जोहोर राज्य एवं इंडोनेशिया के रियाऊ और पश्चिमी सुमात्रा प्रांत को जोड़ता है। अस्सी एवं नब्बे के दशक के बीच में इंडोनेशिया का बातम पर्यटन एवं सिंगापुर से रियल इस्टेट निवेश का प्रमुख गंतव्य था, जबकि जोहोर श्रम-आधारित निर्माण का पसंदीदा स्थल था। (को-ऑप्टिंग कोऑपरेशन : दि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सबरीजनल इकोनॉमिक जॉस, क्रिएटिंग पोवेटी : दि एडीबी इन एशिया, फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ, मई 2000)।

¹⁸ नेपाल में यूएस के पूर्व राजदूत सैंडी वोगील्लसैंग द्वारा गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में व्यापक निवेश के अवसर उपलब्ध कराने में नेपाल की भूमिका की तारीफ के आधार पर यह दलील दी गई। इसके तहत जलविद्युत के क्षेत्र में यूएस के निवेशकों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए गए। 'साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रैंगल, सम डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कंट्राडिक्शंस', राघव नैरसले, प्रॉफिटिंग फ्रॉम पोवेटी – दि एडीबी, प्राइवेट सेक्टर एंड डेवलपमेंट इन एशिया, फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ, अप्रैल 2001।

¹⁹ अपने कई दस्तावेजों में, एडीबी लगातार थाइलैंड को जीएमएस का अर्थिक केन्द्र बताती है एवं एसएसईसी में भारत उसके समकक्ष है। थाइलैंड के लिए एडीबी की देश रणनीति कार्यक्रम में कहा गया है कि, जीएमएस का आर्थिक केन्द्र होने के कारण थाइलैंड अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत आपसी हित स्थापित कर सका है। (थाइलैंड सीएसपी अपडेट 2006-08)

²⁰ वही 7

सारिणी 5 : पर्यटन घटक के साथ विश्व बैंक की परियोजनाएं (2005 के अनुसार)

क्रम	एडीबी देश रणनीति एवं कार्यक्रम अपडेट	संदर्भ का स्वभाव/पर्यटन में रुचि
1	बांग्लादेश (सीएसपी 2006–2010)	एसएसआईसी के माध्यम से पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग
2	भूटान (सीएसपी 2006–2010)	एसएसआईसी के माध्यम से पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग, खासकर इकोटूरिज्म एवं गांव आधारित पर्यटन को सक्रिय प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, नये इलाके खोलना एवं पर्यटन को नियंत्रित मुक्त करना।
3	कंबोडिया (सीएसपी 2005–2009)	जीएमएस के माध्यम से गरीब अनुकूल पर्यटन विकास, शहरी एकीकरण माध्यम से पर्यटन को सहयोग, एवं इकोटूरिज्म को सहयोग के लिए संरचना, पर्यावरण प्रबंधन योजना।
4	चीन पिपुल्स रिपब्लिक (सीएसपी अपडेट 2006–2008)	जीएमएस के माध्यम से यूनान में पर्यटन, इकोटूरिज्म एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शांक्सी किंगिंग माउंटेन एकीकृत इकोसिस्टम प्रबंधन योजना।
5	कुक द्वीप समूह (सीएसपी 2004–06)	पर्यटन में पीएसपी को सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्यक्रम जल एवं सैनिटेशन प्रबंधन कार्यक्रम स्थापित करना व यूजर चार्ज सिद्धांत लागू करना, समुदाय आधारित इकोटूरिज्म
6	फीजी द्वीप समूह (सीएसपी अपडेट 2005–2007)	पर्यटन संबंधित संरचना विकास, इकोटूरिज्म एवं बाहरी द्वीप विकास परियोजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट नवीनीकरण एवं क्षमता बढ़ाना
7	किरीबाती (सीएसपी अपडेट 2006–2007)	पर्यटन के लिए भूमि उपयोग पैटर्न में सुधार करना एवं क्षेत्रीय बदलाव को क्रियान्वित करना एवं क्षेत्र परियोजना के लिए जमीन मुक्त कराने के लिए सरकार को मदद करना
8	लाओ पीडीआर (सीएसपी अपडेट 2006–2008)	जीएमएस के माध्यम से गरीब अनुकूल पर्यटन
9	मालदीव (सीएसपी अपडेट 2006–2008)	पर्यटन विकास को देखने के लिए घरेलू मेरिटाइम परिवहन
10	मार्शल द्वीप समूह गणतंत्र (सीएसपी अपडेट 2005–2006)	पर्यटन संरचना में निजी क्षेत्र का निवेश, पर्यटन नीति की समीक्षा।
11	माइक्रोनेशिया फेडरेशन (सीएसपी अपडेट 2006–2007)	पर्यटन में पीएसपी, एसएमई में मानको का क्रियान्वयन, आमदनी/रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
12	मोंगोलिया (सीएसपी 2006–2008)	पर्यटन में पीएसपी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड कॉरिडोर विकास परियोजना।
13	नेपाल (सीएसपी 2005–2009)	एसएसआईसी के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन, पर्यटन संरचना के लिए स्वतंत्र कर्ज।
14	सोलोमन द्वीप समूह (सीएसपी अपडेट 2005–2006)	पीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के मालिकाना वाले पर्यटन में बदलाव के लिए सरकार को मदद करना।
15	श्री लंका (सीएसपी अपडेट 2006–2008)	पर्यटन के लिए एसएसआईसी को आमंत्रण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलंबो साउथ पोर्ट हारबर का निर्माण।
16	थाइलैंड (सीएसपी अपडेट 2002–2004)	जीएमएस के माध्यम पर्यटन को प्रोत्साहन।
17	टोंगा (सीएसपी अपडेट 2005–2006)	पर्यटन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग पैटर्न पर अध्ययन।
18	विएतनाम (सीएसपी अपडेट 2006–2008)	मीकांग पर्यटन संरचना विकास परियोजना।
19	वनुआतु (सीएसपी अपडेट 2005–2006)	क्रूज पर्यटन गंतव्य की तरह विकास करना।

स्रोत : एडीबी की देश रणनीति कार्यक्रम www.adb.org

हालांकि, क्षेत्रीय सहयोग रणनीति के संदर्भ में एडीबी के लिए पर्यटन का महत्व काफी बढ़ा है। उदाहरण के लिए सीएसआईसी रणनीति एवं कार्यक्रम अपडेट (2006–08) का कहना है कि पर्यटन विकास के लिए तकनीकी सहायता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 800,000 अमेरिकी डॉलर सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन कोष की पुनः प्राथमिकता निर्धारण होने के कारण यह अब तक उपयोग नहीं हुआ है। इसी तरह प्रशांत क्षेत्र की रणनीति में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राजनैतिक स्थिरता लाने पर जोर दिया गया है। जीएमएस और एसएसआईसी में, क्षेत्रीय सहयोग के लिए पर्यटन न सिर्फ प्राथमिकता वाला क्षेत्र है बल्कि एडीबी ने राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों के साथ एजेंडा को आगे ले जाने के लिए क्षेत्र रणनीति एवं कार्यसमूह तैयार करने के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल होना शुरू कर दिया है।

इसीलिए, एडीबी क्षेत्र विशेष कर्ज एवं परियोजनाओं के बजाय क्षेत्रीय सहयोग रणनीति के माध्यम से पर्यटन विकास को सहयोग करने के प्रति ज्यादा इच्छुक है। कुछ संभावित व्याख्या इस प्रकार है :

- पर्यटन के पार-क्षेत्रीय स्वरूप एवं जटिल संस्थागत संरचना के कारण किसी अलग पर्यटन परियोजनाओं पर सक्षम रूप से कार्य कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरणतया, सैद्धांतिक रूप से एक पर्यटन परियोजना के अंतर्गत किसी गंतव्य को विकसित करने या नया गंतव्य तैयार करने के लिए एक क्रियान्वयन एजेंसी की जरूरत होगी और उसे पर्यटन से जुड़ी परिवहन, पर्यावरण व वन, शहरी विकास जैसे अन्य संस्थाओं/संगठनों के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। इससे यह व्याख्या हो सकती है कि पर्यटन में निवेश अक्सर पर्यावरणीय संरक्षण परियोजनाओं (जैसे कि अफ्रीका में विश्व बैंक परियोजनाएं) या ढांचागत व परिवहन क्षेत्र के परियोजनाओं (जैसे कि एशिया प्रशांत में एडीबी) में उप-घटक होता है।
- एडीबी जैसे बैंक द्वारा सेक्टर कर्ज मंजूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कसौटियां तय की गई हैं। ये कसौटियां हैं कर्ज लेने वाले देश/क्रियान्वयन एजेंसी की स्पष्ट क्षेत्र विकास योजनाएं तय करने एवं उन्हें हासिल करने हेतु संभावित वित्तपोषण वाले परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में संस्थागत क्षमता का होना।²¹ पर्यटन के मामले में बहुत कम देशों ने स्पष्ट नीति एवं प्राथमिकताएं तय की हैं। इसके अलावा, पर्यटन में सटीक डाटा और आंकड़ों के न होने के कारण पर्यटन के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण की आवश्यकता को समर्थन देने में बाधा आ सकती है।
- क्षेत्रीय सहयोग के मामले में, एडीबी का विश्वास है कि सभी क्षेत्रों के बीच सामान्यतया ऊर्जा, पानी, परिवहन एवं संप्रेषण को क्षेत्रीय सहयोग के लिए चुना जाता है; पर्यटन को 'न्यूनतम विरोध' वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। अर्थात् भागीदार देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए अन्य क्षेत्रों जिसमें विवाद या समस्याएं आ सकती हैं उनके मुकाबले पर्यटन के प्रति काफी खुलापन रखते हैं। इन क्षेत्रीय समन्वयों में से 'एकल गंतव्य' तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को इस्तेमाल करने की एडीबी महत्वाकांक्षा से यह विचार मजबूत हुआ है। पूरे उद्देश्य के बारे में एडीबी की जीएमएस पर्यटन सेक्टर रणनीति का कहना है कि – "मीकांग को एकल गंतव्य के तौर पर विकसित व प्रोत्साहित करना...जो लाभों को ज्यादा व्यापक तरीके से वितरित करने में मदद करता है, हरेक जीएमएस देश के विकास प्रयास को जोड़ता है.... जबकि किसी विपरीत असरों को कम करता है"²²। इसलिए जीएमएस के अंतर्गत पर्यटन उपक्षेत्र को सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं एडवेंचर गंतव्य के तौर पर "मीकांग ब्रांड" के आसपास बढ़ावा देगा, एसएसएसईसी दक्षिण एशिया में उपक्षेत्रों को प्रमुख 'इकोटूरिज्म अगुआ' या "बौद्ध केन्द्र" के तौर पर मार्केटिंग करेगी²³। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि एडीबी के लिए मौजूदा क्रियाकलाप के पसंदीदा स्वरूप क्षेत्रीय सहयोग के तौर पर पर्यटन प्रमुख एजेंडा है। जबकि, क्या इस क्षेत्र की समस्याओं का हल पर्यटन है? इस उपक्षेत्र में हरेक उपक्षेत्र के विकास स्तरों, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं प्राथमिकताओं में विविधता व अंतर होने के कारण एकीकृत पर्यटन विकास योजनाओं का संभावित असर क्या होगा? आगे का हिस्सा एडीबी की एसएसएसईसी पर्यटन योजना एवं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में उपरोक्त सवालों का जवाब तलाशता है।

संयुक्त ब्रांड : एसएसएसईसी पर्यटन योजना एवं उत्पाद

एसएसएसईसी की पृष्ठभूमि

एडीबी एसएसएसईसी उप क्षेत्र में बांग्लादेश, भूटान के अलावा भारत के उत्तर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13 राज्यों²⁴ को शामिल करते हुए इसे परिभाषित करता है। भौगोलिक रूप से इसमें दक्षिण एशिया के पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी उपक्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज से उभरे एसएसएसईसी के माध्यम से, एडीबी ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए छः प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन किया है। ये क्षेत्र हैं – ऊर्जा व बिजली, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, व्यापार व निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी। निःसंदेह, एसएसएसईसी ने पर्यटन क्षेत्र में बहुत लय बनायी है। इसके कई संकेत इस प्रकार हैं :

- सन 2001 में अपनी पहली गोष्ठी से शुरू करके, पर्यटन कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) (जिसमें चार राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालयों/बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं) की अब तक छः बार बैठकें हो चुकी हैं, जो कि एसएसएसईसी के किसी अन्य कार्य समूहों के मुकाबले ज्यादा गतिशील है।

²¹ एडीबी की बैंक नीतियों के लिए संचालन मैनुअल (2003) का कहना है कि एडीबी की क्षेत्रीय कर्ज नीति को पूरा करने के लिए तीन प्रमुख कसौटी को संतुष्ट करने की जरूरत होती है – क) कर्ज लेने वाले देश के पास सेक्टर विकास योजना होनी चाहिए; ख) उस सेक्टर विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत क्षमता का होना; ग) सेक्टर के लिए उपयुक्त नीतियों का होना, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। स्रोत : http://www.adb.org/Documents/Manuals/Operations/OMD03_29oct03.pdf

²² ग्रेटर मीकांग सबरीजन टूरिज्म सेक्टर स्ट्रेटजी, एडीबी, 2005, कार्यकारी सारांश

²³ मार्केटिंग कार्यक्रम समन्वय, एसएसएसईसी टूरिज्म टेवलपमेंट फ्रेमवर्क, एडीबी, 2004।

²⁴ ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम

- संदर्भ के मामले में टीडब्ल्यूजी के पास कई उपलब्धियां हैं। नेपाल के काठमांडू शहर में कार्यालय स्थापित करने एवं एसएसईसी पर्यटन चार्टर (2002, काठमांडू) अपनाने, एसएसईसी पर्यटन विकास योजना (2004, नई दिल्ली) तैयार करने व अपनाने, एसएसईसी सतत पर्यटन फोरम की पहली बैठक करने एवं एसएसईसी टीडीपी में श्रीलंका को जोड़ने (नवंबर 2005, कोलंबो) जैसे लक्ष्यों के मामले में इसने नियमित प्रगति की है।
- एसएसईसी टीडीपी 2004 में जारी हुआ था और यह पिछले पांच सालों में एसएसईसी की गतिविधियों से निकलने वाली एकमात्र अधिकारिक रिपोर्ट है।

पर्यटन के लिए अन्य प्रयासों में एसएसईसी पर्यटन में बौद्ध सर्किट²⁵ बनाने हेतु सहयोग की संभावना के लिए एवं एसएसईसी पर्यटन में मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य अध्ययन गठित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करना शामिल है। टीडब्ल्यूजी की बैठकों के कार्यवृत्त एवं दस्तावेज बताते हैं कि क्षेत्र में पर्यटन के लिए ब्रांड बनाने, संपर्क बनाए रखने एवं संयुक्त मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि टिकाऊपन, संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के लिए ध्यान नगण्य है। एसएसईसी पर्यटन चार्टर स्वयं क्षेत्र को 'एसएसईसी में धार्मिक अनुभव चाहने' की थीम के साथ ब्रांड बनाने पर, न्यू एशियन हाइवे के माध्यम से संपर्क में सुधार करने एवं राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों में क्षमता निर्माण के प्रयास बढ़ाने को प्राथमिकता देती है।²⁶

एक मॉडल के तौर पर मीकांग

अपने शुरुआती स्तर से ही एसएसईसी में पर्यटन विकास का स्वरूप जीएमएस में पर्यटन सहयोग के अनुरूप बनाया गया। इसमें थाइलैंड, कंबोडिया, विएतनाम, म्यांमार, लाओ पीडीआर एवं चीन का यूनान प्रांत शामिल हैं। एडीबी जीएमएस के अंतर्गत अपने पर्यटन सहयोग रणनीति को एक असमांतर सफलता के तौर पर दावा करता है और इसे एसएसईसी ढांचे में समायोजित करना चाहता है। इस बारे में स्पष्ट समझ के लिए जीएमएस मॉडल को विश्लेषण करने की जरूरत है, जो रणनीति एसएसईसी में अपनाई जानी हैं।

सन 1994 में, एडीबी एवं यूनीस्कैप (एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग) ने संयुक्त रूप से जीएमएस देशों की एक मीटिंग आयोजित की इससे पर्यटन कार्यसमूह एवं बाद में मीकांग पर्यटन फोरम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मूल रूप से मार्केटिंग की पांच जीएमएस पर्यटन परियोजनाएं संरक्षण में उपक्षेत्रीय फोरम, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संसाधन प्रबंधक बनाती हैं एवं मीकांग/लैकांग का नदी पर्यटन विकसित करती हैं, जो कि 2003 में सात ठोस प्लैगशिप कार्यक्रमों की उपज हैं²⁷—

- एकल पर्यटन गंतव्य के तौर पर जीएमएस को बढ़ावा देना
- पर्यटन संबंधित संरचना में सुधार करना
- पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन का सुधार करना
- प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मानकों में सुधार करना
- जीएमएस में गरीब अनुकूल टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना
- जीएमएस पर्यटन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- जीएमएस में पर्यटकों को आवगमन के लिए सहूलियत देना

मीकांग टीडब्ल्यूजी का स्थायी कार्यालय 1997 में स्थापित हुआ। इसे एसोसिएशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग मीकांग टूरिज्म एक्टिविटीज (एएमटीए) नाम से जाना जाता है जो कि बैंकाक में टूरिज्म आथॉरिटी ऑफ थाइलैंड के अंतर्गत स्थित है। जीएमएस मॉडल में निम्नलिखित कामों में लगी विभिन्न संस्थाओं के बीच भूमिकाएं बंटी हुई हैं²⁸—

- टीडब्ल्यूजी को समर्थन कर रहे एडीबी एवं यूनीस्कैप, इसकी बैठकों का खर्च उठाते हैं। अध्ययन एवं क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं और सालाना मीकांग टूरिज्म फोरम को वित्तपोषित कर रहे हैं।

²⁵ जनवरी 2005 में, एडीबी एवं यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक धरोहरों के सतत विकास एवं दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक पर्यटन पर एक गोलमेज मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में संरक्षण एवं विशिष्ट परियोजनाओं के विकास के माध्यम से बौद्ध सर्किट के समन्वय की संभावना पर चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी के लिए देखें — <http://www.adb.org/Documents/Events/2005/ADB-UNESCO-Roundtable/default.asp>

²⁶ नेपाल के काठमांडू में 31 मई से 2 जून 2002 तक पर्यटन कार्यसमूह के दूसरे बैठक में एसएसईसी पर्यटन चार्टर प्रस्तुत किया गया और मंजूर किया गया।

²⁷ 'दि ग्रेटर मीकांग सबरीजन (जीएमएस) एक्सपीरिएंस इन टूरिज्म', 2003 में ढाका में हुई एसएसईसी के तीसरे कार्यसमूह की मीटिंग के सलाहकार लेस क्लार्क की प्रस्तुति। http://www.adb.org/Documents/Events/2003/SASEC/Third_Mtg_Tourism/clark_gms.pdf

²⁸ काठमांडू में पर्यटन कार्यसमूह की पहली बैठक में एडीबी द्वारा 'कोऑपरेशन इन टूरिज्म' पर प्रस्तुत प्रस्तुत पेपर

एडीबी शोध अध्ययन भी विकसित कर रहा है और मीकांग में नदी आधारित पर्यटन संरचना जैसे जीएमएस पर्यटन योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए और कंबोडिया, विएतनाम एवं लाओ पीडीआर में परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।

- पीएटीए के सहयोग से एएमटीए जीएमएस पर्यटन का मार्केटिंग घटक है
- यूनेस्को संरक्षण संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है
- यूएनडब्ल्यूटीओ विभिन्न संस्थाओं से संपर्क बनाकर योजनाओं के लिए वित्तपोषण के विकल्प तलाशता है

एडीबी के अनुसार, जीएमएस पर्यटन सहयोग के कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :

- थाइलैंड-लाओ-यूनान के बीच दोस्ताना कारवां आयोजित करना
- जीएमएस के अंतर्गत नये हवाई मार्ग उपलब्ध कराना
- अंतरराष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट पर ज्यादा खुलापन उपलब्ध कराना
- कस्टम, आप्रवजन एवं संगरोध प्रक्रियाओं में तेजी लाना
- मीकांग नदी में व्यावसायिक नौकाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता
- गांव आधारित पर्यटन विचार को बढ़ावा देना

लेकिन क्या यही मॉडल है जिसे एडीबी द्वारा क्षेत्र में दीर्घकाल के लिए टिकाऊ होने की सक्रिय वकालत की जाती है? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं। बैंकॉक स्थित पर्यटन जांच एवं निगरानी दल (टिम टीम) द्वारा किए गए शोध में यह बात स्पष्ट होती है कि किस तरह एक के बाद एक करके एडीबी के जीएमएस पर्यटन कार्यक्रम ने किस तरह व्यापक स्तर पर विस्थापन करने के लिए 'टिकाऊ पर्यटन' एवं 'पर्यटन व संरक्षण' का शोर मचाया। यह 'इकोटूरिस्ट' के अधिकारों का महत्व देकर समुदायों को उनके प्राकृतिक व सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार देने से इनकार करती है।²⁹ स्थानीय समुदायों के उदाहरण बताते हैं कि एडीबी जैसी संस्थाएं गरीबी निवारण के नाम पर जो सीधा तरीका अपनाती हैं वह सामान्यता काम नहीं करता एवं इस क्षेत्र में निवेश को इच्छुक निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसका आगे कहना है कि 'टिकाऊ पर्यटन' का विचार मूल रूप से पश्चिमी पर्यावरणीय सोच में बसी हुई है जो कि एशिया के गरीब देशों में स्थित समुदायों के मूलभूत आजीविका की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखती है। इस तरह यह अति गरीबी, ज्यादा आर्थिक असमानता एवं विवाद संभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढल सकती है। व्यापक पर्यटन संरचना परियोजनाओं की अनुपयुक्तता की थाइलैंड के उदाहरण से व्याख्या की जा सकती है, जो कि व्यापक स्तरीय पर्यटन के दुष्प्रभाव का समाना कर रही है। इकोटूरिज्म का मतलब है वनों की कटाई, जहां हाइवे, एयरपोर्ट, होटलों, रिजॉर्टों, गोल्फ कोर्सों, पर्यटक केन्द्रों आदि पर्यटक संबंधित सुविधाओं के लिए व्यापक स्तर पर आसपास के जंगलों की कटाई की जाती है³⁰। पर्यटन ने अन्य मीकांग देशों को भी नुकसान पहुंचाया है जिनमें कंबोडिया के अंकोरवाट में सांस्कृतिक ह्रास; बर्मा में मूलभूत मानवाधिकारों का हनन एवं विएतनाम, लाओ व कंबोडिया में गोल्फ कोर्सों की भरमार से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय विनाश होना प्रमुख हैं। साथ ही मीकांग नदी में बांध बनाकर एवं क्षेत्र में सड़क एवं हाइवे परियोजनाओं की वजह से विस्थापन लाकर समस्याओं को और भी बढ़ाया है³¹। ऐसे में, इस एकल गंतव्य को मार्केटिंग करने की एडीबी द्वारा प्रायोजित जीएमएस योजना से दुष्प्रभाव बढ़ेंगे और पर्यटन के लाभ कम होंगे। यह पेपर अंत में कहता है कि, "इस पूरे परिदृश्य को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि मीकांग पर्यटन विकास के लिए सरकारों, राष्ट्रीय पर्यटन विभागों एवं एडीबी जैसी सुपरनेशनल संस्थाओं द्वारा आगे बढ़ाई जाने वाली नीतियां उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा अनुकूल हैं न कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए"³²।

जीएमएस के तथ्य से ठोस सुझाव उभरते हैं कि पर्यटन विकास योजना के माध्यम से एसएसईसी में भी ऐसी ही परेशानियां उभर सकती हैं, जो कि इस क्षेत्र के समुदायों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आगामी हिस्सा एसएसईसी टीडीपी के आगे बढ़ाने वाले क्षेत्रों को रेखांकित करता है और योजना में आशंका का प्रमुख क्षेत्र बन रहा है।

²⁹ 'मीकांग पर्यटन - मॉडल या उपहास? 'टिकाऊ पर्यटन' संबंधी एक केस स्टडी' अनीता प्लीमरम, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क इनवायमेंट एंड डेवलपमेंट सीरीज संख्या 3, पेनाग, मलेशिया, 2001

³⁰ 'एडीबीज टूरिज्म प्लान्स फॉर दि मीकांग रीजंस पोसेस रिस्कस नॉट बेनिफिट', नोएल राजेश, एशिया-यूरोप डायलॉग एंड पार्टनर, 2004।

³¹ बांध एवं ऊर्जा क्षेत्र में एडीबी की नीतियों से पैदा हुई समस्याओं पर व्यापक मूल्यांकन के लिए पढ़ें - मीकांग इन डेंजर : एडीबीज इन्वाल्मेंट इन दि ग्रेटर मीकांग सबरीजन' एनजीओ फोरम ऑन दि एडीबी गाइडबुक सीरीज, मार्च 2005

³² वही 29

पूर्वोत्तर के लिए क्या खास है?

एसएएसईसी पर्यटन योजना कुछ मामलों में जीएमएस के मुकाबले ज्यादा महत्वाकांक्षी है। चार लुभावने नारों को अपनाकर एसएएसईसी टीडीपी 23 विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 7 मोटे उपक्षेत्रीय कार्यक्रमों को रेखांकित करती है। ये नारे हैं 'अभिमुखी', 'संपर्क', 'समन्वय' एवं 'संरक्षण'। व्यापक तौर पर रेखांकित रणनीति इस प्रकार है (जीएमएस रणनीतियों के अनुरूप नहीं) –

- पर्यटन टिकाऊ एवं गरीबी निवारण के प्रति योगदान करने वाला होना चाहिए
- एसएएसईसी उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ध्यान केन्द्रित करना चाहिए न कि उपक्षेत्र पर
- संयुक्त मार्केटिंग
- उपक्षेत्र को पर्यटन अनुकूल गंतव्य के तौर पर स्थापित करना
- प्रतियोगी पर्यटन उद्योग का विकास³³
- पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना

अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों में शामिल है सार्क के लक्ष्यों से तालमेल बनाना, लाभ की भागीदारी सुनिश्चित करना, एसएएसईसी के अंतर्गत सदभावपूर्ण सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना एवं पर्यटन बुनियादी ढांचे का अधिकतम इस्तेमाल करना। इसके लिए चार मूलभूत कार्यक्रम रेखांकित किए गए हैं – मार्केटिंग प्रयासों में सहयोग³⁴, उत्पाद गुणवत्ता सुधारना, पार-देशीय यात्रा में सहूलियत देना एवं मानव संसाधन विकास करना। आगामी हिस्सा तीन कार्यक्रमों पारदेशीय यात्रा सुलभ करना, इकोटूरिज्म एवं बौद्ध सर्किट की योजना का विवरण देता है।

1. पार-देशीय यात्रा सुलभ कराना

क्षेत्र में आपसी यात्रा सुलभ कराने पर केन्द्रित रणनीति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह क्षेत्र के लिए नियोजित परिवहन गतिविधियों के साथ संपर्क को महत्व देता है। नियोजित कार्यक्रमों में से एक है चार पहियों वाले वाहन से जमीनी कारवां के रूप में पूर्वी हिमालय कारवां आयोजित करना। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रों द्वारा आयोजित, पार-देशीय मार्गों की क्षमता तलाशना एवं उनका उपयोग करना शामिल है। राष्ट्रीय पर्यटन संगठन इन मार्गों पर फ्लैग-वेविंग गतिविधि आयोजित करेंगे। प्रस्तावित मार्ग हैं पैरो (नेपाल) से गंगटोक, दार्जिलिंग, बागडोगरा, सिलीगुड़ी, ढाका, शिलांग, काजीरंगा, कोहिमा तवांग एवं गुवाहाटी तक। इसका कहना है – अंतिम लक्ष्य है सीमा की औपचारिकताओं को आसान बनाना। अन्य नियोजित गतिविधि है बागडोगरा को एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदलना और इसे केन्द्र के रूप में एसएएसईसी का प्रवेश मार्ग कहकर प्रस्तुत करना। भारत सरकार को इस उपाय की संभाव्यता पता करने और एयरलाइंस ऑपरेटरों को इस पर काम करने के लिए एक अध्ययन करवाना है। यात्रा सुलभ कराने के लिए तीसरी प्रस्तावित गतिविधि है यात्रा के अवरोधों को कम करना जिसमें वीजा एवं अनुमति, सीमा की औपचारिकताएं, एयरलाइंस उपलब्धता, मुद्रा इस्तेमाल एवं पर्यटन ऑपरेटर नियमन बनाना। यह महसूस करती है कि इन बाधाओं को समाप्त करके उपक्षेत्र के आकर्षण में मूल रूप से सुधार होगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ऑपरेटरों को दूर समूह आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरह “....दक्षिण एशिया को बेचें, खासकर कम प्रचलित इलाकों को जैसे कि बांग्लादेश, पूर्वी भूटान, भारत के पूर्वोत्तर के दूर-दराज के इलाके।” चौथा मुख्य प्रस्ताव है कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं सुलभ कराने के लिए एसएएसईसी के अंदर ही एशियन हाइवे³⁵ पहल

³³ ऐसी सुविधाओं के अंतर्गत टीडीपी देशों को सार्वजनिक-निजी सहयोग बढ़ाना, पर्यटन नियमन में सुधार करना एवं विदेशी ऑपरेटरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपलब्ध कराना (इस पर ज्यादा जोर), एसएएसईसी, टीडीपी, एडीबी, 2004।

³⁴ संयुक्त मार्केटिंग टीडीपी द्वारा चयन किए गए उप-विचारों एशिया में इकोटूरिज्म एवं बौद्ध सर्किट के इर्द-गिर्द घूमेगी। मजेदार बात यह है कि मार्केटिंग अभियान 'अतुल्य भारत' के अनुरूप होगा और उसका लाभ उठाया जायगा। इसका कहना है – उसीको इस्तेमाल करने से इस अभियान की सफलता बढ़ेगी, उप-क्षेत्रीय उत्पादों के इमेज को मजबूती मिलेगी एवं भारत के सोच से अभियान को महत्व मिलेगा। भारत सरकार एसएएसईसी पर्यटन मार्केटिंग कोष स्थापित करने के लिए कोष जुटाने हेतु शुरुआती गारंटी सामग्री तैयार करने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा एडीबी, जेबीआईसी, पीएटीए, फिक्की, एयरलाइंस एवं अन्य निजी क्षेत्रों के साथ सदस्य के बतौर एक एसएएसईसी मार्केटिंग समन्वय स्थापित किया जाएगा, जहां कुछ सदस्य प्रक्रिया को मदद कर सकें एवं कुछ उद्देश्य के लिए वित्तपोषित कर सकें।

³⁵ एशियन हाइवे परियोजना सन 1992 से यूनीस्कैप द्वारा कल्पना किया गया, तैयार किया गया और क्रियान्वित किया गया था। इसके अंतर्गत एशिया में कुल 1,40,000 किमी से लम्बे मार्ग के लिए 34 देशों ने इसके क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह पहले के एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली ऐतिहासिक सिल्क मार्ग की पुनर्रचना है। इस परियोजना से अफगानिस्तान, नेपाल, लाओस एवं भूटान जैसे जमीनी सीमाओं से घिरे हुए देशों को खासतौर पर लाभ की संभावना है।

को इस्तेमाल करना। टीडीपी की भारत में एशियन हाइवे के आसपास सड़क किनारे भ्रमण केन्द्रों और औद्योगिक गांवों³⁶ में भ्रमण की जेबीआईसी की योजना को स्वीकार करने की योजना है।

2. इकोटूरिज्म

एसएसआईसी टीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इकोटूरिज्म एवं बौद्ध सर्किट जैसे दो विचारों पर आधारित उत्पाद विकास करना। इकोटूरिज्म की योजनाओं में हिमालय में चढ़ाई के लिए एकीकृत परियोजना शामिल है, जो कि ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई को महत्ता देगी और अंततः सभी एसएसआईसी देशों को जोड़ेगी और चार देशों में प्राकृतिक स्थानीय, राष्ट्रीय पार्कों के माध्यम से पर्यटकों को लाएगी। एक बार शुरू होने के बाद परियोजना को बढ़ाकर इसमें जंगलों, आदिवासी लोगों एवं धरोहर गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित होगा। अन्य परियोजना क्षेत्र के गंगा-ब्रह्मपुत्र नदीघाटी में जल संसाधनों एवं इकोटूरिज्म पर फोकस करता है। परियोजना के भौगोलिक उद्देश्य में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता नदी के आसपास समस्त प्रसिद्ध दृश्य शामिल हैं। जैसे कि सुन्दरबन को नेपाल, भूटान एवं भारत में राष्ट्रीय पार्कों से जोड़ने की योजना। इसकी मार्केटिंग, क्षेत्र के सजीव वन्यजीव एवं प्राचीन संस्कृतियों पर आधारित होगी। इसका प्रमुख शुरुआती बिन्दु होगा ब्रह्मपुत्र में नये क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहन एवं विस्तार करना। इकोटूरिज्म का तीसरा हिस्सा होगा एसएसआईसी क्षेत्र में जल आधारित एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देना। परियोजना में नागालैंड के मोन एवं स्वेनसांग जिले, अरुणाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर जैसे एडवेंचर पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देना शामिल होगा। इच्छुक निजी पक्षों का नेटवर्क बनाया जाएगा जो उपक्षेत्र में मौजूदा मुक्त प्रवाही नदियों को संरक्षण या एडवेंचर पर्यटन की संभावित इस्तेमाल जैसे हितों को प्रोत्साहित करेंगे।

3. बौद्ध सर्किट विकसित करना

एसएसआईसी पर्यटन उत्पाद में जो अन्य मुख्य विचार का चयन किया गया वह है एसएसआईसी देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व को देखते हुए बौद्ध सर्किट विकास करना। प्रस्ताव में भारत और नेपाल के नेतृत्व में 'भगवान बुद्ध के पदचिन्ह' शामिल है, जिसमें सर्किट का संयुक्त नियोजन, मार्केटिंग एवं विकास करना शामिल है³⁷। भागीदारों की चर्चा में डॉटस, एसआई, बौद्ध सोसायिटियों, एडीबी, जेबीआईसी, जेआईसीए, यूएनडीपी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को शामिल करने का अनुमान है। दूसरे प्रस्ताव को 'लिविंग बुद्धिज्म इन हिमालय' कहा जाता है, जो कि सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एवं भूटान के 15 सजीव बौद्ध गंतव्यों का सुधार करने पर केन्द्रित होगा। इसमें बौद्ध विहार, धार्मिक स्थल, गुफाएं, मूर्तियां एवं पवित्र झील शामिल हैं, जिसमें कि धर्म के छात्रों, पर्वतारोहियों, योग प्रशंसकों एवं शांति चाहने वालों को लक्ष्य बनाया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव है दक्षिण एशिया में बौद्ध कला एवं पुरातत्व को महत्ता प्रदान करना, जिसमें स्थलों का सहयोगपूर्ण संरक्षण एवं प्रबंधन, ठहरने की व्यवस्था में सुधार करना, स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षित करना शामिल है एवं इन आकर्षणों को कवर करने के लिए मीडिया, फिल्म निर्माताओं एवं पुस्तक प्रकाशकों को आमंत्रित करना शामिल है।

सतत विकास की मरीचिका

दक्षिण एशिया उप क्षेत्र आर्थिक कार्यक्रम (एसएसआईसी) टीडीपी को लेकर चिंताएं एवं कुल मुद्दे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में।

1. टीडीपी तैयार करने में समुदायों की कम भागीदारी

एडीबी की अधिकतर अन्य परियोजनाओं के अनुरूप एसएसआईसी टीडीपी ऐसी योजना प्रतीत होती है जिससे पूरी तरह से नौकरशाही मशीनरी और पर्यटन में उद्योग लाबी के परामर्श से तैयार किया गया है तथा यह कारपोरेट परामर्श का परिणाम लगता है³⁸। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीडीपी पर कार्य राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालयों और चार एसएसआईसी राज्यों के संगठनों के साथ गहन परामर्श के साथ किया गया है। हालांकि, यह जानामाना तथ्य है कि

³⁶ यह विचार जेबीआईसी द्वारा दिया गया है, इसके अंतर्गत समुदायों को हस्तशिल्प उत्पादन एवं बिक्री के लिए केन्द्र बनाने एवं अपने गांवों के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

³⁷ सर्किट के गंतव्यों में बिहार के राजगीर, नालंदा, बोध गया, एवं वैशाली; उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती; कपिलवस्तु नेपाल में लुम्बिनी एवं आसपास के इलाके शामिल हैं।

³⁸ कारपोरेट टूरिज्म रिसोर्स कंसल्टेंट्स न्यूजीलैंड और काठमांडू की मेटकॉन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने एडीबी के लिए एसएसआईसी टीडीपी को तैयार एवं उनका क्रियान्वयन किया। टूरिज्म रिसोर्स निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो संरक्षण पहलु के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के सिलसिले में परामर्श मुहैया कराती है। फर्म ने हाल ही में जीएमएस टूरिज्म स्ट्रेटजी तैयार की है (<http://www.trcnz.com/>)। वही मेटकॉन ने नेपाल में एडीबी वित्तपोषित सभी परियोजनाएं तैयार की है (<http://www.metconnepal.com/>)।

कई देशों में पर्यटन विकास और नीति-निर्माण एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और स्थानीय सरकारों और समुदायों से योजना चरण में बहुत राय नहीं ली जाती (इक्वेशंस- 2005)। टीडीपी विकसित करने के रवैए और तौर तरीके से संबंधित खंड में दावा किया गया है, “योजना तैयार करने वाली टीम का पूरा जोर विभिन्न तथ्यों के साथ देश में ही परामर्श पर था ताकि क्षेत्र के अंदर और अंतर-राष्ट्रीय पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए उपक्षेत्रीय सहयोग के बेहतर इस्तेमाल की खातिर सरकार और उद्योग का नजरिया हासिल किया जा सके और उन्हें समझा जा सके।”³⁹ प्रक्रिया के संबंध में ढोंग उपर्युक्त बयान में साफ झलकता है और पूरे दस्तावेज को सही ठहराता है। टीडीपी में “सामुदायिक भागीदारी” को पर्यटन के एक उद्देश्य के रूप में बार-बार कहा गया है लेकिन वास्तव में योजना तैयार करने या उनके क्रियान्वयन में समुदायों की सहभागिता या उनके चयनित स्थानीय प्रतिनिधियों की सहभागिता नगण्य रही है। टीडीपी में एक जरूरी अनुबंध है जिसमें ‘योजना प्रक्रिया के प्रतिभागियों’ की सूची है – वे जो आयोजित कार्यशालाओं में शामिल हुए हैं या किसी अन्य तरीके से टीडीपी में योगदान किया है। भारत में कार्यशालाएं नयी दिल्ली, कोलकाता और सिक्किम/सिलिगुड़ी/बागडोगरा में आयोजित की गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि अन्य ‘प्रमुख क्षेत्रों’ में कोई परामर्श या कार्यशाला आयोजित नहीं किया गया जिनकी पहचान टीडीपी ने गहन पर्यटन विकास के लिए की है। इनमें पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्र जैसे असम का मानस पार्क, त्रिपुरा का पिलक क्षेत्र, भूटान की सीमा से लगता अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन शामिल है। इसके अलावा सभी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले लोगों की सूची के अनुसार बड़ी संख्या में (कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक) केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय नौकरशाही, दिलचस्पी रखने वाली औद्योगिक पार्टियां (होटल एसोसिएशन, रिजॉर्ट स्वामी और विमानन कंपनियां) और मीडिया के कुछ प्रतिनिधि (स्थानीय मीडिया के नहीं बल्कि ट्रेवल पत्रिकाओं के), शिक्षण संस्थान और स्थानीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठन/शोध संगठनों ने भाग लिया⁴⁰। सूची के अनुसार बहुपक्षीय बैंक और एडीबी के अलावा जेबीआईसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, यूएनडीपी और यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए लोगो की वास्तविक योजना के रूप में एसएसईसी टीडीपी को अस्वीकार्य करने के लिए ये खुलासा मजबूत और प्राथमिक कारण हैं।

2. समग्रता बनाम प्रतिबंध : यह कौन सा रास्ता अपना रहा है?

उपक्षेत्र विकास योजना के रूप में, स्वाभाविक रूप से, एसएसईसी, टीडीपी का जोर क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय एकीकरण संबंधी प्रतिबंध में कमी लाने पर है। भारत के संबंध में, टीडीपी में बार-बार एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया गया है और सरकारी मंत्रालयों तथा पर्यटन प्रमोटर भी इसका समर्थन करते रहे हैं। यह विचार प्रतिबंध क्षेत्र परमिट और इनर-लाइन परमिट में ढील से है जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों पर लागू होती है। उपक्षेत्रीय पर्यटन से संबंधित अपने खंड में टीडीपी इनर लाइन तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमितों पर विशेष चर्चा करता है जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड के एक हिस्से में बाहरी लोगो के लिए जरूरी है। इसका जिक्र पर्यटन में बाधा के रूप में किया गया है। इसके तहत वह आगे भारत के लिए अनुशंसा करता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाए। यहां तक कि उच्च संवैधानिक कार्यालय भी ऐसा विचार प्रदर्शित करते हैं— मणिपुर के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा में अपने संबोधन में इनर लाइन परमिट राज्य हटाने की आवश्यकता पर बल दिया जो पर्यटकों और निवेशकों के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा है⁴¹।

बहरहाल पूर्वोत्तर में इनर लाइन परमिट का मुद्दा काफी संवेदनशील है और इसमें बेरुखी से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा एसएसईसी टीडीपी का पर्यटन को बढ़ावा देने में है। ऐतिहासिक रूप से पूर्वोत्तर में ऐसे परमिट का विचार अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने 1873 में बंगाल पूर्वी सीमा कानून लागू किया था ताकि क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। ऐसा आदिवासियों के राजाओं के साथ संघर्ष

³⁹ एसएसईसी टीडीपी, परिचय, खंड सी – एप्रोच एंड मेथोडोलॉजी, एडीबी।

⁴⁰ सिक्किम में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में जिन समूहों का नाम भाग लेने वालों के रूप में लिया गया उनमें इकोटूरिज्म एंड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ सिक्किम (ईसीओएसएस), इनवायर्मेंटल इनफोर्मेशन सिस्टम फार इकोटूरिज्म (ईएनवीआईएस) केहेदी इकोटूरिज्म एंड इकोडेवलपमेंट प्रमोशन (केईईपी), कंचनजंगा कंजर्वेशन कमेटी, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म और अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट (एटीआरईई)।

⁴¹ भाषण हवाला देता है, “हमने पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरी सरकार भारत सरकार से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्यवस्था और इनर लाइन परमिट प्रणाली हटाने के लिए अनुरोध करती रहेगी। इनका न सिर्फ उद्देश्य पुराना हो गया है बल्कि संभावित निवेशकों, पर्यटकों एवं राज्य के लोगो के लिए परिहार्य मनोवैज्ञानिक बाधा बन गए हैं।” मणिपुर के राज्यपाल महामहिम श्री वेदप्रकाश मारवाह मणिपुर विधान सभा में 13.3.2000 को। स्रोत (<http://manipurassembly.nic>)

और क्षेत्र में आक्रामकता के स्थान पर 'शांति' की नीति के तहत किया गया था⁴²। आजादी के बाद भारत के संविधान में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया लेकिन एक नए दर्शन के साथ। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त रूप से आने जाने या किसी प्रदेश में निवास करने की स्वतंत्रता की गारंटी है। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इससे राज्यों को ऐसे अधिकारों पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने से नहीं रोका जा सकता। राज्य आम नागरिक या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं। इस मामले में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों, जिसकी पहचान सूची-6 क्षेत्रों के रूप की गयी है, बाहरी लोगों के आगमन या उनके आने जाने पर परमिट लगा सकते हैं⁴³। हाल के वर्षों में, क्षेत्र में राजनीतिक संघर्षों में परमिट मुद्दे को और ज्यादा विवादास्पद बना दिया है। इसमें स्थानीय विचारों में भी मतभेद है। मिजो लोगो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इनर लाइन परमिट समाप्त करने का विरोध किया और दलील दी कि उनकी अनोखी पहचान एवं संस्कृति की रक्षा के लिए यह अहम है⁴⁴, वहीं उत्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) ने मेघालय सरकार द्वारा असम के लोगो पर इनर लाइन परमिट लगाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उसका कहना था कि इससे दो राज्यों के लोगो के बीच ऐतिहासिक एवं भावनात्मक सौहार्द प्रभावित होगा⁴⁵। इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इनर लाइन व्यवस्था से छोड़छाड़ में हिचक रही है। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्यवस्था में ढील दी गयी है लेकिन बांग्लादेश से चकमा और हाजोंग शरणार्थियों के भारी संख्या में आने के मुद्दे पर वह हिचक रही है।⁴⁶

स्पष्ट है कि इनर लाइन परमिट का मुद्दा पर्यटन से बड़ा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें हटाने का सुझाव देना क्षेत्र की भौगोलिक-राजनीतिक, जातीय और सामाजिक संवेदनशीलता के मद्देनजर तर्कहीन और अत्यधिक संवेदनहीन होगा।

3. प्रमुख क्षेत्र – विकासशील अंतः क्षेत्र?

टीडीपी में सुझाव लिए गए प्रमुख कार्यक्रमों में एक 'प्रमुख क्षेत्र कार्यक्रम' है जहां पर्यटन में उपक्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष नजर है। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को कम से कम दो एसएसएससी राज्यों में शामिल होना है और उनमें इकोटूरिज्म तथा बौद्ध सर्किट विकास की संभावना होनी चाहिए। ऐसे 11 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी है –

- बरदिया और सुकलपनता (नेपाल में) से दुधवा राष्ट्रीय पार्क (उत्तर प्रदेश, भारत)
- बौद्धस्थल – लुंबिनी से भारत तक
- कंचनजंगा, सिक्किम और दार्जिलिंग
- पूर्वी सिक्किम से पश्चिमी भूटान
- सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र⁴⁷ (पश्चिम बंगाल, भारत – बांग्लादेश)

⁴² इतिहासकारों के अनुसार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873 से ब्रिटिश भारत के लिए एक नयी आंतरिक सीमा बन गयी। इससे उपनिवेशी राज्य को असम की तराई में एक इनर लाइन स्थापित करने का मौका मिला। वहां की सीमा के आगे लोगों को अपने मामलों से खुद ही निबटने का मौका मिला तथा सीमांत अधिकारी राजनीतिक मामलों में सलाह योग्य भूमिका तक ही हस्तक्षेप करते। यह नियमन अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ 1874 एवं फ्रंटियर ट्रैक्ट रेग्यूलेशन एक्ट ऑफ 1980 द्वारा शामिल होना था। इस एक्ट ने नागरिक एवं अपराधिक प्रक्रिया, संपत्ति व हस्तांतरण कानून के नियम एवं अन्य अनुपयुक्त कानूनों एवं दायरे में आने वाले इलाकों को निकाल बाहर करने की अनुमति दी; जयिता शर्मा, स्रोत : <http://www.india-seminar.com/2005/550/550jayeeta sharma.htm>

⁴³ वी एन शुक्ला के विश्लेषण में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 डी के अनुप्रयोग पर रोक का एक आधार 'जनजातीय लोगों के हितों' की रक्षा करना है। इसे संविधान में शामिल किया गया ताकि भारत के मूल जनजातीय लोगों की रक्षा की जा सके जो असम में रह रहे हैं। ऐसे जनजातीय लोगो के इलाकों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए राज्य को अधिकार संपन्न बनाना जरूरी था। जनजातीय लोगों के अन्य वर्गों के लोगो के साथ अनियंत्रित मेलजोल से अवांछनीय प्रभाव होने की आशंका है। कन्सीट्यूशन आफ इंडिया : वीएन शुक्ला, महेन्द्र पी सिंह द्वारा संशोधित, 10वां संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी, 2001

⁴⁴ 1993 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक कथित बयान कि इनर लाइन परमिट रद्द किया जा सकता है, का पूरे क्षेत्र में भारी विरोध हुआ। इस कदम के विरोध में छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं की आगुवाई में तत्काल एक संयुक्त कार्यसमिति गठित की गयी। इंडियाज नार्थईस्ट रिसर्जेंट: एथनिसिटी, इनसर्जेंसी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, बी जी वर्गीज, कोणार्क पब्लिशर्स प्रा. लि., 1996

⁴⁵ इनर लाइन परमिट को लेकर उत्फा की चिंताएं <http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/7434/freedom0204.htm> - ULFA's%20concern%20about%20

⁴⁶ <http://www.achrweb.org/countries/india/arunachal/SCJAP0703.htm>

⁴⁷ सुंदरबन के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पूर्व में एक इकोटूरिज्म योजना इसकी निरंतरता के आधार पर स्थानीय समुदायों के अभियान एवं विरोध पर रद्द की जा चुकी है। 2003 में, देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक सहारा समूह ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के लिए 540 करोड़ रुपए की इकोटूरिज्म परियोजना पेश की। (सहारा समूह पर्यटन उद्योग के आलावा

- पहाड़पुर (नेपाल) से सिलिगुड़ी और बागडोगरा
- मैनामती (बंगलादेश) से त्रिपुरा
- पूर्वी भूटान से अरुणाचल प्रदेश
- भारत के पूर्वोत्तर राज्य
- काठमांडू हब

प्रमुख क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए कुल 33 परियोजनाओं की अनुशंसा की गयी है। इनमें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़कों के किनारे सुविधाएं स्थापित करने, हवाई अड्डा आधुनिकीकरण और इकोटूरिज्म रणनीति (विशेष रूप से सुंदरबन, मानस, पश्चिमी सिक्किम) के लिए, और आगंतुक प्रबंधन योजनाओं पर जोर दिया गया है। कुछ विशेष परियोजनाओं में अरुणाचल में एडवेंचर ट्रेकिंग, हस्तकला कार्यक्रम और सुंदरबन में समुदाय आधारित केंद्र आदि शामिल हैं। टीडीपी में कहा गया है कि एडीबी और पर्यटन कार्यसमूह प्रमुख क्षेत्रों में अपनी दिलचस्पी कायम रखेंगे। लेकिन परियोजनाओं के कार्यक्रम का जिम्मा राष्ट्रीय सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाओं में कुछ का विकास तत्काल व्यवहार्य है जबकि अन्य के लिए परमिट प्रक्रियाओं और सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी।

टीडीपी में पहचान किए गए ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थापना का एक तात्कालिक प्रतिकूल असर वहां गहन विकास होना है। यह सिर्फ पर्यटन परियोजनाओं में ही नहीं बल्कि सड़कों, हवाई अड्डों के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास में भी होगा। पहचान किए गए लगभग सभी क्षेत्र पारिस्थितिकी तथा सामाजिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हैं। जिनकी वहन क्षमता पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे के लिए स्थान तथा संसाधनों के असीमित उपयोग को कायम नहीं रख सकती⁴⁸। भारतीय पर्यटन परिदृश्य में कुछ क्षेत्रों को विशेष जोन बनाने या इस मामले जैसा प्रमुख क्षेत्र बनाने का विचार पूरी तरह नाकाम रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1992 में बेकल, महाबलीपुरम, कोवलम और सिंधु दुर्ग की विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में पहचान की गयी थी लेकिन वे अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग-थलग, दोहन एवं निवेश केन्द्र बन गए। इससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और समुदायों का विस्थापन हुआ जबकि मूल लक्ष्य हवा हो गया। ऐसे केन्द्रों तथा आसपास के क्षेत्रों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक खाई बढ़ गयी और गोवा, बाली तथा हवाई में ऐसा देखा जा सकता है। टीडीपी के “प्रमुख क्षेत्र कार्यक्रम” में इन गलतियों के दुहराने के पर्याप्त आसार हैं। खासकर भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में। यह कहना जल्दबाजी होगा कि जो भी तरीके अपनाए जाते हैं या संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, उनसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या आसपास के क्षेत्रों पर कोई असर नहीं छोड़ेगा।

4. इकोटूरिज्म पहल : धुंआ बढेगा

दुनिया भर में इकोटूरिज्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा नया मंत्र माना गया है जो पर्यावरण के अनुकूल है तथा इसमें नुकसान नहीं है। दुर्भाग्य से इसे प्राकृतिक पर्यटन, सुरक्षित विचार और पर्यावरण जोन में पर्यटन का पर्याय बना दिया गया है। इस कारण पर्यटन विकास का प्रकार लगभग मुख्य धारा का है, इसे ऐसे पर्यटन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है जो कम असरकारी तथा पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल है (इक्वेसंस, 1999)।

मनोरंजन, खुदरा कारोबार, नगर विमानन जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं)। निवासियों पर असर, संरक्षण मुद्दों और मछली मारने के अपने अधिकारों को लेकर समुदायों के विरोध के बीच सरकार ने जनवरी 2004 में इंडीग्रेटेड सहारा टूरिज्म सर्किट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जो कोलकत्ता, सागर, फ्रेजरगंज, एल-प्लाट, कैरवली, झारखली क्षेत्रों की 868 एकड़ भूमि में फैला था। परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक समय लिखा था – “देश के सबसे बड़े डेल्टा को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए सुंदरबन परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए परियोजना में विभिन्न निवास सुविधाएं (काटेज एवं बोट हाउस सहित) आधुनिक खेल, स्पा, स्वास्थ्य केंद्र, क्लब हाउस और कैसिनो, अत्याधुनिक संचार एवं यातायात प्रणाली आदि भी होंगे। अगर इसका क्रियान्वयन होता तो पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान होने के साथ ही कई मछली मारने वाले पारंपरिक गांवों को विस्थापित होना पड़ता या उनकी पहुंच पानी तक नहीं होती और वे आर्थिक रूप से असहाय हो जाते। स्थानीय समुदायों और सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ लंबे समय तक अभियान चलाया और अंततः मार्च 2005 में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया।

⁴⁸ पर्यावरण वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता है जिसमें उत्पादकता, स्वीकार्यता तथा नवीनीकरण की योग्यता कायम रह सकती है। पर्यटन वहन क्षमता विशेष प्रकार की पर्यावरण वहन क्षमता है और यह पर्यटन गतिविधि तथा विकास के संदर्भ में जैव भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। इसमें पर्यटकों की अधिकतम संख्या तथा क्षेत्र में संभव बुनियादी ढांचे के बारे में जिक्र किया जाता है। अगर इसे पार कर लिया जाए तो क्षेत्र के पर्यावरण संसाधनों का क्षय, आगंतुकों की संतुष्टि में कमी और समाज संस्कृति व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका बन जाती है।

टीडीपी ने एसएसईसी उपक्षेत्र में 'संस्कृति एवं प्रकृति पर आधारित इकोटूरिज्म का विकास' शीर्षक से कई परियोजनाओं को पहचान की है जिन्हें बढ़ावा दिया जाना है। प्रस्तावित गतिविधियों में ट्रेकिंग, नदी आधारित पर्यटन और एडवेंचर पर्यटन शामिल हैं। इनमें से कुछ पूर्वोत्तर के लिए उपयुक्त नहीं हैं और क्रियान्वयन करने पर पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही एक प्रस्ताव है – गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का उपयोग नदी पर आधारित गतिविधियों जैसे नौकायन के लिए करना। नौकायन पर्यटन को दुनिया भर में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला पर्यटन माना जाता है। कैरिबियन द्वीपसमूह तथा मध्य अमेरिका में कई नौकायन गंतव्य हैं जो प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह पोतो, उनके अवशिष्ट पदार्थों, तेल रिसाव तथा विभिन्न प्रकार के जैविक तथा अजैविक कचरे के कारण सामने आया है⁴⁹। आर्थिक पहलु के लिहाज से भी नौकायन पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए बहुत लाभप्रद नहीं रहा है। क्योंकि क्रूज पैकेज पूरी तरह से टूर आपरेटर्स द्वारा संचालित किए जाते हैं और थल आधारित पर्यटन से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं (कैरिबियन टूरिज्म आर्गनाइजेशन, 2004)। नदियों में क्रूज से और अधिक प्रतिकूल असर हो सकता है क्योंकि नदियों के तट पर जहां पोत रुकते हैं, वहां अधिक प्रदूषण हो सकता है। इससे मछली पकड़ने पर भी प्रतिकूल असर हो सकता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इन सब के मद्देनजर किसी भी प्रकार के क्रूज गतिविधि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जा सकता और यह पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र के लिए बुरा विचार साबित हो सकता है। इनके अलावा राफ्टिंग और पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर पर्यटन का भी प्रस्ताव है जिनसे जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है।

प्रस्तावित गतिविधियों में क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों की ओर भी जोर दिया गया है ताकि पशु एवं वनस्पति संबंधी विविधताओं को रेखांकित किया जा सके। वन्यजीवन पर्यटन के विचार को सबसे पहले अफ्रीका के सहारा क्षेत्रों में खासकर केन्या, तंजानिया और यूगांडा में बढ़ावा दिया गया। बाद के वर्षों में इसके प्रसार का असर महसूस किया जाने लगा तथा मूल मासई लोगों का अपने पारंपरिक इलाकों से लगातार विस्थापन हुआ। इससे वन्यजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनके निवास के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास तथा पर्यटकों के लगातार आगमन का दबाव भी महसूस किया गया (केआईपीपीआरए, 2002)⁵⁰। एसएसईसी उपक्षेत्र में राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों की ओर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रस्ताव से भारत के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा होने की आशंका बनी हुई है। पहले से ही ऐसी खबरें हैं कि मानस राष्ट्रीय पार्क को वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में पेश किया जा रहा है⁵¹। आगंतुकों की संख्या एवं ऐसे पार्कों में अंदर या उनके बाहर पर्यटन सुविधाओं के नियमन से असर को कम किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह टीडीपी की प्राथमिकता नहीं है क्योंकि वह ऐसे मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं देता।

शोध से खुलासा होता है कि पिछले 20 वर्षों में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई है। इसकी वजह लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना, खनन, मिलें और कागज उद्योग के अलावा उग्रवाद विरोधी प्रयास आदि हैं⁵²। वनों के घटने का असर क्षेत्र के पशु एवं वनस्पति पर भी हुआ है। इसके अलावा मौसम की स्थिति, फसल पद्धति, स्थानीय लोगों के विकल्पों के प्रभावित होने के साथ ही बाढ़ एवं भूस्खलन की विभीषिका भी बढ़ी है⁵³। क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं से वनों के क्षेत्रफल में कमी आएगी और सावधानी पूर्वक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तो टीडीपी की प्रस्तावित पर्यटन गतिविधियां गलत साबित होंगी।

टीडीपी साउथ अफ्रीका सस्टेनेबल टूरिज्म फोरम के नए विचार के साथ सामने आया है जो इकोटूरिज्म में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों के बीच पुल का काम करेगा। मीकांग टूरिज्म फोरम की तर्ज पर तैयार, एसएसटीएफ का उद्देश्य इकोटूरिज्म में संयुक्त नियोजन एवं विपणन के लिए मंच के रूप में काम करना, क्षेत्रीय पहलों के बीच समन्वय में मदद करना तथा इकोटूरिज्म केन्द्र के रूप में क्षेत्र को पेश किए जाने को गौरवान्वित करना है। एक बार फिर फोरम में समुदायों के प्रतिनिधि को कोई स्थान नहीं मिला है। पर्यटन के समर्थक शायद ही स्वीकार करें कि

⁴⁹ क्रूज पोतों के प्रभाव के विस्तृत अध्ययन के लिए देखें – 'क्रूज इंडस्ट्री बेस्ड चैलेंजेज फेसिंग कैरिबियन डेस्टिनेशंस' केनेथ के आर्थर्ली बारबेडेंस पोर्ट अथॉरिटी।

⁵⁰ पर्यावरण पर पर्यटन के विस्तृत अध्ययन के लिए देखें – 'इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म आन दि एनवायरनमेंट इन केन्या : स्टैट्स एंड पालिसी' केन्या इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस, 2002।

⁵¹ टूरिज्म होप्स फॉर मानस : दि टेलीग्राफ, फरवरी 13, 2006।

⁵² 'लैंडस ऑफ अली डॉन – नार्थ ईस्ट ऑफ इंडिया – रमेश भट्टाचार्य, रूपा एंड कंपनी – 2002 के अध्याय 'फेडिंग फॉरेस्ट्स नार्थईस्ट इन ट्रबल' से

⁵³ वही

इकोटूरिज्म सिर्फ पारिस्थितिकी के अनुकूल कदमों और पर्यावरण पर कम असर की ही बात नहीं करता बल्कि इसमें लाभ में समान हिस्सेदारी के अलावा सतत पर्यटन में सहभागिता तथा समान पहुंच संबंधी सिद्धांत भी शामिल हैं। हालांकि टीडीपी ने कहीं-कहीं पर्यावरण के अनुकूल सतत पर्यटन की आवश्यकता स्वीकार की है लेकिन उसने लाभ में हिस्सेदारी और वास्तविक सामुदायिक सहभागिता के पहलुओं को बढ़ावा नहीं दिया है।

5. पर्यटन में लाभ हिस्सेदारी तथा सहभागिता – सिर्फ दिखावा

टीडीपी परियोजनाओं में समुदाय की सहभागिता के बारे में प्रस्तावित परियोजनाओं के उद्देश्य या क्रियान्वयन सिद्धांत में बहुधा जिक्र करता रहा है। लेकिन व्यवहार में, इस विशाल योजना में समुदायों की सार्थक भूमिका कठिन नजर आती है। जब नीतियां या योजनाएं तैयार की जाती हैं, उद्योगों की पहल से, इसे समुदायों के सामने तब लाया जाता है जब अनुमति की दरकार हो, यह 'सामुदायिक सहभागिता' का मजाक है। पर्यटन परियोजनाएं समुदायों के लिए तब अधिकतम सार्थक होती हैं जब उनकी ही पहल हो और उनकी शर्तों पर तथा उनकी जरूरतों एवं प्राथमिकता के अनुरूप हो। ऐसे पहलों का उदाहरण सामने है और विश्व के कई हिस्सों में ये सफलतापूर्वक चल रहे हैं लेकिन एसएसईसी पर्यटन संबंधी एडीबी की विशाल योजना में उनका जिक्र नहीं है। ऐसा एक उदाहरण क्षेत्र में ही उपलब्ध है। नगालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गांव खोनोमा में अधिकतर खेती से जुड़ा समुदाय है। उन्होंने अतिरिक्त आमदनी के लिए पर्यटन को अनुपूरक स्रोत बनाने में दिलचस्पी प्रदर्शित की। गांव की पारंपरिक स्वशासन संस्था ग्राम परिषद में पर्यटन के बारे में इसके रूप, सीमा, उद्देश्य एवं नियमों के साथ विचार विमर्श किया गया। पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के पहले पर्यावरण असर का विस्तृत आकलन किया गया। अध्ययन में समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसमें पर्यटन में संभावनाओं पर विचार करने के अलावा नियामक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया ताकि गांव में पर्यटन लंबे समय तक कायम रह सके। (केटीडीबी, 2004)

पर्यटन में लाभ हिस्सेदारी में सिर्फ आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी फायदा ही शामिल नहीं है बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ भी शामिल हैं और समुदायों को पर्यटन में शामिल कर इसे हासिल किया जा सकता है (एनबीएसएजी 2002)⁵⁴। विकासशील दुनिया के पर्यटन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पर्यटन में बढ़ी संख्या का मतलब हमेशा अधिक आमदनी नहीं है क्योंकि लाभ समुदाय स्तर तक नहीं पहुंचता (इक्वेशंस, 2004)। इस संबंध में टीडीपी की कोई ठोस योजना नहीं है कि पर्यटन परियोजनाओं से होने वाली आय को किस प्रकार क्षेत्र के गरीब समुदायों के बीच वितरित किया जाएगा। एक साधारण दलील पेश की गयी है कि बौद्ध सर्किट के विकास तथा अन्य उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लंबे समय तक ठहरने के लिए प्रेरित होंगे, दूरदराज एवं निर्धन क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे इस प्रकार पर्यटन से फायदा बढ़ेगा। यह लाभ-हिस्सेदारी के अर्थ का अतार्किक एवं अपर्याप्त मतलब है और इसे किस प्रकार हासिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह एसएसईसी में पर्यटन विकास के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाने की वकालत करता है। परिभाषा से निजी क्षेत्र पहल में लाभ हिस्सेदारी का सिद्धांत शामिल नहीं है जो उनके लाभ के उद्देश्य का विरोधीभासी हो। अगर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पर जोर दिया जाता है तो एसएसईसी टीडीपी को यह निश्चित तौर पर स्पष्ट करना होगा कि लाभ-हिस्सेदारी का उद्देश्य हासिल करने की उम्मीद कैसे पूरी होगी⁵⁵।

6. विनियमन तथा निरंतरता

पर्यटन देश के उन सेक्टरों में से है जो सर्वाधिक अनियंत्रित हैं और उसके बारे में धारणा है कि यह नुकसान रहित उद्योग है। इससे, इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए लाभ की स्थिति बन जाती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक उदारीकरण के साथ पर्यावरण नियमन में ढील दी गयी उन बाधाओं को दूर कर दिया गया जो निवेश में बाधा पहुंचाते थे। टीडीपी बिना यह समझे अपना दर्शन प्रदर्शित करता है कि पर्यटन का नियमन या उस संबंध में

⁵⁴ इकोटूरिज्म के संदर्भ में लाभ हिस्सेदारी के विस्तृत अध्ययन के लिए देखें सब थीमैटिक बायोडायवर्सिटी एंड टूरिज्म, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की कार्ययोजना के लिए, इक्वेशंस द्वारा 2002 में तैयार।

⁵⁵ एडीबी जैसे एमडीबी के लक्ष्यों से संबंध में न्यूरिना बिडाग्डो ने लिखा है, 'निजी क्षेत्र विकास रणनीति के साथ कम से कम दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो चिंतित करने वाले हैं। पहला— निजी क्षेत्र विकास और निर्धनता में कमी के बीच कड़ी से संबंधित लाभ अवधारणा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि एडीबी अन्य एमडीबी के साथ दावा करता है कि गरीबी में कमी उसका प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य है। दूसरा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सहभागिता है जिन पर एडीबी के सभी कार्यों में ध्यान रखा जाना चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ के कार्य में भी.....। एडीबी निजी क्षेत्र विकास रणनीति में जवाबदेही मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। जब उत्पाद एवं सेवाओं की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित होती है तो उसकी जवाबदेही कायम रहे।' ए क्रिटिक ऑफ दि एएनडी प्राइवेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी न्यूरिना बिडाग्डो, क्रिएटिंग पोवर्टी, दि एडीबी इन एशिया, फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ, 2000।

सभी गतिविधियां पूर्वोत्तर में सतत विकास के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी हुयी हैं⁵⁶। संविधान ने इस वजह के अलावा अन्य कारणों से ही क्षेत्र की पहचान, सूची-6 क्षेत्र के रूप में और देश के बाकी हिस्से से अलग योजना की अनुमति दी। इस सिद्धान्त में ग्राम परिषद की भूमिका जैसी योजना की अनुमति दी। इस सिद्धान्त में ग्राम परिषद की भूमिका जैसी पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का ख्याल रखते हुए उनका सम्मान किया गया है। अभी पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया जा रहा है और वहां गतिविधियों एवं कोष के जरिए गहन विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन आय का सतत स्रोत और आजीविका का विकल्प बन सकता है लेकिन इसे नियंत्रित एवं नपे तुले कदमों के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। पर्यटन परियोजनाओं की अचानक बाढ़ आने से काफी बड़ी मात्रा में निवेश होगा और स्थानीय पर्यावरण तथा समुदायों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा कि वे इसके अभ्यस्त हो सकें और ऐसे निवेश का फायदा उठा सकें। विनियमन भी अनिवार्य है ताकि स्थानीय कानूनों, जो क्षेत्र के संदर्भ में विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं, पर अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थोपे जा सकें। इसके अलावा पर्यटन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- पर्यटन में विनियमन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं— औद्योगिक गतिविधियों का विनियमन, जैसे एक क्षेत्र में होटल/रिजॉर्ट की संख्या सीमित करना या टूर समूहों की संख्या पर नजर रखना। किसी स्थान पर पर्यटकों की संख्या को प्रतिबंधित करना या संरक्षित क्षेत्र में वाहनों की संख्या सीमित करना।
- पर्यटन से स्थानीय लोगों को फायदा के लिए विनियमन, उदाहरण के लिए टूर गाईड या होटल स्टाफ या पर्यटन प्रतिष्ठानों में स्वामित्व में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव रोकने के लिए कचरा प्रबंधन प्रणाली क्षमता अध्ययन करना, जन सुनवाई, पर्यावरण असर आकलन के लिए विनियमन।
- भूमि, वन, जलाशयों में स्थानीय लोगों का स्वामित्व कायम रखना तथा संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

टीडीपी में, इनमें से किसी या विनियमन के विचार का जिक्र नहीं मिलता है क्योंकि इसे निवेश में बाधक माना जाता है। इसे पर्यटन में निजी भागीदारी के लिए अवरोधक माना जाता है। यह देश में जारी नियमन हटाने के दौर का समर्थन करता है जहां पर्यावरण, परिस्थितिकी वन्य जीवन और पर्यटन से संबंधित कई कानूनों की 'विशेष व्यवस्था' की जा रही है। कुछ स्थानों पर टीडीपी कहता है कि प्रस्तावित गतिविधियां नियंत्रित होंगी और न्यूनतम असर सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन उसका रुख विरोधाभासी दिखता है क्योंकि वह निजी क्षेत्र के लिए नियमन हटाने की लगातार मांग करता रहा है। नियोजकों और नीति-निर्माताओं को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि विनियमन की अनुपस्थिति में पूर्वोत्तर में सतत पर्यटन हासिल नहीं की जा सकती — यह ऐसी वास्तविकता है जिससे सतत पर्यटन को लेकर सवालिया निशान लगते हैं जिसकी वकालत टीडीपी लगातार करता रहा है।⁵⁷

7. टीडीपी का वित्तपोषण—बहुपक्षीय बैंकों के लिए आकर्षक विकल्प

टीडीपी ने अपने क्रियान्वयन के लिए 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, करीब 3375 करोड़ रुपए, खर्च होने की बात की है। सुझाए गए वित्तपोषण विकल्पों में राष्ट्रीय सरकार के संसाधनों को भी शामिल किया गया है। इसके बारे में टीडीपी का मानना है कि प्रस्तावित योजना के कई भाग लागू करने में वह सक्षम नहीं है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और पहलू जो (उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था जैसी) सुधार कर सकें, तथा राष्ट्रीय बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी बात की गयी है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से टीडीपी ने राष्ट्रीय सरकारों पर टीडीपी के पहलुओं को लागू करने के

⁵⁶ उदाहरण के लिए खोनोमा गांव में स्थानीय पर्यटन विकास बोर्ड तथा ग्राम परिषद का स्पष्ट विचार है कि गांव में पर्यटक विकास के लिए विनियमन जरूरी है। उसका कहना है कि खोनोसर में कई पारंपरिक कानून, नियम हैं जिनमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। ये पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से भी जुड़े हुए हैं। पर्यटन शुरू किए जाने का पर्यावरण पर विभिन्न तरह से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में गांव के लिए नए नियम बनाने जरूरी हैं जो नयी स्थिति तथा गांव की सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण स्थिति के लिहाज से उपयुक्त हों। गांव को पर्यटन गतिविधियों पर नजर रखनी होगी तथा उसकी समीक्षा करनी होगी। विभिन्न पक्षों द्वारा स्वयं पहल कर आचार संहिता स्वीकार करनी होगी। संक्षेप में शिक्षा एवं स्वयंसेवी दिशानिर्देश तथा आचार संहिता की आवश्यकता है। इसके बाद कानून और अधिकारियों द्वारा उनका सख्ती से पालन करवाने की आवश्यकता है। केटीडीबी 2004

⁵⁷ अनीता प्लेमर ने मीकांग में एडीबी के पर्यटन विकास मॉडल की आलोचना में भी ऐसे ही सवाल किए हैं। वह कहती हैं “खासकर निर्धन देशों में पर्यटन की आर्थिक व्यवहार्यता को निरंतरता के लिए प्रमुख योग्यता के रूप में देखा जाता है। ऐसे में पुराने प्रश्न कि पर्यटन से वास्तविक फायदा किसे होता है — को वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के संदर्भ में फिर से उठाने की आवश्यकता है। तीसरी दुनिया में पर्यटन अधिकतर विदेशी उद्योगों के हितों के लिए होता है और गंतव्य देशों के आर्थिक लाभ के बारे में काफी अधिक आकलन कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय आर्थिक लाभ में वृद्धि के लिए सतत पर्यटन और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण का घोषित लक्ष्य का पूरा होना कठिन है।”

लिए जोर दिया है। उसका कहना है, “पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग एक परस्पर लाभप्रद अवसर है.....। इस मौके के लिए डोनर की सहायता की आवश्यकता है। डोनर एजेंसियों के साथ विमर्श जारी रहनी चाहिए। मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की एसएसईसी बैठक में डोनर समुदाय के प्रतिनिधियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए – पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग का महत्व बताने के लिए तथा उचित परियोजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करने एवं लागू करने में डोनरों की भागीदारी पर जोर देने के लिए।” स्पष्टतया टीडीपी दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों के लिए कर्ज तथा अन्य प्रकार के भुगतान के जरिए विकास सहायता की खातिर काफी सम्भवनाएं बनाता है। टीडीपी द्वारा पहचान की गयी 23 परियोजनाओं में सात में एडीबी तथा जेबीआईसी ने आंशिक या पूर्ण रूप से दिलचस्पी प्रदर्शित की है। इन परियोजनाओं में बागडोगरा टूरिज्म गेटवे एंड हब प्लानिंग स्टडी, एशियन हाइवेज लिंकेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग फार एनटीओएस, टीए फार दि इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन ट्रेकिंग इन हिमालयन, फुटस्टेप्स ऑफ लार्ड बुद्धा पहल शामिल हैं⁵⁸। टीडीपी अन्य डोनरों की नीति में बदलाव की सिफारिश करता है ताकि पर्यटन के लिए सीधे तौर पर अधिक कोष उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित गतिविधियों से समुदायों को फायदा हो या नहीं, टीडीपी एमडीबी के लिए अवसरों के द्वार खोल देता है।

निष्कर्ष

एसएसईसी टीडीपी ऐसे समय आया है जब पूर्वोत्तर क्षेत्र कई उन परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव से गुजर रहा है जिन्हे सरकार ने शुरू किया और एमडीबी ने वित्तपोषण किया है। पर्यटन क्षेत्र को विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप देखा जा रहा है जिसमें सभी संबंधित पक्षों के लिए लाभ होने की बात की गयी है। एसएसईसी के तहत पर्यटन कार्यसमूह जिस तेजी से प्रगति कर रहे हैं, वह निश्चित संकेत है कि पूर्वोत्तर में कुछ गंभीर पर्यटन निवेश होना है। इससे क्षेत्र में मौजूदा एवं प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के असर में वृद्धि होने की आशंका बन जाती है। लेकिन जैसा इस पेपर में रेखांकित किया गया है, – कई नियोजित गतिविधियां तथा योजना तैयार करने की प्रक्रिया खुद ही वास्तविक सामुदायिक भागीदारी एवं निरंतरता से दूर हो गयी हैं। एसएसईसी के पर्यटन उद्योगों में वही दुखद प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है जो पूर्वोत्तर के विकास के नाम पर प्रस्तावित है – विकास का ऐसा माडल जो अपने संदर्भ एवं माहौल से अलग है। विकास गुरुओं, राजनेताओं और एमडीबी का मानना है कि पूर्वोत्तर में परेशानी का वक्त भले ही रहा हो लेकिन अब नया सबेरा दिख रहा है – विकास, प्रगति और संपन्नता का। आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे विशाल विकास संदर्भ में स्थानीय लोग कहीं नहीं दिखते। इससे विचारोत्तेजक निष्कर्ष निकलता है – “पूर्वोत्तर की सीमा में जो लोग रह रहे हैं, वे भारत के बाकी हिस्से के सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो व्यापारी, सैनिक और राजस्व अधिकारी हैं। उन्हें कोई डाक्टर या विकास कर्मी नहीं दिखता जिनकी उन्हें बेहद आवश्यकता है... वे उन्हीं ही देखते हैं जिनकी आवश्यकता सबसे कम है...” (भट्टाचार्य – 2002) उम्मीद है कि एडीबी हवाई किले बनाना बंद करेगा और जमीनी सच्चाई से रूबरू होगा।

⁵⁸ एसएसईसी टीडीपी डेवलपमेंट मैट्रिक्स एंड एक्शन प्लान

एडीबी का नवीनतम पर्यटन अवतार : सभी लोगों व निवेशकों के लिए खुला मौका

व्यापक पर्यटन संरचना विकास परियोजना के माध्यम से भारत को
दिए जाने वाले एडीबी के नवीनतम पर्यटन विशेष कर्ज पर विचार

सौपर्ण लाहिरी, मार्च 2008

पर्यटन क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार के बीच भागीदारी दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम तक सीमित रही है जहां भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के अलावा भारत प्रमुख देशों में शामिल है।

एडीबी प्रस्तावित व्यापक पर्यटन संरचना विकास परियोजना (आईटीआईडीपी) के माध्यम से पहली बार भारत में पर्यटन विकास के लिए अलग से कर्ज देने पर विचार कर रही है। यह प्रक्रिया भारत सरकार के अनुरोध पर की जा रही है और इसकी तकनीकी सहायता रिपोर्ट (टीए) तैयार हो रही है।

शुरुआत

एडीबी निदेशक मंडल द्वारा यूनाइटेड किंगडम सरकार से वित्तपोषित परियोजना संसाधन और क्षमता विकास के लिए एक तकनीकी सहायता समूह (टीएसी) को 30 जून 2006 को मंजूरी दी गई थी। भारत में विकास परियोजनाएं तैयार करने में क्षमता और समयबद्धता बढ़ाकर एडीबी के क्रियाकलापों से परिणाम को बढ़ावा देने के लिए टीएसी का डिजाइन किया गया था। टीएसी में एक घटक तकनीकी सहायता (सीटीए) के तौर पर पर्यटन संरचना विकास अध्ययन को शामिल किया गया था।

एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक ने सीटीए के क्रियान्वयन व्यवस्थाओं एवं लक्ष्य को 18 दिसम्बर 2006 को मंजूरी दी।

इंडिया कंट्री स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम अपडेट 2006 में एडीबी की प्रस्तावित कर्ज के अंतर्गत पर्यटन संरचना विकास 2008 के लिए कर्ज दिया जाना शामिल है। सीटीए द्वारा ऐसी परियोजना तैयारी तकनीकी सहायता आधार प्रदान करने की आशा थी जिससे 2008 में एडीबी के संभावित वित्तपोषण के लिए सरकार को विकासशील पर्यटन संरचना के लिए निवेश पैकेज तैयार करने में मदद मिले। एडीबी की संभावित वित्तपोषण के लिए व्यवहार्य पर्यटन संरचना विकास परियोजना तैयार करने में भारत सरकार द्वारा एडीबी से मदद का अनुरोध करने पर सीटीए हाथ में लिया गया।

व्यापक पर्यटन संरचना विकास परियोजना?

परियोजना के नाम से ही कई सवाल उठते हैं; इनमें से सबसे प्रमुख है कि इसे “व्यापक” क्यों कहा जा रहा है। परियोजना दस्तावेज के अनुसार, सीटीए का इरादा था कि सरकार एक पर्यटन संरचना रोड मैप विकसित करे जो कि उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन संरचना विकास के लिए एक एकीकृत नियोजन ढांचा और संस्थागत व नियामक हस्तक्षेपों के लिए सिफारिश प्रदान करे। अध्ययन का गठन 10 साल के लिए नियोजन संभावना के साथ पर्यटन विकास रोड मैप तय करने के लिए और (क) देश की पर्यटन बंदोबस्त एवं ढांचागत आवश्यकताएं आकलन करने (ख) उच्च-प्राथमिकता वाले पर्यटन सर्किट एवं ढांचागत आवश्यकताओं का चयन करने, और (ग) संस्थागत व नियामक व्यवस्था व क्षमता आकलन करने और टिकाऊ व सामाजिक आधार पर पर्यटन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए किया गया था।

टीए, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है, उसका उद्देश्य पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ एवं सामाजिक रूप से समावेशी तरीके से पर्यटन क्षेत्र की प्रदर्शन क्षमता में सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार को मदद करना है। ताकि इससे ज्यादा पर्यटक आएँ और अधिक समय तक ठहरें। पर्यटन से व्यापक आमदनी और लाभ हो। पर्यटन के महत्व के प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थलों का बेहतर प्रबंधन हो। टिकाऊ एवं सामाजिक रूप से समावेशी पर्यटन के लिए प्रस्तावित ढांचा एडीबी के मौजूदा गरीब-अनुकूल एवं व्यापक क्षेत्रीय विकास संरचना में फिट बैठती है जिसमें गरीबी निवारण और समुदायों के शामिल होने व भागीदारी को काफी महत्व दिया गया है।

दूसरा सवाल जैसे परियोजना के दायरे में ही परिवहन व संप्रेषण, सड़क, राजमार्ग, जल आपूर्ति, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों एवं उप-क्षेत्रों के शामिल होने से सम्बन्धित है। प्रस्तावित परियोजना के तहत कुछ राज्यों में अग्रलिखित निवेश होने की संभावना है : (क) पर्यटन के लिए पहुंच और संपर्क ढांचे, उदाहरणतया सड़क, परिवहन, एयरपोर्ट आदि, (ख) गंतव्य सेवा ढांचे व सेवाएं, उदाहरणतया सीवेज, पानी, ठोस कचरा प्रबंधन, (ग) प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं सहयोगी ढांचे व सेवाएं, (घ) अन्य पर्यटन सुविधाएं एवं सेवाएं (उदाहरणतया पर्यटन सेवा केन्द्र, पर्यटन जानकारी सुविधाएं) और प्रमुख गंतव्य व स्थल मार्ग पर सुविधाएं (ठहराव केन्द्र आदि) एवं (च) पर्यटन से स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए समुदाय आधारित पर्यटन योजनाओं एवं अवधारणाओं को बढ़ावा देना।

एडीबी को संप्रेषण व परिवहन संरचना, जल आपूर्ति, सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन की एक परियोजना के लिए 290 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता क्यों करनी चाहिए जबकि ऐसे क्षेत्र एवं उप-क्षेत्र सम्बन्धित परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं या की जानी हैं और एडीबी द्वारा ही वित्तपोषित हैं?

विशालकाय और विवादास्पद जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) के अलावा बहुत सारी शहरी विकास परियोजनाएं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड एवं उत्तर-पूर्व राज्यों में या तो क्रियान्वित हो रही हैं या फिर प्रस्तावित हैं, जहां जल आपूर्ति, सैनिटेशन एवं कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके अलावा, ये सब इलाके भारत में पर्यटन सर्किट के भी हिस्से हैं।

इसी तरह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, केरल, कर्नाटक और उत्तर-पूर्व में एडीबी की सहायता से परिवहन क्षेत्र, सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएं संचालन में हैं। महत्वाकांक्षी पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण गलियारा भी प्रक्रिया में है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित पर्यटन परियोजना मौजूदा शहरी विकास एवं संपर्क संरचना परियोजनाओं से आगे निकल जाएगी। यह क्यों जरूरी है और एडीबी और भारत सरकार को ऐसी परियोजना में पैसा क्यों बहाना चाहिए?

इसका जवाब शायद परियोजना जानकारी दस्तावेज (पीआईडी) में मौजूद हो।

सुरक्षा उपायों का पूरा अभाव

परियोजना क्रमांक 40648 के पीआईडी में जो सुरक्षा उपाय दर्ज हैं वे एडीबी की मौजूदा सुरक्षा उपाय नीति के तहत लागू किए जाने हैं। प्रस्तावित परियोजना से महिलाओं/या लड़कियों पर या लैंगिक असमानता बढ़ने के नकारात्मक असर होने को, पीआईडी नकारता है। यह नीति अनैच्छिक पुनर्वास के मामले में, केवल अल्पकालीन योजना की बात करती है क्योंकि परियोजना से बहुत ही सीमित असर का दावा करती है। आदिवासियों पर होने वाले असर को भी सीमित बताया गया है और दुष्प्रभाव कम करने के लिए कोई प्रमुख या अल्पकालीन योजना नहीं है। प्रमुख श्रम मानक के मुद्दे पर, इस पर्यटन परियोजना में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पीआईडी का यह भी कहना है कि परियोजना में सामाजिक व स्वास्थ्य जोखिम, महिलाओं व बच्चों का शोषण भी बहुत सीमित होगा। इस तरह सुरक्षा उपाय सूची में एचआईवी/एड्स और मानव खरीद-बिक्री के मुद्दे को जगह नहीं दी गई है।

परियोजना के लिए अपनाई गई सुरक्षा उपाय व्यवस्था सभी तर्कों का विरोध करती है और और वह भी पर्यटन जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए, जिसने कि पर्यटन में शामिल समुदायों, आदिवासी समुदायों की संस्कृति व पहचान, महिलाओं व बच्चों पर होने वाले असरों को स्वीकार किया है। वहां काफी संख्या में मानव व्यापार एवं पर्यटन, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े काम और एचआईवी/एड्स की घटनाएं होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है

कि एडीबी उन असरों को मान्यता नहीं देना चाहती है, खासकर तब जबकि परियोजना में निजी क्षेत्र और पर्यटन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मामला जुड़ा हो। खासकर उत्तर-पूर्व एवं उत्तराखण्ड के मूल जंगलों व आजीविका संसाधनों की क्षति और जमीन अधिग्रहण के कारण वनवासियों के विस्थापन और लैंगिक असमानता के मामले में परियोजना उतनी ही असंवेदनशील है।

एडीबी बोर्ड द्वारा 2008 में अपनाए जा रहे सुरक्षा उपाय नीति के नये विवादास्पद मसौदे के मामले में, भारत में प्रस्तावित व्यापक पर्यटन विकास परियोजना जैसी परियोजनाएं प्रभावित समुदायों के लिए विनाशकारी होगी। पर्यटन उद्योग, आतिथ्य और परिवहन क्षेत्र, रियल इस्टेट व निर्माण उद्योग और शहरी विकासकर्ताओं के पास खुला मौका होगा कि वे चालाकी से मौजूदा एवं प्रस्तावित शहरी विकास एवं सड़क व राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यटन परियोजनाओं में परिवर्तित कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं के मुकाबले मौजूदा शहरी विकास एवं ढांचागत परियोजनाओं में सुरक्षा उपाय व्यवस्था बहुत कड़े हैं। इसके लिए निवेश का प्रवाह लगातार और प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा होगा!

इआईए मानक को दरकिनार किया जाना : सबके लिए बाधामुक्त

ढांचागत एवं शहरी विकास को पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के तर्क बहुत गहरे हैं और यदि हम भारत के मौजूदा पर्यावरणीय मानकों पर विचार करते हैं तो इसके परिणाम बहुत व्यापक हैं। एक उद्योग के तौर पर पर्यटन को पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना (इआईए) 2006 के दायरे से बाहर रखा गया है। यह पिछली इआईए अधिसूचना 1994 में शामिल था।

इस तरह यह संभव है कि पर्यटन के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों, सड़क व राजमार्गों, ठोस कचरा प्रबंधन एवं यहां तक कि निर्माण परियोजनाएं इआईए 2006 से अलग हो जाएं। इन परियोजनाओं को जनसुनवाई और औपचारिक इआईए रिपोर्टों की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार इस व्यापक पर्यटन ढांचागत विकास परियोजना के लिए कोई सुरक्षा उपाय अपनाने से इनकार भी कर सकती है। यदि एडीबी की सुरक्षा उपाय नीति के अनुसार एडीबी की ऐसी परियोजना भारत में अपनाई जाती है तो, कोई भी कानूनी तौर पर सुरक्षा उपाय व्यवस्था से बच सकता है। इस तरह निवेशक को दुष्प्रभाव कम करने के लिए एक रूपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

इस तरह यह एडीबी के सौजन्य से सबके लिए खुला मौका और इन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले समुदायों के लिए संभवतः विनाशकारी है।

कथन

नयी दिल्ली, भारत में 24 सितंबर 2007 को विश्व बैंक पर इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल (आईपीटी) की ज्यूरी के समक्ष कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और आंदोलनकारियों की पर्यटन क्षेत्र के संबंध में बयान/टिप्पणी¹

¹ विश्व बैंक—आईपीटी में पर्यटन क्षेत्र की सुनवाई का समन्वय अल्टरनेटिव, गोवा एवं इक्वेशंस द्वारा किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक परिचालनों के संदर्भ में पर्यटन संभवतः सबसे कम चर्चित लेकिन सर्वाधिक विवादित क्षेत्रों में से एक है। 1980 के दशक में परमाणु उर्जा के साथ ही पर्यटन उन कुछ गतिविधियों में था जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने रोकने के लिए चुना था। आज, जब बैंक पर्यटन संबंधी गतिविधियों को नए उत्साह से शुरू कर रहा है, यह नोट पर्यटन के साथ बैंक के ऐतिहासिक गठजोड़ की पृष्ठभूमि में निहितार्थ की विवेचना करेगा। आईपीटी की ज्यूरी के समक्ष पर्यटन क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुतीकरण एवं बयानों में दलील दी गयी कि विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी एजेंसियां – आईएफसी, एमआईजीए और जीईएफ – का विकासशील दुनिया में बड़े पैमाने वाले तथा विशाल स्तरीय पर्यटन विकास माडलों को मदद देने का इतिहास रहा है। इसका दुनिया में अब स्थापित विशेष “पर्यटन केंद्र” में नकारात्मक असर साफ दृष्टिगोचर हुआ है। इसके अलावा 1990 के दशक से बैंक समूह ने संरक्षण एवं सतत विकास रूख के तहत भारत में संरक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया। इससे आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ा, साथ ही इन संरक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ रिजर्व) को पर्यटन के बढ़ावा के लिए खोल दिया गया। पर्यटन कई बड़ी विनाशकारी आधारभूत परियोजनाओं में प्रेरक कारक रहा है। राजमार्ग विकास, सड़क एवं शहरी विकास जैसी इन परियोजनाओं का भारत के पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में बैंकों ने वित्तपोषण किया है। इन दलीलों के साथ संगठन एवं प्रभावित समुदाय पर्यटन से बैंकों की सहभागिता पूरी तरह समाप्त करने की अपील करेंगे। क्योंकि इससे ऐसे विनाशकारी एवं विस्फोटक मॉडलों को प्रश्रय मिला है जिससे उद्योगों को फायदा हुआ है। लेकिन वहां के स्थानीय समुदाय लाभान्वित नहीं हुए हैं।

पर्यटन क्षेत्र में विश्व बैंक की सहभागिता की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुयी जब विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की शाखा आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन) ने केन्या में होटल संपत्ति में निवेश शुरू किया। 1969 से विश्व बैंक ने अपने पर्यटन विकास विभाग (टीपीडी) के जरिए निवेश एवं पैमाने के लिहाज से विश्व की कुछ सर्वाधिक बड़ी पर्यटन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। इन परियोजनाओं में केन्या वन्यजीव एवं पर्यटन परियोजना, बाली पर्यटन मास्टर प्लान और डोमिनिक गणराज्य की परियोजनाएं शामिल हैं। टीपीडी का जोर विशाल पर्यटन बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं पर था जो होटल निवेशकों को आकर्षित करता। इसका उद्देश्य मौजूदा केंद्रों को बढ़ाकर या केंद्रों के विकास के जरिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए एक मंच तैयार करना था। वास्तव में बैंक को केन्या, बाली, मेक्सिको, डोमिनिक गणराज्य एवं मिस्र जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र विकसित करने का श्रेय हासिल है।

इस दौरान बैंक ने जिन मॉडल और परियोजनाओं का वित्तपोषण किया, वे विकसित दुनिया के धनी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। इन परियोजनाओं से स्थानीय संसाधनों का शोषण हुआ और इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण क्षेत्र में हानिकर परिणाम सामने आए। बैंक के अपने मूल्यांकन एवं परियोजना पूर्ण होने संबंधी दस्तावेजों में इस तथ्य का समर्थन किया गया है। इसके फलस्वरूप बैंक ने एक दशक तक पर्यटन का वित्तपोषण करने के बाद 1979 में अपना टीपीडी बंद कर लिया। इसके साथ ही बैंक ने कोष को अन्य वरीयतावाली आवश्यकताओं में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। लेकिन “पर्यटन से दूर रहने” संबंधी सार्वजनिक बयान के विपरीत विश्व बैंक परोक्ष रूप से इससे जुड़ा रहा जबकि आईएफसी एवं एमआईजीए आतिथ्य सत्कार (मेजबानी) क्षेत्र को मदद देने पर जोर देते रहे।

आईएफसी ने अब तक वैश्विक स्तर पर दो अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है (आईएफसी-2007) उसका जोर निवास, मनोरंजन पार्क समुद्री पर्यटन पोत, इकोटूरिज्म, प्रबंधन सेवा और कार्यालयों पर रहा है। 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मौजूदा पर्यटन कोष के साथ प्रौद्योगिकी सहायता तथा सूक्ष्म – वित्त उपकरणों के साथ 70 सक्रिय परियोजनाएं हैं। जिससे उसे बड़े निवेशकों एवं लघु स्तरीय आपूर्ति संबंधी कारोबार के बीच बेहतर कड़ी की स्थापना में मदद करना है। पर्यटन में उसके अनुभवों में रिजॉर्ट, नगर एवं कारोबार होटल तथा मिश्रित इस्तेमाल के उद्योग निवेश शामिल हैं। आईएफसी के ग्राहकों में पर्यटन में स्वामी परिचालक और अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशक शामिल हैं। इनमें ओरिएंट एक्सप्रेस होटल्स, आस्ट्रेलियन लीपर एंड हॉस्पिटलिटी ग्रुप, हयात, मेरियट, ताज एवं सरकारों द्वारा संचालित होटल एवं पर्यटन निगम शामिल हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा के प्रतिनिधियों के अनुभव से विशाल स्तरीय पर्यटन के प्रभाव का पता लगेगा। यह भी स्पष्ट होगा कि किस प्रकार वित्तीय संस्थान एवं उद्योग का बड़ी परियोजनाओं के प्रति विशेष झुकाव होता है एवं वे स्थानीय उद्यमियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हैं।

नब्बे के दशक में सतत विकास प्रतिमान के शुरू होते ही पर्यटन विश्व बैंक की जैवविविधता संरक्षण एवं सतत पर्यटन

परियोजनाओं के जरिए उनके दस्तावेजों में पुनः शामिल हो गया। 1991 में विश्व बैंक ने विकासशील देशों में जैवविविधता को संरक्षण देने में मदद के उद्देश्य से ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) की स्थापना में सहायता की। नये रुख के साथ काम करने के बावजूद इस चरण में बैंक के संरक्षण नजरिए से हजारों देशी समुदायों को उनके पारंपरिक वन्य भूमि से विस्थापित होने के लिए बाध्य होना पड़ा या उनका परोक्ष विस्थापन हुआ। इसके साथ ही इन क्षेत्रों को इकोटूरिज्म के लिए खोल दिया गया। भारत में विश्व बैंक की इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1995 में शुरू हुयी जिसका उद्देश्य देश के सात राष्ट्रीय उद्यानों (बक्सा, पेंच, रणथंभौर, पेरियार, नागरहोले, पलामू और गिर) की जैवविविधता में स्थानीय लोगों के प्रभाव में कमी लाना तथा उद्यान प्रबंधन को मदद पहुंचाना था। लेकिन परियोजना की वजह से बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन हुआ जो उन क्षेत्रों के अंदर रह रहे थे। वे अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। उसी समय नागरहोले, पेरियार, पेंच, एवं रणथंभौर उद्यान इकोटूरिज्म एवं वन्यजीव पर्यटन के लिए खोल दिया गया। छत्तीसगढ़ एवं नागरहोले कर्नाटक के आदिवासी प्रतिनिधियों के बयानों से विश्व बैंक की इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट के परिणाम सामने आएंगे तथा स्थानीय समुदायों के संघर्ष का ब्यौरा सामने आएगा।

भारत के पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे से संबंधित कई विशाल विनाशकारी परियोजनाओं के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण और प्रेरक कारक रहा है जिनका वित्तपोषण बैंक ने किया है। भारत के पूर्वोत्तर में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित शहरी विकास एवं सड़क परियोजनाओं में पर्यटन एक सुस्पष्ट कारक है और उसमें तर्काधार भी है। यह भी ध्यान किया जाना चाहिए कि विश्व बैंक की सहयोगी एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने अपनी परियोजना दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक निगम (एसएएसईसी) के जरिए कई विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं में दिलचस्पी प्रदर्शित की है। पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों तथा नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में बौद्ध सर्किट तथा इकोटूरिज्म के लिए बुनियादी ढांचा का विकास करना इस परियोजना में शामिल है। लेकिन क्या पूर्वोत्तर के समुदाय गैर नियमित एवं गैर नियंत्रित पर्यटन के प्रभावों से अवगत हैं। पूर्वोत्तर की नाजुक पारिस्थितिकी एवं संवेदनशील सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पर पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ेगा? पूर्वोत्तर के समुदाय प्रतिनिधियों की बातों से आधारभूत ढांचा नीत पर्यटन के प्रभाव तथा उलझन सामने आएंगे।

पर्यटन क्षेत्र में विश्व बैंक की सहभागिता के सवाल पर कार्यरत शोधकर्ताओं और आंदोलनकारियों की प्रमुख प्रस्तुति आगे वर्णित है।

पर्यटन एवं लघु उद्यमियों के लिए अवसर गेराल्डाइन फर्नांडिस, गेस्टहाउस मालिक, बैनोलिम, गोवा

ज्यूरी के सम्मानित सदस्यों एवं न्याय के लिए संघर्षरत सहकार्यकर्ताओं, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने कथन में पहले कुछ ऐसी टिप्पणी हो जिससे हम विश्व बैंक और पर्यटन के बीच की कड़ी देख सकें।

आपने अभी सुना है कि किस प्रकार 1960 के दशक में विश्व बैंक ने विभिन्न महत्व के साथ, विभिन्न चरणों में अपने को शामिल किया। मेरे मामले में, गोवा में मेरे गांव बैनोलिम में आप पर्यटन एवं विश्व बैंक के बीच परोक्ष या एक हद तक सूक्ष्म कड़ी आसानी से स्थापित नहीं कर सकते हैं।

किसी के लिए वैश्वीकरण धन सृजक है। दूसरे शब्दों में यह एक संभ्रात वर्ग पैदा करता है। अन्य शब्दों में वैश्वीकरण से विश्व में छुट्टी मनाने वाला पर्यटक वर्ग बनता है।

दूसरा, बड़े परिचालकों के साथ ही पर्यटन आधारभूत ढांचा, होटल एवं बड़े रिजॉर्ट से संबंधित नीतियों में प्रतिमान स्थापित करने की विश्व बैंक की नीति से छोटे उद्यमियों को व्यापक नुकसान हुआ है। वे हाशिए पर चले गए हैं।

तीसरा, विश्व बैंक एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है – सक्रिय भूमिका के साथ। कोई पूछता है : उनकी योजनाओं में समुदाय आधारित पर्यटन की धारणा (सीबीटी) कहां सही बैठती है – इसका अर्थ है कि हम छोटे उद्यमियों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि विलुप्त भी होने की आशंका है।

मैं आप सबको आमंत्रित करती हूं कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं जो कहूंगी, उसे आप ध्यान से सुनें।

मैं दक्षिणी गोवा से एक लघु उद्यमी हूं। मैं सालसेटे जिला में गोवा के समुद्री तट पर स्थित बैनोलिम गांव में रहती हूं। मेरे गांव की आबादी करीब पांच हजार है। पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या बैनोलिम में स्थानीय आबादी के बराबर हो जाती है।

मैं मूल रूप से उत्तरी गोवा की हूं और 1993 में बैनोलिम आयी। सृजनात्मक एवं आजाद ख्याल की होने के नाते मैंने फैसला किया कि कुछ स्वरोजगार किया जाए। मेरे पास एक फार्मसी तथा रेस्तरां चलाने का भी पूर्व अनुभव था जो पारंपरिक कारोबार का हिस्सा था। अंततः मैं बैनोलिम में गेस्ट हाउस शुरू करने की दिशा में काम करने लगी।

मैंने इसके लिए बैनोलिम के आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की। वहां मेरे पति को उनके पिता से कुछ जमीन मिली थी। विस्तृत बाजार सर्वेक्षण तथा संभावनाओं का आकलन करने के बाद मैंने मित्रों एवं परिवार से सलाह मशविरा किया। उन सबने मुझे पर्यटन उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।

मुझे इस विचार एवं आश्वासन से भी प्रेरणा मिली कि वाणिज्यिक बैंकों पर लघु स्तरीय उद्यमियों को मदद देने का दायित्व है। साथ ही महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ कहने भर के लिए था।

इसके पहले कि मैं अपनी कहानी एवं अनुभव पेश करूं, मैं आपको इस पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि किस प्रकार पर्यटन विकसित हुआ। उम्मीद है कि इससे मेरी दलीलें एवं न्याय के दावे सही रूप में सामने आ सकेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने दो अनिवार्य बिन्दु रखने का प्रयास कर रही हूं :

1. यह कहना भ्रम है कि पर्यटन से स्थानीय समुदाय को फायदा होता है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। हम गोववासी होने के नाते पर्यटन की कीमत चुकाते हैं। पर्यटन समीकरण में असली लूटने वाले, पर्यटक तथा भेजने वाले देश बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं बड़े व्यवसायी हैं जो धनी देशों से पर्यटक भेजते हैं।

2. जब पर्यटन से संबंधित उद्यम शुरू करने की बात आती है तो गोवावासी हाशिये पर डाल दिये जाते हैं। उनके लिए चीजें करीब असंभव सी हो जाती हैं। इस दलील को आगे बढ़ाने में यह कहना उपयोगी होगा कि इस स्थिति की पहली वजह बराबरी के मौके का न होना है जिससे स्थानीय उद्यमी बड़े व्यावसायियों एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बड़े व्यवसायियों एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। दूसरी वजह यह है कि पर्यटक खुद ही लघु उद्यमियों के बीच की प्रतिस्पर्धा को देखते हैं और इसका फायदा उठाते हुए जोर शोर से मोलतोल करते हैं। इससे कभी-कभी व्यापार कम व्यवहार्य रह जाता है।

गोवा में 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर पर्यटन की शुरुआत हुयी। सबसे पहले हिप्पी वहां आए जिनकी अपनी जरूरतें एवं पसंद थी। अपने समाज के भौतिकवाद का परित्याग करते हुए उन्होंने अध्यात्म में शरण लेने का प्रयास किया। लेकिन जल्दी ही उनका आदर्श समाप्त हो गया और उनका स्थान पलायनवादी विचारधाराओं ने ले लिया। जल्दी ही उनका ध्यान सेक्स, नशीली दवाइयों, नग्नवाद आदि की ओर केन्द्रित हो गया। अत्यधिक स्वतंत्र व्यवहार 'हिप्पी संस्कृति' के केन्द्र में स्थापित हो गया। इस प्रकार भौतिकवाद का त्याग करते हुए उन्होंने समान रूप से दमनकारी एवं नकारात्मक जीवन शैली को अंगीकार कर लिया। इसमें कोई दलील दे सकता है कि यह उनका निजी मामला था, लेकिन यह हमारे तटीय क्षेत्रों में हो रहा था और हमें इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना था। आखिरकार वह जीवन शैली दूसरों को लुभाने वाली थी और हमारे कुछ युवा उसमें शामिल हो गए। उसका प्रभाव भी रहा। उसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। हमने उस कीमत का पूरा आकलन भी नहीं किया और संभव है कि हमें इसकी पूरी जानकारी भी ना मिल सके।

गोवा में हिप्पी जैसे पर्यटक का अभी भी सामना करना पड़ता है। उस ओर ध्यान नहीं देने वाली सरकार की वजह से हमें उन्हें चुपचाप सहन करना पड़ता है। स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है। वे कम खर्च करने वाले, अधिक मोलतोल करने वाले हैं लेकिन उनके व्यवहार एवं आचरण से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

हिप्पी 60 के दशक में वापस गए और अपने सभी जाननेवालों को बताया कि गोवा सस्ता गंतव्य है। इससे जल्दी ही गोवा में दो प्रकार के पर्यटक – हरे कृष्णा छापवाले हिप्पी और चार्टर – पर्यटक आने लगे। इससे गोवा में बड़े पैमाने पर पर्यटन की शुरुआत हुई। हरे कृष्णा श्रेणीवाले हिप्पी ने हिप्पी युग में वृद्धि की। उन्होंने अपने लिए विशेष स्थान बना लिए जहां गोवावासियों को जाने की मनाही थी!! एक बार तो दुर्घटनावश मुझ पर पत्थर फेंके गए। चार्टर पर्यटक की चाहत हिप्पियों से अधिक थी लेकिन वे कम कीमत पर ऐसा चाहते थे। हमने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि हमारी सरकारों को डॉलर नजर आ रहा था। उन्हें शायद जानकारी नहीं थी या उन्हें पता था लेकिन हमें नहीं बताया गया कि अंततः फायदा पर्यटकों को होना है हमें नहीं। पर्यटन क्या है आप देखिए – आनंद उठाने के बाद अपने मित्रों एवं परिचितों को बताइए कि वह जगह घूमने योग्य है। समय बीतने के साथ ही खर्च करने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी। लेकिन उनकी अधिक मांगों से लागत मुनाफा समीकरण प्रभावित हुआ। हमें कभी लाभ नहीं हुआ। राज्य की कुल आमदनी का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा पर्यटन से आता है। जब आप पर्यटन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे पर हुए भारी खर्च घटाते हैं और उसे सामाजिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लागत एवं महिलाओं एवं बच्चों के लिहाज से देखते हैं तो नुकसान ही काफी अधिक दिखता है। सिर्फ इसी छोटी गणना से स्पष्ट हो जाएगा कि मेजबान, पर्यटकों पर कितना निवेश एवं खर्च करते हैं। इससे ही स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी।

उपरोक्त तथ्यों से पर्यटन का असर स्पष्ट होता है। तटीय क्षेत्रों में छेड़छाड़ की गयी— बालू के टीलों को समाप्त कर दिया ताकि पर्यटकों को सब कुछ अबाध तरीके से दिख सके। तटीय पादपो को नष्ट कर दिया गया ताकि पर्यटकों के लिए दृश्य बेहतर हो सकें। पारंपरिक समुदाय (किसान एवं मछुआरे) पर्यटन उद्योगों के लिए विस्थापित कर दिए गए और सार्वजनिक क्षेत्र निजी हो गए। बचपन में मैं जिन बीचों पर खेलती थी, अब वे होटलों और रिजॉर्टों की निजी जायदाद हो गए। हमारे मामले में सीआरजेड सिर्फ कागजी टुकड़ा बन के रह गया। उन्होंने इसे बाहर फेंक दिया और अब हमारे अधिकतर तटीय इलाके बोली पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं!

अब मैं उन मुद्दों पर आती हूं जिसे मैं रेखांकित करना चाहती हूं : जब मैंने अपना छोटा पर्यटन कारोबार शुरू करने का फैसला किया – एक गेस्ट हाउस जिसमें आठ कमरे और तीन फ्लैट हों (जिसे अक्सर पेंट हाउस कहा जाता है), आरामदायक, स्वच्छ, पर्याप्त जगह वाला – पर्यटन संहिता के आधार पर निर्मित – मुझे पता लगा कि स्थिति काफी भिन्न है। सबसे पहले मुझे पता लगा कि पांच सितारा होटलों को चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, काफी रियायतें दी

जा रही हैं। उन्हें बाजार मूल्य की अपेक्षा कम दामों पर जमीन दिए जा रहे हैं बल्कि उन्हें आसान शर्तों पर आसानी से कर्ज भी प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं उनके लिए संपर्क सड़क, बिजली, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन आदि में भी राहत दी जा रही है। सरकार ने उनकी आवश्यकताओं और मांगों में निवेश किया है। इसके विपरीत हम छोटों उद्यमियों को कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है। जैसा असीम श्रीवास्तव ने बेहतर वर्णन किया, विश्व बैंक ने कभी भी अपने नीति प्रारूप में उस जोखिम उपबंध के लिए जगह नहीं रखा जिनका सामाजिक उद्देश्य (स्वरोजगार) है और जिनमें कम प्रतिफल नहीं है।

मेरी कहानी से शायद यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार व्यवस्था लघु उद्यमियों के खिलाफ काम करती है और उसका बड़े व्यावसायियों की ओर झुकाव है। मुझे सात लाख रुपए के ऋण की आवश्यकता थी। हमने कर्ज मांगने के पहले ही अपने गेस्टहाउस का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हमने वादा किया और वह सब कुछ दिया जिससे पैसे मिल सकते थे – सोना, चांदी, संपत्ति। लोगों ने हमारी सख्त जरूरतों को देखा, बातचीत के लिए शर्तें बहुत मददगार नहीं थीं और हमें कुछ कटु सौदे करने पड़े। हमने वाणिज्यिक बैंकों से भी संपर्क किया। इन बैंकों में बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ोदा, कार्पोरेशन बैंक शामिल हैं। लेकिन उन्होंने हमारी मांग को ठुकरा दिया और दावा किया कि वे पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक उद्यमों को मदद नहीं देते। उनका बहाना था कि पर्यटन संवेदनशील उद्योग है और इसके मौसमी चरित्र के कारण कर्ज देना व्यवहार्य नहीं है।

अंततः मुझे एक सहकारी बैंक मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ऋण मिला। बैंक के निदेशक मंडल ने मुझसे घंटों पूछताछ की और एक निदेशक ने मेरे दावों और योजनाओं को देखते हुए गारंटी देने का निर्णय लिया। मेरा व्यवसाय, जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि बाजार सर्वेक्षण पर आधारित था। मुझे अब आश्चर्य हो रहा है कि क्या उद्देश्यपरक सर्वेक्षण कारगर होते हैं। पूरा पर्यटन अनियमित इकाई है और यह निश्चित नियम पर काम नहीं करता, साथ ही प्रतिस्पर्धा का भी लाभ उठाता है! मेरा आकलन था कि मुझे अपने कमरों से 300 रुपए और पेंट हाउस से 500 रुपए रोजाना मिलेंगे – व्यस्तम सीजन में। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। सभी गाइड बुक में पर्यटकों से कहा जाता है कि गोवा में मोलभाव (बारगेन) बेहद जरूरी है और वे ऐसा करते हैं। मैं अक्सर अपना कमरा 150 रु. में देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं दृढ़ रही तो मेरे प्रतिस्पर्धी उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर आपको गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता सकती हूँ कि यह किस प्रकार मेरे कारोबार में काम करता है। अपनी लंबी बात को संक्षेप करते हुए मैं बताती हूँ कि मैंने जो आकलन किया था जिसके आधार पर ऋण एवं अन्य दावे दिए थे वे बिल्कुल भिन्न साबित हुए। मुझे उम्मीद से काफी कम लाभ हुआ। वास्तव में शुरुआती चरण में तो न नफा – न नुकसान की स्थिति रही – कई बार नुकसान भी हुआ। कर्ज अदायगी की शर्त सख्त थी और मैंने हरसंभव प्रयास किया कि नियमित रूप से किस्त दी जाए। तीन साल साल की कर्ज अवधि समाप्त हो गयी लेकिन तब भी मैं कर्ज में थी – इसकी वजह पर्यटकों का व्यवहार और किस्त अदायगी की स्थिति थी। जब आप ऋणग्रस्त होते हैं तो आप कर्ज लेते हैं। मेरे ऊपर एक साथ कई ऋण थे। कई बार लंबी अवधि तक रहने वाले ग्राहकों से पैसे लिए जिन्होंने एक बार में छह महीने तक बिना अतिरिक्त पैसे दिए कमरे का उपयोग किया। मुझे कर अवकाश की सुविधा नहीं थी। मुझे उसी महीने से किस्त शुरू करना पड़ा जब मुझे कर्ज मिला हालांकि वह गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए था। मेरे सवाल का जवाब आसान नहीं था, जब निर्माण चल रहा हो तो मैं किस्त की अदायगी किस खाते से करूंगी। मुझे उसी समय समझ में आया कि लाचार व्यक्तियों की क्या स्थिति होती है। हमें बैंक की सख्त शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। इसकी कल्पना कीजिए – मैं लघु उद्यमी हूँ। क्योंकि मैं अपना कमरा 100 रु० से अधिक पर दे देती हूँ, हमें विलासिता कर, पंचायत कर, कमरा कर, गृह कर, लाइसेंस, पर्यटन लाइसेंस, रेस्तरां लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि का भुगतान करना होता है। मेरा सवाल है कि लघु उद्यमियों के लिए इतनी शर्तें क्यों हैं? मैं समझती हूँ कि पर्यटन क्षेत्र में उद्यमी के रूप में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर बड़े व्यावसायियों के लिए सब कुछ है रियायतें, छूट, सस्ती भूमि, आसान शर्तें एवं ऋण, तट के सर्वश्रेष्ठ स्थान तक उनकी पहुंच, यहां तक कि सीआरजेड के उल्लंघन की छूट। इस सब के अलावा हमें अनैतिक एवं असमान प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। रिजॉर्ट तथा बड़े होटल अपने ग्राहकों से कहते हैं कि वे किसी भी कीमत पर होटलों से बाहर नहीं जाएंगे। बदले में वे परिसर के अंदर ही 'वास्तविक गोवा' का अनुभव मुहैया कराते हैं, अगर उन्हें दूर पर ले जाया जाता है तो उन्हें सुरक्षा में रखा जाता है मानो पूरे गोवावासी संभावित चोर हों। उनका सीधा उद्देश्य यह है कि पर्यटक ठहरने या खाने के लिए वैकल्पिक स्थल की तलाश न कर सकें। बेहतर सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने से वे विजेता हैं!

मैं किस प्रकार इसे समाप्त करूँ? मुझे यह उजागर करना है कि हम गोवावासियों पर वैश्वीकरण का कितना गंभीर असर हुआ है। इसके तहत विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की नीतियों का जिक्र करती हूँ। आईएफसी ने अब तक वैश्विक स्तर पर दो अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। उसका जोर निवास, मनोरंजन पार्क समुद्री पर्यटन पोत, इकोटूरिज्म, प्रबंधन सेवा और कार्यालयों पर रहा है। 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मौजूदा पर्यटन कोष के साथ प्रौद्योगिकी सहायता तथा सूक्ष्म – वित्त उपकरणों के साथ 70 सक्रिय परियोजनाएं हैं जिससे उसे बड़े निवेशकों एवं लघु स्तरीय आपूर्ति संबंधी कारोबार के बीच बेहतर कड़ी की स्थापना में मदद करना है। पर्यटन में उसके अनुभवों में रिजॉर्ट, नगर एवं कारोबार होटल तथा मिश्रित इस्तेमाल के उद्योग निवेश शामिल हैं। आईएफसी के ग्राहकों में पर्यटन में स्वामी परिचालक और अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशक शामिल हैं। इनमें ओरिएंट एक्सप्रेस होटल्स, आस्ट्रेलियन लीपर एंड हॉस्पिटलिटी ग्रुप, हयात, मेरियट, ताज एवं सरकारों द्वारा संचालित होटल एवं पर्यटन निगम शामिल हैं। इसके अलावा आईएफसी का कहना है कि वह पर्यावरण संबंधी एवं सामाजिक सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इकोटूरिज्म सांस्कृतिक पर्यटन जैसे नए रुझान लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे निवेश को बढ़ावा देने में उसकी विशेष दिलचस्पी है।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बड़े उद्यमियों के प्रति विश्व बैंक का कैसा पूर्वाग्रह है। पर्यटन क्षेत्र में छोटे उद्यमी के अस्तित्व में रहने की संभावना क्षीण है। सामाजिक परिदृश्य जब व्यक्त किए जाते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं होता।

वैश्वीकरण से दुनिया में कुछ ही लोग धनी हुए हैं। धनी के पास अपने पर खर्च करने से अधिक राशि है। वे अब आकर्षक स्थलों पर छुट्टियां बिताते हैं, गोवा वैसे उन स्थलों में एक है। वैश्वीकरण में इंजन की भूमिका निभाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्व बैंक तथा अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। ऐसी कंपनियां सुनिश्चित करती हैं कि एमएनसी द्वारा अर्जित पैसे उनके दायरे से बाहर नहीं जाएं। इस कारण वे सुनिश्चित करते हैं कि छुट्टी उद्योग को पर्यटन से फायदा हो और इस प्रकार यह भी निर्धारित करते हैं कि आर्थिक विशेषाधिकार में वृद्धि हो। लेकिन उसी वर्ग तक सीमित हो जिसे वैश्वीकरण से फायदा होता है। यही वजह है कि 'छोटे वर्ग' के लिए स्थिति सुधारने की बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद पर्यटन उद्योग धनी, प्रभावशाली और बड़े उद्यमियों के लिए काम करता है। छोटे उद्यमियों को नजरअंदाज कर उन्हें हाशिए पर डाल देता है। छोटे उद्यमी के रूप में हम तभी काम कर सकते हैं जब हम बड़े होटलों रिजॉर्टों और संबंधित उद्यमों की शर्तों को स्वीकार करें। अगर विश्व बैंक यह सोचता है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तब इस क्षेत्र को खुला छोड़ना चाहिए। उसके बाद यह भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि पर्यटन का लोकतंत्रीकरण हो तथा यह समुदायों के लिए फायदेमंद हो। समुदाय आधारित पर्यटन में पर्यटकों की मेजबानी समुदायों को करनी चाहिए न कि पांच सितारा या सात सितारा होटलों को। वे मेजबान नहीं हैं, वे मुनाफा कमाने वाले ढांचे हैं जो हमारी संस्कृति, तट, बच्चे, महिलाएं एवं श्रमिकों के साथ भेदभाव कर हमारे तट का उल्लंघन करते हैं। वे गोवावासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे सिर्फ मुनाफा एवं पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इसके शिकार हैं क्योंकि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में हमारे लिए, छोटे उद्यमियों के लिए कोई जगह नहीं है। विश्व बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्थाएं एवं सरकारें उस वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मुझे नहीं मालूम कि विश्व बैंक कभी बदल सकता है। अगर उसमें बदलाव नहीं आ सकता, उसे जाने दीजिए। हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं।

पर्यटन एवं स्थानीय समुदायों का अधिकार : एक श्रमिक का नजरिया

जॉन रीगो, होटल एंड टूरिज्म वर्कर्स यूनियन, गोवा के महासचिव

मैं यहां गोवा में पर्यटन क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिना श्रमिकों के पर्यटन उद्योग पूर्णतया असमर्थ हो जाएगा। हम इसके लिए रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है तथा हमारे अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है। इतना ही नहीं, हमारी कार्यस्थिति में लगातार गिरावट आ रही है और अमानवीय कार्य स्थिति हम पर थोपी जा रही है। होटल प्रतिष्ठानों ने हरेक चीज को इस तरह से अपने पक्ष में कर लिया है कि यूनियनों को हाशिए पर डाल दिया गया है, यहां तक कि श्रमिक यूनियन में शामिल होने या अपने अधिकारों की बात करने में भी भय महसूस करते हैं। (नौकरी की सुरक्षा ही एकमात्र उद्देश्य बचता है) फलस्वरूप होटलों में श्रमिक उपनिवेशवादी व्यवस्था के तहत विभाजित हो गए हैं।

मैं सबसे पहले वैश्वीकरण के पद्धति पर बोलना चाहता हूं। नव उदारवाद के कई नकारात्मक पहलु हैं। इससे काफी असमानता बढ़ती है और उसके तरीकों की वजह से इसमें कुछ लोग और धनी हो जाते हैं एवं बड़ी संख्या में लोग निर्धन होते जाते हैं। बाजार व्यवस्था में नाजुक स्थिति का सामना कर रहा मध्यम वर्ग अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए गलत तरीके अपनाता है। बाजार व्यवस्था की स्थिति भी समान नहीं है। यह असमान है और एक वर्ग फायदे की स्थिति में है।

मैं 20 साल से होटल क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं पूरा जीवन गोवा में यूनियनों में विभिन्न जिम्मेदारियां सम्भालता रहा हूं। अभी मैं सिडाडे डी गोवा के कर्मचारियों के यूनियन का महासचिव हूं। हमें कम खर्च करनेवाले पर्यटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमें आश्चर्य है कि काफी खर्च करने वाले पर्यटक इतनी संख्या में गोवा आते हैं। हालांकि वे अच्छी राशि खर्च करते हैं। लेकिन उनसे हमलोगों को फायदा नहीं होता क्योंकि वे सिर्फ अपने पर तथा होटल के अंदर ही खर्च करते हैं।

सभी नए एवं विशाल प्रतिष्ठान काफी लाभ कमा रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। उन्हें इतने फायदे मिलते हैं। कर अवकाश, पानी एवं बिजली की दरों में छूट, रियायती दर पर भूमि, व्यापक विशेषाधिकार जैसे कई प्रोत्साहन बड़े उद्यमियों को मुहैया कराए जा रहे हैं। इन उद्यमियों में एमएनसी, अन्य होटल एवं भारतीय एमएनसी भी शामिल हैं। लाभ का लालच अतृप्त है और उस लालच की वजह से वे दमनकारी, अलोकत्रांतिक बन जाते हैं। श्रमिकों के अधिकारों का दमन सत्तावाद की बुरी नीयत से तनिक भी कम नहीं है।

विश्व बैंक नव उदारवाद का प्रायोजक है। अगर विश्व बैंक की नीतियों से धन समृद्ध राष्ट्रों और अपने देश में धनी लोगों के लिए नहीं मिलता तो स्थिति काफी बेहतर होती। इस प्रकार होटल-पर्यटन क्षेत्र में श्रमिकों पर विश्व बैंक की नीतियों का परोक्ष लेकिन घातक असर हुआ है।

गोवा में पुराने होटलों में स्थायी कर्मचारी हैं और उनका संघ है। लेकिन वे होटल भी यूनियन नहीं चाहते। ट्रेड यूनियनो से निजात पाने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू की। अधिकतर प्रबंधन का मानना है कि अगर कोई यूनियन नहीं है तो उन्हें औद्योगिक शांति मिलेगी साथ ही प्रति कर्मचारी खर्च भी न्यूनतम होगा। कम लागत एवं अधिक मुनाफा किसी भी समानता वाली स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्थायी कर्मचारी की तुलना में अस्थायी कर्मचारी पर काफी अधिक लागत आती है। वैसी स्थिति में प्रबंधन कंपनी को ओवरटाइम, छुट्टी, ग्रेच्यूटी के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इसका अर्थ यह है कि स्थाई श्रमिकों की मोलतोल की क्षमता प्रभावित होती है और जब कर्मचारी सामूहिक मोलतोल समझौते की प्रक्रिया में होते हैं तो प्रबंधन अधिक प्रभावशाली होता है। इस प्रकार अधिकतर प्रबंधन चार साल के वेतन समझौता के लिए कर्मचारियों को बाध्य कर रहे हैं जब कि पहले प्रबंधन एवं यूनियन तीन साल का वेतन समझौता करते थे।

मानव श्रम में कमी आने से कर्मचारी लंबी छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि इससे उनके सहकर्मियों की असुविधाएं बढ़ जाएंगी और वे साप्ताहिक अवकाश से भी वंचित रह जाएंगे। ऐसे में प्रबंधन भी कर्मचारियों की कम

संख्या को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि जब कोई स्थायी कर्मचारी काम छोड़ता है तो उसके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती।

इन दिनों अधिकतर होटल किराए पर लिए गए प्लैट होते हैं या खास समय के लिए समझौता किया जाता है। मौसम आने पर वे इसे विदेशी ग्राहकों को दे देते हैं जबकि अप्रैल मई में उनका मालिक आता है और वहां रहता है। बिल्डर पर्यटन मौसम में उसका उपयोग होटल के रूप में करते हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को मौसमी श्रमिक कहा जाता है।

अधिकतर होटल सीमित अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और वे अकसर कंपनी की सूची में भी शामिल नहीं होते। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता जिससे वे बता सकें कि वे उस होटल में काम करते हैं।

पहले होटल 60 प्रतिशत स्थायी कर्मचारी रखते थे लेकिन अब यह अनुपात घटकर 20 से 25 प्रतिशत हो गया है। ऐसे में अधिक शुल्क अदा करने पर भी ग्राहकों को अपेक्षित सेवाएं नहीं मिलती और न ही उनके पैसे का पूरा मूल्य मिलता है।

इन दिनों अधिकतर होटल बहु कुशलता पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने 12 घंटे प्रतिदिन काम की पद्धति शुरू की है। इससे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में वे वैसे कर्मचारियों को वरीयता देते हैं जो दूसरे राज्यों के एवं अपने घरों से दूर हैं। वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं।

बोनस

हाल में केन्द्र सरकार ने बोनस में कुछ बदलाव किए हैं लेकिन प्रबंधन अब भी 1965 के बोनस कानून के तहत बोनस देता है। उनका कहना कि संशोधन अभी प्रभावी नहीं हुआ है। यह कानून 1965 में पारित हुआ था तब डॉलर की कीमत पांच रुपये थे। अब डॉलर की कीमत 42 रुपए है। लेकिन अभी भी सरकार वही कानून मान रही है जिसमें कहा गया है कि 3500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी बोनस का हकदार नहीं है। ऐसे कर्मचारी को अनुग्रह राशि दी जा सकती है, यह राशि प्रबंधन द्वारा सद्भावना के तौर पर देय है।

सरकार का श्रम विभाग इतना धीमा है कि जब प्रबंधन किसी कर्मचारी को निकाल देता है और वह कर्मचारी श्रम आयुक्त के कार्यालय जाता है तो अकसर प्रबंधन आयुक्त कार्यालय तक जाए बिना ही स्थगन ले लेता है। आयुक्त को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रबंधन को प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य कर सके। ऐसे में मामला खिंचता रहता है और बाद में वह औद्योगिक प्राधिकरण जाता है। इस बीच प्रबंधन स्थगन लेता रहता है। मामला पूरा होते होते कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु पार हो जाती है।

मैं अपनी बात पूरी करते हुए ज्यूरी से अनुरोध करूंगा कि वे निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दें :

1. विश्व बैंक-एडीबी व्यवस्था के तहत पर्यटन क्षेत्र में कर्मचारियों, होटलों तथा अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को न्याय दिलाने की संभावना नहीं है या ऐसी संभावना क्षीण है। उनकी भूमिका धनी वर्ग को अधिक सहूलियत पहुंचाने की है। नव उदारवाद की नींव एवं धारणा में न्याय के लिए अधिक स्थान नहीं है। छुट्टी उद्योग वैसे कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जिन्हें खुद कभी छुट्टी नहीं मिलती। इसमें भी खराब स्थिति है कि कर्मचारी प्रबंधन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हुए ग्राहकों को आराम एवं सुख मुहैया कराते हैं। वे कर्मचारियों के अधिकारों या न्याय से वंचित लोगों के हक की बात नहीं कर सकते। आज्ञाकारी कर्मचारियों की मांग और शांतिपूर्ण औद्योगिक माहौल से प्रबंधन को अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। साथ ही ग्राहक शानदार तरीके से छुट्टी मनाते हैं। इस बीच कर्मचारी अपना खून, पसीना, और आंसू बहाते रहते हैं।

2. हालांकि मैं होटल उद्योग के औपचारिक क्षेत्र से हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह औपचारिक क्षेत्र के लिए उचित समय है कि वह गैर औपचारिक क्षेत्र को मदद दे, जो पर्यटन के कुल कार्यबल का 92 प्रतिशत है। उन्हीं की वजह से छुट्टी उद्योग संभव होता है, उन्हें न्याय अवश्य मिलना चाहिए। वे भी मानव हैं और उन्हें कमतर आंकना या बुरा बर्ताव करना उचित नहीं है। उनकी वजह से ही पर्यटन का फायदा संभव होता है।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भरोसा व्यक्त करता हूं कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे न्याय संभव होगा।

भारत में संरक्षण एवं पर्यटन की वजह से विस्थापन अनीता ध्रुव, सीतानदी अभयारण्य, छत्तीसगढ़

मैं अनीता ध्रुव छत्तीसगढ़ राज्य के सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र की एक आदिवासी हूँ। भारत में विश्व बैंक समूह के इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल के सम्मानित ज्युरी के समक्ष मेरी याचिका है ताकि मेरे द्वारा पेश तथ्यों एवं अनुभवों के आधार पर भारत में विश्व बैंक तथा ग्लोबल एनवायरमेंट फ़ैसिलिटी (जीईएफ) जैसी उसकी सहयोगी एजेंसियों की इकोटूरिज्म को प्रोत्साहन देने की विनाशकारी रणनीतियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया जा सके।

विश्व में जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत विश्व बैंक ने भारत में 1990 के दशक से इकोटूरिज्म परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। इस रणनीति की मुख्य विशेषता देश में जैवविविधताओं से भरपूर क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बाघ रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण है। हालांकि ये वन विविध प्रकार के देसी या मूल समुदायों का निवास रहे हैं। जिनके लिए वन पहचान, आजीविका, सांस्कृतिक अस्तित्व और इतिहास का आधार रहा है। 'हरितक्षेत्र' व 'संरक्षण' के विचार, जिसमें कोई मानवीय आबादी नहीं है, से पारंपरिक अधिकार व जीवनशैली पर असर पड़ा और भारत में वनों से जनजातीय समुदायों को बाहर होना पड़ा।

इकोटूरिज्म घटक के साथ जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र विश्व बैंक वित्त पोषित मुख्य परियोजनाएं इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (1996–2002) और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश में (1994–2000) वन परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में विश्व बैंक के इरादों के बारे में कहा गया कि संरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों का असर तथा उन लोगों पर उस क्षेत्र के प्रभाव की ओर ध्यान देना तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के लिए तंत्र में सुधार लाना था। उदाहरण के लिए पेरियार, पेंच, पलामू, नागरहोले, गिर, बक्सा और, रणथंभौर सुरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से भारत में इको डेवलपमेंट परियोजना ने काम किया। इस रणनीति के तहत वन पर आश्रित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका मुहैया कराने के साथ संरक्षित क्षेत्र में वित्त पोषण के स्रोत के रूप में बैंक ने इकोटूरिज्म को बढ़ावा दिया। लेकिन जमीनी स्थिति काफी भिन्न रही है।

वास्तव में, बैंक द्वारा वित्तपोषित संरक्षण प्रयासों से स्थानीय एवं मूल समुदायों के अधिकारों की कीमत पर जैवविविधता की रक्षा की गयी है। सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण जैसी संरक्षण रणनीति से उन समुदायों को लगातार बाहर होना पड़ रहा है जिनका जीवन पारंपरिक रूप से उन वनों के साथ रहा है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों को खोल दिया गया, पर्यटन के लिए! समुदायों की सहमति, सहभागिता लाभ में हिस्सेदारी, वन संपदा पर उन समुदायों का अधिकार, ये सब बातें गायब हो गयीं। इससे बैंक की इकोटूरिज्म रणनीति की असफलता सुनिश्चित हो गयी। इसके अलावा इन परियोजनाओं के तहत गठित इको डेवलपमेंट समितियां व समुदायों के बीच के संबंधों में असंवेदनशीलता रहीं। इससे उन क्षेत्रों में सामाजिक संघर्ष की स्थिति गंभीर हो गयी।

बैंक की इको डेवलपमेंट परियोजना स्थलों में समुदायों के अनुभव इसके प्रमाण हैं। नागरहोले, कर्नाटक में 1997 में 32 हजार आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। उस क्षेत्र को इको डेवलपमेंट परियोजना के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। उनके विस्थापन के अलावा सरकार ने उनकी वनों में कई गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। इन गतिविधियों में शिकार, खेती वन उत्पादों का संग्रह आदि शामिल हैं। इस प्रकार उन्हें उनकी आजीविका के साधन से वंचित कर दिया गया और उनके लिए अतिरिक्त संकट पैदा हो गया। उधर कर्नाटक सरकार ने 1994 में ताज होटल समूह की सहायक इकाई गेटवे होटल्स एंड गेटवे रिजॉर्ट को नागरहोले उद्यान के अंदर भारत का पहला रिजॉर्ट चलाने का ठेका दे दिया। आदिवासी अधिकार संगठनों व स्थानीय लोगों के जोरदार विरोध तथा कानूनी मदद के कारण उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय से राहत मिली और अततः रिजॉर्ट के निर्माण पर रोक लगी। इस अप्रिय मामले में राज्य सरकार की भूमिका को भी दोषी ठहराया गया। नागरहोले फैसला इकोटूरिज्म के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और सुरक्षित क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए मिसाल बन गया। लेकिन आदिवासी समुदाय का भविष्य अधर में ही लटका रहा।

आदिवासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हुआ जो मध्य प्रदेश में है। उसे 1992 में देश का 19वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1995 में विश्व बैंक की इकोटूरिज्म परियोजना की शुरुआत के साथ ही उस क्षेत्र में तथा आसपास कई गांव विस्थापित होने लगे। पेंच नदी के तट पर परंपरागत रूप से रह रहे 15 गोंड परिवारों को उनके गांव अलीकट्टा से विस्थापित होकर दुर्गापुर में शरण लेनी पड़ी। उन्हें कहा गया कि उन्हें वहां से हटना होगा क्योंकि वहां राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की वहां उर्वर भूमि थी लेकिन आज वे खेती नहीं करते और न ही जंगलों में जाते हैं। उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा होता है। उद्यान की स्थापना में गोंड संस्कृति व पहचान पृष्ठभूमि में चली गयी और ग्रामीणों तथा वन विभाग के संबंध खराब हो गए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभयारण्य पर्यटकों के लिए खोले जाने पर वन्य जीवों की पर्याप्त 'सुरक्षा' हो रही है या नहीं।

मैं सीतानदी छत्तीसगढ़ से हूँ जिसे 1970 के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उस समय से हमारा, उस क्षेत्र के मूल निवासियों का लगातार विस्थापन हुआ है। विश्व बैंक अपनी इको डेवलपमेंट परियोजनाओं के साथ क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए आगे आया। लेकिन उसके अंदर के आदिवासियों को बाहर निकाल कर। बैंक और राज्य सरकार का मानना है कि वनों के विनाश के लिए हम दोषी हैं क्योंकि हम वनों से जड़ी बूटियों, लकड़ियों और अन्य छोटे उत्पाद एकत्र करते हैं। वास्तविकता यह है कि हम आदिवासी सदियों से वनों की रक्षा कर रहे हैं। जब आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा था तब राज्य सरकार तथा विश्व बैंक वनों के 'संरक्षित' क्षेत्र में इकोटूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। अगर बैंक की रणनीति है कि वनों को बिना मानव आबादी के संरक्षित करना है तो इकोटूरिज्म किस प्रकार इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंकों और सरकार के लिए ऐसे वनों में पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन मूल निवासियों का नहीं। पर्यटन हमारे लिए दहशत का पर्याय बन गया है क्योंकि हमारी अपनी पैतृक भूमि और वनों को होटलों तथा रिजॉर्ट बनाने वालों को बेचा जाता है या उन्हें लीज पर दिया जा रहा है। यहां तक कि जो आदिवासी आज वनों के अंदर हैं, पर्यटन ने उन्हें मनोरंजन का स्रोत बना दिया है। उनके साथ पर्यटक नाच गा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं या आनंद प्राप्त कर सकते हैं!

आज देश में आदिवासी समुदाय अपनी पहचान एवं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो क्षेत्र कभी उनका अपना हुआ करता था वहां पर्यटन एवं इकोटूरिज्म फलफूल रहा है। विश्व बैंक का संयुक्त वन प्रबंधन, सहभागिता वन प्रबंधन और यहां तक कि समुदाय वन प्रबंधन जैसे विभिन्न तरीकों के जरिए संरक्षण की वकालत करना जारी है। पिछली असफलताओं के बावजूद विश्व बैंक ने सबक नहीं लिया है। उसकी 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट "अनलॉकिंग अपॉरच्युनिटीज फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपुल इन इंडिया" में इसकी पुष्टि होती है।

हम सीतानदी के लोगों ने बैंक, राज्य सरकार तथा निजी कंपनियों के चंगुल से अपने वनों को बचाने के लिए जोरदार संघर्ष किया है। हमने इसके लिए पिछले 12 साल के दौरान हर प्रकार के अभियान और विरोध का सहारा लिया और बैंक को अपने क्षेत्रों से बाहर करने में कामयाब रहे। बैंक को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी नीतियों और परियोजनाओं से पारिस्थितिकी का व्यावसायीकरण हो गया, सामाजिक बिखराव बढ़ा, मानव अधिकारों तथा पहचान के लिए संघर्ष तेज हुआ। साथ ही सामुदायिक विचार विमर्श और सहमति के अभाव की स्थिति बनी। समुदायों की ओर से सख्त विरोध बैंक के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि उसके रवैये और हस्तक्षेप का स्वागत नहीं है। हम अपने वनों, अपनी जमीन पर विश्व बैंक को आने की कभी इजाजत नहीं देंगे – ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है।

नागरहोले कर्नाटक में विश्व बैंक की पर्यावरण, विकास परियोजना तथा ताजसमूह के रिजॉर्ट बनाने के प्रयास के खिलाफ स्थानीय समुदायों का संघर्ष पी. के. राजू, आदिवासी, नागरहोले, कर्नाटक

मेरा नाम पी. के. राजू है और मैं कर्नाटक से आया हूँ। हम जनजातीय समुदाय को राज्य सरकार के उस कदम के खिलाफ खड़ा होना पड़ा जब उसने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अपनी भूमि व क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब यह कानून बन गया है और आदिवासी समुदाय को बाहर जाना पड़ेगा। जब हमने विरोध किया तो राज्य सरकार के वन अधिकारियों ने कहा कि वे हमारे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे या हमें जेल में डाल देंगे। उन्होंने तो जान से मारने तक की धमकी दी लेकिन हम उनके दबावों के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमारा मानना है कि वह हमारा है तथा यही वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। हम और कहीं नहीं जा सकते। हमने अदालतों के समक्ष अपनी दलीले रखीं। अगर कानून के अनुसार वन या अभयारण्य को बिना मानव आबादी से संरक्षित किया जाना है तो राज्य सरकार ने किस प्रकार एक पर्यटन परियोजना के निर्माण की अनुमति दी जिससे उसी क्षेत्र में पर्यटकों को जाने का मौका मिलेगा। इस तर्क के साथ स्थानीय समुदाय ने “ताज समूह” के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया। इसी समूह को क्षेत्र के अंदर रिजॉर्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। सुनवाई के दौरान ताज समूह और राज्य सरकार ने दिलचस्प सवाल पेश किए कि किस प्रकार आदिवासी साबित कर सकते हैं कि आदिवासी जंगलों के एकमात्र निवासी हैं या वह समुदाय वहाँ पहले आया। जब मामला अदालत में गया तो उन्होंने कहा कि आदिवासी मूल निवासी हैं क्योंकि वनों में सदियों से उनके जीवन का प्रमाण है। उनकी आत्मा एवं दिल वहीं है। दूसरा पक्ष तर्कसंगत दलील पेश नहीं कर सका और अदालत ने आदिवासी समुदाय के पक्ष में अपना फैसला दिया।

मुकदमा जीत जाने के बावजूद उन क्षेत्रों में पर्यटन फल फूल रहा है जहाँ आदिवासी अब पुनर्वासित हुए हैं। वन तभी ठीक रह सकते हैं कि जब देशी समुदाय उनके अंदर ठीक से हों। ऐसे में हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे या उन्हें पर्यटन या किसी अन्य विकास के लिए नहीं देंगे। हमने राज्य सरकार तथा अधिकारियों के समक्ष सवाल रखा कि वे हम पर क्यों दबाव दे रहे हैं और अपनी भूमि, घर छोड़ने को कह रहे हैं। वे हमें क्यों विस्थापित कर रहे हैं? हमने कोई अहित नहीं किया है और न ही आपसे अपना स्थान छोड़ने को कहा है। अगर हम आपसे चांद पर जाने को कहें तो क्या आप जाएंगे? हमने अधिकारियों से ऐसे सवाल किए।

जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि आदिवासियों पर कोई दबाव नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें उसी रूप में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस प्रकार से वे अभी रह रहे हैं। उन्हें विकास के लिए पूर्ण मदद दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि आदिवासियों पर सरकार की नीतियां थोपी जाती हैं, वे सोचते हैं कि आदिवासी बर्बर और हानिकर हैं, लेकिन हम वन एवं प्राकृतिक संसधानों की रक्षा करने वाले हैं। हमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मरक्षा तथा अपने वनों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

भारत के पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा विकास और पर्यटन

रेव. अवला लौंगकुमेर नगालैंड, कार्यकारी सचिव, एनसीसीआई (नेशनल काउंसिल आफ चर्चेज ऑफ इंडिया)

मैं देश के ऐसे हिस्से से हूँ, जहाँ आप में से अधिकतर नहीं गए हैं और संभवतः वहाँ के बारे में कम ही जानते हैं। सिर्फ यही तथ्य हमारे क्षेत्र में पर्यटन को प्रमुख उद्योग के तौर पर उभरने की संभावना बनाता है और यही पूरी धारणा हमारे लिए समस्या पैदा करने वाली है। जब आप दूसरों के लिए कोई योजना बनाते हैं तो पूरी आशंका होती है कि आप गंभीर गलती करें। मैं इस संबंध में एक प्रचलित लोक कथा सुनाना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार है :

एक बार एक बंदर ऐसे जगह पर गया जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। वह ऐसे समय वहाँ गया जब वहाँ बाढ़ आयी हुई थी, चारों ओर तबाही का मंजर देखकर बंदर की आँखों में आंसू आ गए। उसने अकेले दम पर राहत कार्यशुरु करने का फैसला किया, अकेले व्यक्ति (क्षमा कीजिए अकेला बंदर) का अभिमान! वह नदी के तट पर गया और मछलियों को तैरते हुए देखकर उसने विचार किया कि 'इसके पहले कि मछलियाँ मर जाएँ, उन्हें बचाना चाहिए'। इसके बाद वह एक के बाद एक मछलियों को किनारे रखने लगा और उनसे कहा अब तुम सुरक्षित हो। इसके पहले कि वह 100 मछलियों को बाहर निकालता, उसने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। उसने मछलियों को देखा – सभी मछलियाँ मर चुकी थीं। एक राहगीर ने बंदर से कहा कि मछलियों के जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है न कि सूखी धरती की।

जब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से पर्यटन के लिए तैयार की जा रही बड़ी योजनाओं पर सोचता हूँ तो 'बंदर की बात' सोचकर चिंतित हो जाता हूँ। क्या वे वही करने वाले हैं जो बंदर ने बाढ़ में नदी के तट पर किया था? मेरी चिंता तब भी होती है, जब सुनता हूँ कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने फिर से पर्यटन में दिलचस्पी लेनी शुरू की है और उनकी योजना फिर से ठीक उन्हीं बातों में वित्तपोषण शुरू करने की है जो हमारे लोगों, संस्कृति, हमारी पारिस्थितिकी, युवा और महिलाओं के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। मुझे आशंका है कि हमारे क्षेत्र को परिभाषित करने वाले संघर्ष और पर्यटन जटिल एवं गंभीर हो सकते हैं। आखिरकार अधिकतर राजनीतिक संघर्ष जो हमारे संदर्भों को परिभाषित करते हैं, हमारी पहचान और देश के लोगों में अलग वर्ग की पुष्टि के लिए हैं।

जब से मैं पर्यटन बहस में शामिल हुआ हूँ कि मेरी चिंताएँ बढ़ गई हैं। मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या हमें इस क्षेत्र में पर्यटन की कोई आवश्यकता है? शायद हाँ, अगर हम सहमत होते हैं कि हमें पर्यटन की आवश्यकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि वाशिंगटन या नयी दिल्ली केंद्रित व्यवस्था की नीतियों और रणनीति पर आधारित नहीं हो सकती। उन्हें साफ तरह से एवं बिना किसी समझौता के लोकतांत्रिक तरीके से तैयार एवं कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। नीतियाँ लोकोन्मुखी होनी चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं।

अब मैं अपने उद्देश्यों की ओर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ :

1. हमारी साम्राज्यावादी केन्द्र सरकार – इस टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे लेकिन हम पूर्वोत्तर में अकसर महसूस करते हैं कि – जिस प्रकार योजनाएँ बनायी गयी हैं वे हमारे मूल चरित्र के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। हमारी सरकारें पर्यटन राजनीति में शामिल हो रही हैं जिससे हमारे लिए जोखिम पैदा हो सकता है। मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि क्षेत्र में विशाल पूंजी परिव्यय मुहैया कराने की योजनाएँ हैं, सवाल यह है कि इसके लिए किसने कहा, क्या हमारे लोगों ने?

2. जो लोग हमारे क्षेत्र को जानते हैं वे इस बात से सहमत होंगे कि हमारा पूरा भौगोलिक क्षेत्र बेहद खूबसूरत है, हमारी संस्कृति लुभावनी है, हमारा संगीत खान-पान और नृत्य सब अनोखे हैं तथा काफी आकर्षक हैं, हमारा अतिथ्य सत्कार और उदार नजरिया स्वागत योग्य है। इस प्रकार हममें वे सब गुण हैं जो किसी पर्यटन केन्द्र में चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि क्यों और किस प्रकार, हमें पर्यटन से फायदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ यही कह सकता है कि मुझे उसके लिए खुशी है। लेकिन हम कब तक भूस्खलन से बचेंगे, जिसकी योजना बन रही है? क्या हम अपने आपको उस हमले के लिए तैयार कर सकते हैं? क्या हम बड़े स्तर पर पर्यटन के आने के पहले कोई विकल्प तैयार कर सकते हैं?

3. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमें पर्यटन की आवश्यकता है या नहीं? हो सकता है कि यह अपरिहार्य हो, एक वांछनीय स्थिति हो सकती है इस आधार पर। आसान शब्दों में पूर्वोत्तर के पास 'उत्पाद' है जिसे उपहार या संपत्ति

कह सकते हैं। हम इस शर्त पर दूसरों को साझीदार बना सकते हैं कि हमारी निष्ठा अपरिवर्तित रहे। साफ तौर पर हम ऐसा पर्यटन नहीं चाहते हैं जिससे हमारा कुछ भी नष्ट हो – संस्कृति, पर्यावरण, लोग खासकर महिलाएं एवं बच्चे और श्रमिक

4. हमारा राजनीतिक संघर्ष इतने वर्षों से सुलझ नहीं सका है। इसके निकट भविष्य में हल होने की संभावना भी काफी कम है। इन संघर्षों से सामाजिक ताना-बाना के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। हमारे कई युवकों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। दुखद है कि जिन्हें हमारा समाधान खोजना है, वे हमारे क्षेत्र के लोगों और उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझते। इसके लिए पर्यटन रामबाण हो सकता है, यह हमारे लोगों तथा देश के बाकी हिस्से के बीच पुल के रूप में उभर सकता है। यह हमारे एकाकीपन को समाप्त कर सकता है तथा एक वास्तविक विविधता स्थापित कर सकता है। यह हमारे अनोखेपन को कायम रख सकता है।

5. पर्यटन को "आनंद एवं छुट्टी" के रूप में प्रमुखता से परिभाषित किया जाता है तो हमारे मन में एक भय पैदा होता है (जो अवास्तविक भय नहीं है) कि पर्यटन के साथ यौन पर्यटन बाल दुर्व्यवहार, बाल यौनशोषण तथा बुराइयां भी साथ आएंगी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और वे हमारी जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन इलाकों को अनिवार्य रूप से संरक्षित क्षेत्र रहने देना चाहिए तथा इन्हें अनियंत्रित पर्यटन के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। इसकी भी आशंका है कि पर्यटन से हमारे सुरक्षित क्षेत्रों में बायोपाइरेसी की आशंका पैदा हो सकती है और इस प्रकार वह नाजुक पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती है। यह चिंता का विषय है। विश्व बैंक की मौजूदा रणनीति और उसका इकोटूरिज्म तथा संरक्षण पर जोर देने वाले रिकार्ड के मददेनजर सजग रहना होगा। पर्यटन के प्रवेश में निम्नलिखित बातें अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिए –

- पर्यटन की नीतियों एवं रणनीतियों में अनिवार्य रूप से स्थानीय समुदाय शामिल हों न कि दूर बैठे नीति निर्माता
- पर्यटन से स्थानीय समुदाय को अवश्य लाभ हो
- हमारे प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों की पूर्व शर्त के रूप में सुरक्षा की जाए और इसके लिए सख्त तंत्र हो।

मैं चेतावनी की घंटी बजाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। यह आशंका मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। सितम्बर 2006 में मैं एक सप्ताह के थाइलैंड दौरे पर था। मैं वहां के लोगों के अनुभव के बारे में जानकारी जुटाने तथा स्थिति का अध्ययन करने के लिए गया था। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि पूर्वोक्त के लोगों को वैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा उत्तरी थाइलैंड के लोग कर रहे हैं। उनकी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। पर्यटन से उत्तरी थाइलैंड के लोगों को जो अपार क्षति हुई है उसे बताना भी भय पैदा करने वाला है। सब कुछ और हर कोई एक वस्तु में तब्दील हो गया है। एक बालिका या एक महिला का मूल्य शून्य है या उससे भी कम हो गया है। संस्कृति खरीददारी के लिए एक वस्तु रह गयी है जिसका मूल्य भी खरीददार ही निर्धारित करता है। एकदम असमान माहौल में पर्यटक हमेशा विजयी रहता है। मेजबान की स्थिति कमजोर हो जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं ने थाइलैंड को प्रभावित किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार की लेकिन आम लोगों को सिसकने के लिए छोड़ दिया। वह विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था जिन्होंने उनका विनाश कर दिया और मेरी नजर में वह अपराध है। हम विश्व बैंक एडीबी, आईएमएफ या केन्द्र सरकार को अपने साथ वैसा व्यवहार नहीं करने देंगे।

मैं एक अन्य आशंका का जिक्र करना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारा क्षेत्र द्वन्द्वों और संघर्षों से घिरा हुआ है। हमें आशंका है कि पर्यटन से इसमें और इजाफा होगा और हमारे सांस्कृतिक उद्योगों का क्षय होगा। पर्यटन से लोगों के बसने और जनसंख्या अनुपात के प्रभावित होने की आशंका है।

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पर्यटन के नाम पर हमारे क्षेत्र में उस बंदर जैसी बात नहीं दोहरायी जाएगी। विश्व बैंक तथा एडीबी का लोगों की ओर से गलती करने का इतिहास रहा है। मैं एक बार फिर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं कि हमारी संस्कृति और पहचान, हमारी प्राकृतिक संपदायें, हमारे मानव संसाधन – विक्रय के लिए नहीं हैं। वे हमारी धरोहर हैं और लोगों के रूप में हमें सिर्फ अपनी चीजों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

पर्यटन से हमारी उम्मीद रहेगी कि इससे फायदा होगा और सतत समुदाय के रूप में हमारी योग्यता बढ़ेगी जिससे वह अपनी संपदा में हिस्सेदारी के साथ विश्व तथा देश के अन्य हिस्से का मुकाबला कर सके – यह उत्पाद या कारोबार लायक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में, जिससे सभी को परस्पर लाभ हो। उससे कम कुछ भी हो उसका विरोध किया जाएगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में आईपीटी की ज्यूरी के समक्ष पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित बातें कहीं –

तर्क संख्या 1: विश्व बैंक का इतिहास रहा है कि उसने 1960 तथा 1970 के दशक में विकासशील देशों को मदद दी जिससे अब स्थापित दुनिया के पर्यटन इन्कलेव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

तर्क संख्या 2: विश्व बैंक ने अपने संरक्षण एवं सतत विकास नजरिये के तहत 1990 के दशक से ही भारत में संरक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया जिससे आदिवासियों और अन्य स्थानीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ा, वहीं उन संरक्षित क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व को पर्यटन के लिए खोल दिया गया।

तर्क संख्या 3: पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कई बड़ी विनाशकारी परियोजनाओं में पर्यटन असरकारी घटक रहा।

तर्क संख्या 4: विश्व बैंक की सहयोगी संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विकासशील देशों में विशाल स्तरीय लक्जरी पर्यटन विकास परियोजनाओं को सक्रिय रूप से मदद दे रही हैं।

तर्क संख्या 5: विश्व बैंक पर्यटन क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय एडीबी की तर्ज पर भारत में परियोजनाओं को सीधे वित्तीय मदद देने में फिर से दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन आशंका इस बात की है कि जिस तरह के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा उससे स्थानीय समुदायों का विशेष लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत देश के संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूदा पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक असरों में और वृद्धि करेगा।

पर्यटन क्षेत्र के समूहों द्वारा प्रस्तावित विकल्प तथा निष्कर्ष इस प्रकार रहे :

- पर्यावरण विकास परियोजना जैसी विश्व बैंक वित्तपोषित संरक्षण परियोजनाओं ने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों को आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय समुदायों की कीमत पर पर्यटकों के लिए खोल दिया है।
- पर्यटन विकास को मदद देने का विश्व बैंक का रवैया शेष विश्व में सफल नहीं रहा है क्योंकि उससे स्थानीय समुदाय को विस्थापित होना पड़ा। साथ ही बड़ी एवं विदेशी स्वामित्व वाली पर्यटन गतिविधियों का पक्षपातपूर्ण समर्थन एवं पर्यटन विकास की पर्यावरण एवं सामाजिक लागत की जिम्मेदारी नहीं लेना भी शामिल रहा। इन सब को देखते हुए इस सिफारिश के पर्याप्त कारण हैं कि बैंक भारत में सीधे तौर पर पर्यटन वित्तपोषण में शामिल नहीं हो (स्वीकार किए जाने वाले पर्यटन मॉडल और ऐसे वित्तपोषण का प्रकार, इरादा, प्रकृति को स्पष्ट किए बिना)।
- पर्यटन आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए पर्यटन उपकरण साबित हो सकता है। लेकिन यह क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि पर्यटन आईएफआई और अपनी राष्ट्रीय सरकार किस मॉडल को बढ़ावा देती है। भारत में पर्यटन के तहत स्थानीय समुदायों के लिए स्थानीय वित्तपोषण एवं तकनीकी मदद की आवश्यकता है जो पर्यटन कारोबार में सार्थक रूप से शामिल हो सकें। ऐसे वित्त देश के राष्ट्रीय और निजी बैंकों से संभव हो सकते हैं तथा इसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों से बड़े पैमाने पर मदद की आवश्यकता नहीं है।

इक्वेशंस एक शोध, अभियान एवं एड्वोकेसी संगठन है। उदारीकृत व्यापार व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला करने एवं आर्थिक सुधार की पहल के संदर्भ में पर्यटन विकास के असरों को समझने के आग्रह के जवाब में सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हम ऐसे पर्यटन की कल्पना करते हैं जो कि शोषणकारी न हो, जहां निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हो व सुलभ हो एवं पर्यटन के लाभों का वितरण एकसमान हो।